हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 3 मार्च 2016 को माननीय उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला 171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

03.03.2016/1100/जेएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2330

श्री संजय रतनः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी 55 साल की उम्र में वे हायर स्टडी के लिए जाते हैं। दो साल वह MSc करते हैं। 57 साल की उम्र में वे वापिस आते हैं या किसी डिप्लोमा में जाते हैं या किसी डिग्री में जाते हैं। वे कर्मचारी न तो विभाग को कुछ कान्ट्रिब्युट कर पाते हैं और न ही सरकार को कोई फायदा होता है। होता क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति की ट्रांसफर होती है वह ट्रांसफर के नये स्टेशन में ज्वाईन करने के बजाए स्टडी लीव के लिए एप्लाई कर देता है। स्टडी लीव ले करके वह दो साल सरकार का पैसा भी लेता है और अपना समय भी व्यतीत करता है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी कोई समय सीमा अवधि निश्चित की जाए ताकि इतनी उम्र के बाद वह प्रशिक्षण के लिए या हायर स्टडी के लिए विभाग उसे स्पोंसर न करें। मेरे हिसाब से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 50-52 साल से ऊपर किसी को भी हायर स्टडी के लिए नहीं भेजना चाहिए।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, **मैं, माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं। हम इसमें संशोधन करेंगे और 50 वर्ष के बाद किसी को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवकाश नहीं देंगे।**

03.03.2016/1100/जेएस/डीसी/2

प्रश्न संख्याः 2491.

श्री ईश्वर दास धीमानः अनुपस्थित।

03.03.2016/1100/जेएस/डीसी/3

प्रश्न संख्याः 2697.

श्री अनिरूद्ध सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और विभाग का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने पांच जो डी0पी0आर्ज़0 डिपार्टमैंट को ऑलरेडी सबमिट करवा दी हैं और मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जो रिमेनिंग डी0पी0आर्ज़ हैं वे टाईमली सबमिट हो ताकि डवैल्पमैंट को गति मिल सके।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, **जो बाकी डी0पी0आर्ज़0 हैं उनको भी तीव्र गति से प्रोसैस किया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी जो काम हैं वे शुरू किए जा सकें।**

03.03.2016/1100/जेएस/डीसी/4

प्रश्न संख्याः 2498.

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उस सूचना के आधार पर पिछले तीन सालों में हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश के बाहर 7401 मिलियन युनिट बिजली बाहर बेची और एवरेज रेट इसका 3.25 पैसे रेट निकला। इसमें 2403 करोड़ रूपये की आय हिमाचल प्रदेश को हुई। इसी के साथ ही इन्होंने वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के रेट्स भी बताए हैं कि किस-किस को किस रेट में बेची। वर्ष 2013-14 के रेट जो इन्होंने बताए हैं पॉवर एक्स्चेंज को 2.19 पैसे ,

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

03.03.2016/1105/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 2698 क्रमागत

डॉ राजीव बिंदल क्रमागतः

वैस्ट बंगाल स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को 3 रुपया 65 पैसे, पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन को 3 रुपया 99 पैसे --(व्यवधान)--

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपना सप्लीमैंटरी पूछिये। This is given on the record. आप सप्लीमैंटरी पूछिये।

डॉ राजीव बिंदलः सर, तभी तो सप्लीमैंटरी बनेगी।

उपाध्यक्षः यह उत्तर में ऑलरेडी है। आप अपना सप्लीमैंटरी पूछिये। This is on the record. केवल सप्लीमैंटरी पूछिये।

Dr. Rajiv Bindal: It is on the record, everything is on the record of the Government but not on the floor of the House.

उपाध्यक्षः आप सप्लीमैंटरी पूछिये।

डॉ राजीव बिंदलः उपाध्यक्ष जी, 2 रुपया 19 पैसे और 4 रुपये 15 पैसे का डिफरैंस है। यह मैं ध्यान में लाना चाह रहा हूं।

उपाध्यक्षः आप सप्लीमैंटरी पूछिये।

डॉ राजीव बिंदलः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंटरी ही पूछ रहा हूं। अगर आप इतना भी एलाऊ नहीं करेंगे तो हम बाहर चले जाते हैं। कोई बात नहीं करते।

उपाध्यक्षः वह तो आपकी इच्छा है अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको नहीं रोक सकता।

डॉ राजीव बिंदलः आपकी इच्छा का क्या मतलब है? हम यहां पर चुन कर आए हैं।

Deputy Speaker: There are 40 questions to be discussed.

डॉ राजीव बिंदलः उपाध्यक्ष जी, आप मुझे शांति से एक मिनट दीजिए। 2 रुपया 19 पैसे और 4 रुपये 15 पैसे का रेट डिफरैंस है। ऐसा ही रेट डिफरैंस 2014-15 में 3 रुपये 24 पैसे

और 4 रुपये 6 पैसे का है। इसी तरह से आपका एवरेज़ 3 रुपये 25 पैसे आया है। जो टोटल बिजली 74.1 मिलीयन यूनिट बेची गई, उसमें से 70 परसैंट बिजली अकेली इस पावर एक्सचेंज कारपोरेशन के माध्यम से बेची गई। जो पावर एक्सचेंज के माध्यम से बेची गई वह सबसे कम दाम पर बेची गई। अब मेरा सवाल इसमें आता है कि यह जो पावर एक्सचेंज है यह क्या ऑर्गेनाइजेशन है? कौन इनके कर्ताधर्ता हैं? इनको यह बिजली कम दाम पर बेचने की क्या वजह है? यह हमारा मूल सवाल है।

दूसरा, 3 रुपये 25 पैसे की एवरेज पावर एक्सचेंज के कारण ही डाऊन आई है, इसलिए इसके बारे में बताने की कृपा करें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, ये रेट्स जो हैं ये उनके साथ फिक्स करने पड़ते हैं। यह डिफरैंस कब बीच में होता है। पावर एक्सचेंज रेट बाईलेटरल सेल से काफी कम रहता है। पूरे देश में अधिकतम बिजली पावर एक्सचेंज प्लेटफार्म के माध्यम से ही बेची जाती है।

डॉ0 राजीव बिंदलः हमारा सवाल यह है कि हमारी बिजली है। पावर एक्सचेंज के माध्यम से बेची जाती होगी, मगर मेरा प्रश्न यह है कि हम पावर एक्सचेंज के माध्यम से क्यों बेच रहे हैं जो हमको कम दाम दे रहा है? ऐसी उसमें क्या खासियत है कि हम पावर एक्सचेंज के माध्यम से इस बिजली को बेचने पर मजबूर हैं? जिसके कारण एवरेज डाउन हो करके हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उसकी हम वजह जानना चाह रहे हैं।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, यहां पर इन्होंने पावर एक्सचेंज का प्रश्न उठाया है। यह संस्था नहीं है। यह एक ट्रेडिंग प्लेटफार्म है और वहां पर जो डिसाइड होता है उसी के हिसाब से बिजली बिकती है।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो दरें यहां पर दर्शाई हैं कि इन दरों पर बिजली दूसरे राज्यों को बेची गई है क्या आप इस हाऊस को यह सूचना भी दे पायेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो इंडस्ट्रीयल एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगी हैं उनको बिजली किन दरों पर दी जाती है?

दूसरा, क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतलायेंगे कि जो डॉमैस्टिक कंज्यूमर हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं उनको बिजली किन दरों पर दी जा रही है? पिछले कल इस

03.03.2016/1105/SS-DC/3

सदन के बीच में चर्चा हुई थी कि जो इंडस्ट्रीयल एरिया है वहां पर 100 से भी ज्यादा बार 240 घंटे बिजली का कट रहा। आप अपनी बिजली बाहर सस्ते में बेच रहे हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो उद्योग हैं उनको 240 घंटे का कट लगना अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके पीछे क्या कारण है?

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2016/1110/केस/एजी/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, जो इन्होंने कट की बात बताई है, यह बिजली की कमी की वजह से नहीं है । कट तो बिजली की खराबी की वजह से भी हो सकता है। रिस्पोंसिबिलिटी तो डिपार्टमैंट और गवर्नमैंट के ऊपर ही आएगी। महेन्द्र सिंह जी, दूसरा आपका प्रश्न क्या था?

श्री महेन्द्र सिंहः हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उनको जो बिजली दी जा रही है वह किस रेट से दी जा रही है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः माननीय सदस्य, यह सूचना आपको दे दी जाएगी। अभी इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। पावर एक्सचेंज की दरों का निर्धारण मार्किट के हिसाब से होता है जो कि सरकार के कंट्रोल में नहीं होता। एक्सचेंज रेट्स

डिमांड एण्ड सप्लाई पर निर्धारित होते हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष जी, मूल प्रश्न के "क" भाग के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा 7401.24 मिलियन युनिट बिजली 3.25 पैसे के हिसाब से बेची गई और 2403.07 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगें कि राजस्व अर्जित करने के उपरांत इसके अंतर्गत प्रदेश को आय कितनी हुई है?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, यह तो रेवन्यू जनरेशन का प्रश्न है । माननीय सदस्य, आप क्या पूछ रहे हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः नैट इन्कम प्रदेश को कितनी हुई प्रोडक्शन के उपरांत, खर्चा करने के उपरांत, यह मैं जानना चाहता हूं?

03.03.2016/1110/केस/एजी/2

उपाध्यक्षः माननीय मंत्री जी, अगर आपके पास इसकी इन्फोर्मेशन है तो जवाब दे दें अन्यथा इनको इसका जवाब बाद में दे दें।

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष जी, इन्होंने पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बताया कि यह ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, हम यह जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो that is an organization. कौन उसके हैड है? उस ट्रेडिंग प्लटफॉर्म को क्या प्रोफिट होता है? क्या वह गवर्नमैंट एजैंसी है या कुछ लोगों की एजैंसी है ? इसको इतने सस्ते में दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो वजह होगी? अगर वह हिमाचल गवर्नमैंट की एजैंसी है तो ठीक है, लेकिन अगर वह किसी और लोगों की एजैंसी है तो उसको हम क्यों दे रहे हैं? तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, कृपया उसके बारे में बताने का कष्ट करें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, आजकल के जमाने में किसी चीज़ की भी प्रोडक्शन है, चाहे वह एग्रिकल्चर में हैं चाहे बिजली है, पैदा करने वाले की कीमत नहीं होती। कीमत तो वह फिक्स करता है जो खरीदता है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ठीक कह रहे हैं लेकिन एक ही साल में चार लोग है । चार लोग चार रेट पर आपका माल खरीद रहे हैं। हम चार रेट क्यों दे रहे हैं, कम वाले को क्यों दे रहे हैं? हम उसका कारण जानना चाहते हैं।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, it is like trading exchange और प्रतिदिन डिमांड और सप्लाई के अनुसार कीमत फ्लक्चुएट करती है। That's all.

03.03.2016/1110/केस/एजी/3

प्रश्न संख्याः 2669.

श्री विनोद कुमारः उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के "ख" भाग के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कंडयाल (खण्डैल) फुट ब्रिज की डी.पी.आर. प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दिनांक 22.07.2012 द्वारा 28.63 लाख रुपये की प्रदान की गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि 22.07.2012 को इसकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति सरकार को मिल गई थी

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.3.2016/1115/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 2669-------- क्रमागत

श्री विनोद कुमार जारी

तो क्या कारण रहे कि उस फुट ब्रिज का कार्य आज दिन तक शुरू नहीं किया गया? दूसरा, क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फुट ब्रिज का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

Chief Minister: Mr. Deputy Speaker, Sir, Kandyal footbridge was included in State budget 2012-2013 with a budget provision of Rs. 20,000/-. There was

budget provision of Rs. 80,000/- in subsequent years. The AA&ES has been accorded by SE, Mandi on 22.07.2012 for Rs. 28.63 lacs. Due to inadequate budget provision, the tender could not be called for footbridge. However, a new motorable bridge on Kandyal-Nandi road, which is approximately 50 meters downstream of Kandyal footbridge, is being constructed under NABARD and likely to be completed by June, 2016. बगल में 50 मीटर नीचे एक नया पुल बन रहा है और वह इस साल जून महीने तक तैयार हो जायेगा। That should serve your purpose.

श्री विनोद कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कंडयाल से लगभग 50 मीटर ऊपर एक नया पुल बन रहा है; परंतु ऐसा नहीं है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर मोटरेबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। वहां की स्थिति के बारे में शायद विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी को गुमराह कर रहा है। जहां पर वह फुट ब्रिज बन रहा है वहां न तो कोई सड़क की सुविधा है और न ही वहां पर सड़क बन सकती है। वह पुल दो पंचायतों को आपस में मिलाता है। उसमें ग्राम पंचायत छपराहन और ग्राम पंचायत नांडी तथा साथ में लगती तीसरी ग्राम पंचायत तांदी है। वहां सब लोगों का आना-जाना उसी रास्ते से है। कई बार वहां पर दुर्घटनाएं भी घटी है तथा उसमें एक-दो जानें गई है। मेरे हिसाब से आपको विभाग द्वारा दी गई जानकारी गलत है। इसलिए मेरा निवेदन है

3.3.2016/1115/av/ag/2

कि उस फुट ब्रिज का निर्माण जनहित में किया जाए और मैं इस बारे में मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूचना मिली है मैंने उसके आधार पर उत्तर दिया है। एक फुट ब्रिज बन रहा है और उसके 50 मीटर ऊपर एक मोटरेबल ब्रिज बन

रहा है। इसलिए यह महसूस किया गया कि जब 50 मीटर की दूरी पर दूसरा पुल बन रहा है तो शायद पहले पुल की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य ने इस बारे में बार-बार आग्रह किया है इसलिए मैं इसके ऊपर पुनः विचार करूंगा।

श्री विनोद कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न के 'ख' भाग में यहां पर विभाग की ओर से जो उत्तर आया है कि नैंडी ग्लू से झुंगी सड़क और झुंगी में मोटरबेल पुल की डी.पी.आर. बन कर तैयार हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस डी.पी.आर. को बने हुए लगभग एक वर्ष से ऊपर का समय हो गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उस डी.पी.आर. को बने हुए एक वर्ष से ऊपर का समय हो गया है तो वह डी.पी.आर. कहां पर है? वह ई.एन.सी. या एस.ई. के पास है, एक्सियन या एस.डी.ओ. के पास है या चीफ इंजीनियर के पास है? मैं चाहूंगा कि जब उसको बने हुए एक साल से ऊपर का समय हो गया है तो माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करें कि आज वह डी.पी.आर. कहां पर है? इस डी.पी.आर. का जो बचा हुआ कार्य है क्या उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन देने की कृपा करेंगे?

मुख्य मंत्री **टी सी द्वारा जारी**

03.03.2016/1120/TCV/AS/1
प्रश्न सं0 2699 --क्रमागत

मुख्य मंत्रीः वैसे तो मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो सवाल उठाया है, इसके बारे में मैं फिर से जानकार प्राप्त करूंगा। जो फुट ब्रिज वहां पर बनना है, वह अवश्य बनना चाहिए। दूसरा जो ब्रिज बन रहा है, वह काफी दूरी पर है, इसमें डिसटेंस के बारे में डिस्पियूट है। इसके बारे में मैं मालूमात करूंगा। बाकी जो दूसरा पुल बन रहा है, वह 16 जून, 2016 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने जिक्र किया है, इसलिए इस सारे मसले के ऊपर विचार किया जाएगा।

03.03.2016/1120/TCV/AS/2

प्रश्न संख्याः 2700

श्रीमती आशा कुमारीः उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। इन्होंने साईट पर जाकर लैंड स्लैक्ट की। मैं इनसे यह जानना चाहती हूं कि लैंड ट्रांसफर का केस किस स्ट्ेज पर है? एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस हो गई है या नहीं? बस स्टैंड बनाने के लिए जो लैंड अवेलेबल है उसके नक्शे पास हो गये हैं या नहीं? क्या इसको डिर्पाटमैंट बनाएगा या इसको आप पी0पी0पी0 मोड़ पर बनाएंगे?

खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय,डलहौजी पर्यटन के हिसाब से और वैसे भी महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। मैं अपने आप भी दो बार वहां जाकर आया हूं। आज भी सुबह हमारे अधिकारियों ने डिप्टी कमिश्नर से बात की है कि यह लैंड जल्दी से विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी जाये। डलहौजी में एक बढ़िया बस स्टैंड बनाकर देंगे,चाहे वह पी0पी0पी0 मोड़ पर हो या बी0ओ0टी0 मोड़ पर हो। एफ0सी0ए0 केस के लिए कागज़ तैयार कर दिए गए हैं और मैंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि बाकी प्रोसैस होता रहेगा। आप टेंडर का प्रोसैस चालू करो।

03.03.2016/1120/TCV/AS/3

प्रश्न संख्याः 2701

श्री महेन्द्र सिंहः आरदणीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं और जो हमारा मूल प्रश्न था, इसमें लिखा था किन-किन योजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है, ब्यौरा कार्यवार दें। हमने ब्यौरा वर्क-वाईज़ मांगा था। लेकिन विभाग ने जो उत्तर दिया है, उस उत्तर में गोलमोल करके लिख दिया है कि सारे 493 काम हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 493 कामों में से अभी तक कितने काम आरम्भ हो चुके हैं? जिन कार्यों के लिए नाबार्ड से राशि मिली है

और राशि 2013-14 व 2014-15 के वर्ष में मिली है। नाबार्ड की जो राशि होती है, उसका एक स्टिपुलेटिड पिरियड होता है। मेरी जानकारी के अनुसार छोटी योजना के लिए 3 साल है और बड़ी योजनाओं के लिए 4 साल है। क्या वज़ह है कि जो 2013 और 2014 के काम है, आज तक उनके टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई?

दूसरा, माननीय मुख्य मंत्री जी जो भाग 'ग' है, उसमें विभाग का जवाब आया है कि लोक निर्माण विभाग के 20 ऐसे कार्य हैं, जिनको 2012 से पहले स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह सोचने का विषय है कि 20 कार्य 2012 से पहले के स्वीकृत है, लेकिन वे 20 कार्य अभी तक भी शुरू नहीं हो सके हैं। उन 20 कार्यों के शुरू न होने के क्या कारण है? मैंने प्लानिंग की बैठक में भी आपसे जिक्र किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक ब्रिज़ है, जिसके अभी तक टेंडर नहीं हुए हैं। जिसके लिए राशि नाबार्ड द्वारा 2011-12 में दी गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

3.03.2016/1125/RKS/AS/1

प्रश्न संख्याः 2701 क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह ....जारी

जो वर्ष 2009-10 व वर्ष 2011-12 के नावार्ड के काम है, क्या कारण है कि वे आजतक समाप्त नहीं हुए?

उपाध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने जो उत्तर दिया है, वह बहुत विस्तृत है। डिटेल में है। एक-एक योजना के बारे में बताया गया है। शायद माननीय सदस्य ने उस उत्तर को पढ़ने की ज़हमत नहीं की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब हमारा उत्तर आता है तो उस उत्तर को आप पूरी तरह पढ़ो। उत्तर को सार दो और उस सार को अपने दिमाग में रखो, तब प्रश्न पूछो। आप यूं ही खड़े होकर पूछते रहते हैं। इस उत्तर को पढ़कर मेरी भी नॉलेज बढ़ी है। I know what is happening. उपाध्यक्ष महोदय, मैं

आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि प्रदेश में वर्ष 2007-08 से 31 दिसम्बर, 2012 तक 1,092 विधायक प्राथमिकताओं के कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा 2,080 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। इन स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण किए गए, अधूरे एवं आरम्भ नहीं किए गए कार्यों का विभागवार ब्यौरा निम्न हैः

विभाग का नाम	पूर्ण किए गए कार्य	अधूरे कार्यों की संख्याः	आरम्भ नहीं किए गए कार्यों की संख्याः	योग
लोक निर्माण	16	357	20	593
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	285	209	5	499

इसके उपरान्त आई. पी.एच. एवं लोक निर्माण विभाग से सबंधित 25 आरम्भ नहीं किए गए कार्यों की टेंडर प्रकिया चल रही है। शेष 18 सड़कें निमार्ण योजनाओं के

3.03.2016/1125/RKS/AS/2

र्य, एफ.सी. ए. और निजी भूमि के कारण आरम्भ नहीं किए गए हैं। यह इसकी वस्तुस्थिति है। क्या आप कुछ और पूछना चाहेंगे? इसमें समस्या यह है कि 3 एम.एल.एज. ने एक ही प्रश्न संयुक्त रूप से पूछा है।

महेन्द्र सिंहः यह हमारा अधिकार है।

मुख्य मंत्री : ठीक है, आप अपने बारे में अलग-अलग पूछो।

श्री रविन्द्र सिंहः इन प्रश्नों को विधान सभा क्लब करता है, हम नहीं करते हैं।

मुख्य मंत्री : विधान सभा को भी तीन एम.एल.एज. के प्रश्न क्लब नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्षः सभी को बोलने का मौका मिल रहा है ।

श्री रविन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो तीन विधायकों ने ये प्रश्न किए थे, वे अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित थे और इनमें अलग-अलग तरह की भाषा का प्रयोग किया गया था। इन प्रश्नों को विधान सभा सचिवालय क्लब करता है, हम नहीं करते हैं। जो प्रश्न किए गए हैं, वे विधान सभा सचिवालय ने क्लब कर दिए हैं। जो उसमें 'क' भाग में पूछा है वह हमने नहीं पूछा था, यह विधान सभा सचिवालय ने क्लब करने के बाद पूछा कि दिनांक 1.01.2013 से 31.01.2016 तक किन-किन याजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई, ब्योरा कार्यवार दें? आपने जवाब दिया, उसमें बताया गया कि 493 योजनाएं स्वीकृत की गई। आपने जवाब कार्यवार नहीं दिया। आपने विभागशः जवाब दिया। आपने सड़कों व पुलों के बारे में 262, लघु सिंचाई योजनाएं 91, ग्रामीण पेयजल योजनाएं 136 व अन्य योजनाएं 4 बताई और 493 योजनाएं पूरी कर दी गई।

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

श्री रविन्द्र सिंह ... जारी

जबकि हमने अपने मूल प्रश्न में कार्यवार सूचना चाही थी। हमारा परिपूरक प्रश्न है कि कार्यवार किन-किन योजनाओं की स्वीकृति हुई है और उनके लिए कितना-कितना धन स्वीकृत हुआ है।

इसी तरह से मेरा दूसरा परिपूरक प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, हमने अपने विधान सभा क्षेत्रों की सूचना चाही थी जिसका उत्तर पहले हमें योजना विभाग से आता रहा है। लोक निर्माण विभाग के जो कार्य हैं, जो हमारे विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 2012 में शुरू हुए थे; इन 3 सालों के कार्यों की DPR या तो बनी नहीं या अगर बनी है तो वह योजना विभाग में लंबित पड़ी हैं। वहां पर सड़कों, पेयजल योजनाओं और सिंचाई योजनाओं, जिनकी हमने प्राथमिकता दी है, का बहुत बुरा हाल है । 3 सालों में प्राथमिकता की हमारी जो योजनाएं बनीं उनमें 6 लोक निर्माण विभाग

की योजनाएं, कुछ आई.पी. एच. की सिंचाई योजनाएं और कुछ दूसरी योजनाओं के साथ कुल मिलाकर 18 योजनाएं बनी हैं। इन 18 योजनाओं की स्थिति आज के दिन में क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दें। 'ग' भाग में जो आपने जवाब दिया, आपने सही कहा कि वह भी पूरा नहीं है। इसमें हो क्या रहा है? मुख्य मंत्री महोदय, मुझे लगता है कि आपने कुछ साल पहले यह आदेश किया था कि किसी भी ठेकेदार को दो से ज्यादा कार्य नहीं दिए जाएंगे। आपने कहा कि 2007-08 से लेकर अब तक 1092 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। वह कितनी पूरी हुईं, कितनी लंबित पड़ी हैं और कितनी में काम शुरू नहीं हो पायाः उनको अमलीजामा नहीं पहनाया गया? विभाग के अधिकारियों को चाहिए था कि अगर प्रदेश में किसी भी ठेकेदार को दो के बाद तीसरा काम मिलता है, तो उनसे पहले के काम पूरा होने के UC लिए जाएं। पहले उनसे UC लिए जाते थे कि क्या उसने वह पहले की दो योजनाएं पूरी कर दी हैं, फिर उनको तीसरा कार्य अवार्ड होता था। अगर उन्होंने वह योजनाएं आगे सबलैट कर दी हैं, सबलैट में मुख्य मंत्री महोदय, क्या हो रहा है कि न तो उन कार्यों में गुणवत्ता होती है ।

03.03.2016/1130/SLS-DC-2

और न वह कार्य सही समय पर पूरे हो रहे हैं। क्या आप फिर से आदेश करेंगे कि जिन-जिन ठेकेदारों ने प्रदेश में दो से ज्यादा कार्य लिए हैं, उन सभी कार्यों को rescind करके फिर से उनके टैंडर लगाए जाएंगे ताकि वह कार्य समय पर पूरे हों? 'ग' भाग में जो कार्य अधूरे पड़े दर्शाए गए हैं क्या आप विभाग को उनको सही समय पर पूरा करने के आदेश करेंगे?

मुख्य मंत्री : जो आपने आखिरी बात कही है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। सरकार ने पहले भी आदेश निकाले हैं और उनको कई बार दोहराया गया है कि किसी भी ठेकेदार को एक समय में दो से ज्यादा टैंडर नहीं दिए जाने चाहिए। अगर टैंडर दिए जाते हैं तो वह उसको सबलैट करता है, उससे उस कार्य की गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है और

उसकी जिम्मेवारी निरस्त हो जाती है। इस आदेश को पुनः दोबारा दोहराया जाएगा।। am very strict about it. चाहे लोक निर्माण विभाग हो या सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी ठेकेदार को दो से ज्यादा टैंडर एक दफा नहीं दिए जाएंगे। अगर दिए हैं तो उनको rescind किया जाएगा। अगर उन्होंने काम आगे सबलैट किया है, that is also not acceptable. दूसरी बात है कि जो यह सारा कंफ्युजन है it has been created by clubbing of the questions. मेरे पास तीनों विधान सभा क्षेत्रों का अलग से उत्तर नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसको अलग करके सारे प्रश्नों का लिखित उत्तर आपको भेजूंगा ताकि इसमें ऑथैंटिक डाकुमैंटेशन हो और किसी तरह का कंफ्युजन न रहे। Thank you very much.

श्री बिक्रम सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्होंने जो 'ग' भाग में अधूरे कार्यों की संख्या बताई है, इसमें आपने लोक निर्माण विभाग के 357 कार्य और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के 209 कार्य बताए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अधूरे कार्यों को ठेकेदार छोड़कर चले गए हों? इनमें ऐसी कितनी स्कीमें हैं जिनको ठेकेदार

03.03.2016/1130/SLS-DC-3

छोड़कर चले गए हैं या वह कार्य अभी चल रहे हैं? क्या उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। वर्ष 2012 से लेकर अब तक तो यह कार्य समाप्त हो जाने चाहिए थे। कहीं इनमें से कुछ स्कीमों को ठेकेदार छोड़कर तो नहीं चले गए?

जारी ...गर्ग जी

03/03/2016/1135/RG/DC/1

प्रश्न सं. 2701 क्रमागत

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, किसी एक की सूचना मेरे पास नहीं है। मेरे पास तीनों की मिलाकर सूचना है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि ये जो तीन अलग-अलग प्रश्न हैं और अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसके हरेक चुनाव क्षेत्र के उत्तर अलग-

अलग होंगे। हमने इनको क्लब करके इनका उत्तर दिया है। क्योंकि ये प्रश्न ही इकट्ठे किए गए थे **इसलिए मैंने कह दिया है कि इस प्रश्न का अलग-अलग माननीय विधायक को अलग से विस्तृत रूप से सूचना देते हुए मैं आपको पत्र लिखूंगा।**

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी भावनाओं को पूरा करने की कोशिश की है। हमने विधान सभा सचिवालय को प्रश्न दिया है और हमारे तीनों सदस्यों के प्रश्न अलग-अलग हैं। हमने जो जानकारी लेनी चाही है वह पूरे प्रदेश के बारे में है न कि हमने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों की सूचना मांगी है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जैसा इन्होंने कहा कि हम आपके तीनों विधान सभा क्षेत्रों की सूचना दे देंगे, लेकिन हमने पूरे प्रदेश की सूचना मांगी है। क्योंकि ये कोई ज्यादा काम नहीं हैं, ये कुल 493 काम हैं, तो 493 का मतलब है कि यदि एक पेज में तीस काम आते हैं, तो यह केवल मात्र 15 पेज का काम है और 15 पेज की सूचना, विभाग इस माननीय सदन में रखने से कतरा रहा है, तो इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है।
उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 का जिक्र किया, जो योजनाएं इन पांच वर्षों की पूरी नहीं हुईं, उनमें जो अब लागत ज्यादा लग रही है और जो काम दो करोड़ रुपये का था अब वह काम दो करोड़ की जगह अढ़ाई करोड़ रुपये में होने जा रहा है। तो जो लागत ज्यादा लग रही है उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्या कोई अधिकारी जिम्मेवार है या कोई दूसरा प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार है? उसकी जिम्मेवारी भी तय की जाए। स्टीपुलेटिड पीरियड में ही सारा-का-सारा काम होना चाहिए। मैं यही माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।
मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि ऐसा ही होता अगर ये प्रश्न अलग-अलग आते। क्योंकि ये प्रश्न क्लब हुए हैं इसलिए यह उत्तर तीनों विधान सभा क्षेत्रों

का इकट्ठा दिया गया है। **आईन्दा मैं भी विधान सभा सचिवालय से चाहूंगा कि ऐसे प्रश्नों को क्लब नहीं करना चाहिए। It could create a confusion. लेकिन मैं इससे भी एक**

कदम आगे जाता हूं। मैं प्रदेश के सभी चुनाव क्षेत्रों की सूचना एक महीने के अंदर हरेक माननीय विधायक को भेज दूंगा।

प्रश्न समाप्त

03/03/2016/1135/RG/DC/3

प्रश्न सं. 2702

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न के 'क' भाग का उत्तर देकर सन्तुष्ट करा दिया है और कह दिया है कि 'प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौ सदन बनना प्रस्तावित है।' भाग 'ख' में पूछा गया था कि 'क्या इन गौ सदनों के लिए भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है।' इसका जवाब यहां पर 'जी नहीं' में दिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हरेक पंचायत ने ग्राम सभा का प्रस्ताव लगाकर खतौनी एवं तरतीमा कटवाकर और पूरी कार्रवाई करके एस.डी.एम. कार्यालय में सबमिट कर दिया, लेकिन आगे की कार्रवाई एस.डी.एम. कार्यालय में रुकी पड़ी है। मैंने इस बारे में एस.डी.एम. साहब को भी पूछा, लेकिन अभी तक एफ.आर.ए. कमेटीज़ भी पूरी विधान सभा क्षेत्र में नहीं बनी हैं। मैंने एस.डी.एम. को कई बार इस बारे में कहा है। तो मैं आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूंगा कि तहसीलदार, एस.डी.एम. और डी.सी. एवं वन के जो अन्य अधिकारी हैं इनको आदेश करें कि इस भूमि का जल्दी गौ सदन के नाम पर हस्तांतरण करने की कोशिश करें। मैं इससे सन्तुष्ट हूं कि इन्होंने 33,49,936/-रुपये का प्रावधान गौ सदन के निर्माण हेतु किया है। परन्तु यह भी अभी जिला परिषद या जो पंचायत समिति की बैठक में पारित होगा। लेकिन जब तक भूमि ही गौ सदन के नाम पर नहीं होगी, तो यह खर्च कहां होगा? इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि विभाग को आदेश दें जल्दी-से-जल्दी जिन पंचायतों के सर्टिफिकेट चले गए, उनके नाम भूमि ट्रांसफर करें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे यहां एक नैनीखड्ड पंचायत है। मैं स्वयं गया हूं, भूमि देखी है, सब कुछ पूरी कार्यवाही करके दे दी है, परन्तु आज तक विभाग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब कोई इनीशियेटिव ही नहीं लिया कि हम इस भूमि का गौ सदन के नाम हस्तांतरित करें। इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन

चाहता हूं।

एम.एस. द्वारा मंत्री शुरू

03/03/2016/1140/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2702 क्रमागत---

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने इच्छा जाहिर की है उसकी वस्तुस्थिति मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों को आदेश दिए गए हैं कि हर पंचायत के अंदर गौ-सदन बनाया जाए। इस तरह से आपकी 60 पंचायतें हैं जिन्होंने प्रस्ताव भेज दिए हैं कि हम गौ-सदन बनाएंगे। उसी सिलसिले में पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से पैसा गौ-सदन के लिए नहीं दिया जा रहा था। जो कन्वरजेंस के लिए 20 प्रतिशत पैसा जिला परिषद और पंचायत समिति के पास अनयुटिलाइज्ड था, मैंने सरकार की तरफ से ये आदेश किए कि उस पैसे को गौ-सदन के लिए या पंचायत भवन की बाउंड्री वॉल के लिए युटिलाइज किया जा सकता है। उसी कारण से आपके यहां पर चार पंचायतों को पैसा दिया गया है, जिसका मैंने जिक्र किया है। इसलिए सबसे बड़ी बात अब यह है कि फॉरैस्ट कन्जरवेशन ऐक्ट 1980 के अनुसार जब हम जमीन ट्रांसफर करेंगे तो एन0पी0वी0 कौन जमा करेगा? क्योंकि डिपोजिट मनी जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से दिया जा रहा है। जमीन जो ट्रांसफर की जाएगी वह पंचायत के नाम पर की जाएगी और उसमें फण्ड्ज जिस-जिस विभाग का होगा, यदि कोई और डिपार्टमैंट बनाना चाहता है, जैसे एनिमल हस्बैंड्री बनाना चाहता है तो उसके नाम पर जमीन ट्रांसफर होगी। उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं सदन में भी इस बात को रखना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या प्रदेश के अंदर आ रही है, वह इस तरह की है कि इस समय हमारे पास इस प्रदेश के अंदर 74 गौ-सदन हैं जहां पर हमारी कैपेस्टी 7,451 पशु रखने की है। इस वक्त 6,498 पशु उनमें रखे गए हैं और टोटल पॉपुलेशन 32130 है। ये आंकड़े वर्ष 2012 की सैंसिज के हिसाब से हैं। आज प्रश्न इस बात का आ रहा है कि माननीय

उच्च न्यायालय तो आदेश दे रहा है परन्तु यदि प्रदेश के अंदर हम गौ-सदन की बात करें तो लगभग 80 करोड़ रुपया हमें गौ-सदन बनाने के लिए चाहिए और लगभग 66 करोड़ रुपया हर साल उसके रख-रखाव के लिए चाहिए। अब उच्च न्यायालय आदेश तो दे

03/03/2016/1140/MS/AG/2

रहा है लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हम गौ-सदन चलाने के लिए और उसके उसके रख-रखाव के लिए, जिसमें चारा और जो वहां लोग रखे जाएंगे, उनके लिए 66 करोड़ रुपया साल में कैसे देंगे। आज यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यह खर्चा हर साल बढ़ता जाएगा। यह बात वर्ष 2012 की है जब हमने इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। तो आज प्रश्न इस बात का आ रहा है कि गौ-सदन तो बनें परन्तु जो एन0पी0वी0 है वह भी उसी पैसे से काटा जाएगा जो पैसा पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से डिपोजिट है। क्योंकि जो पैसा आया था वह 13वें वित्तायोग का पैसा था। अब 14वें वित्तायोग का जो पैसा है उसकी गाइड लाइन्स के मुताबिक यह पैसा सीधा ग्राम पंचायत को जाएगा और वे इसे इस फण्ड के लिए नहीं दे सकते। इसलिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अब यह उच्च न्यायालय को लिखकर दे दिया है कि अब हमारे पास पैसे का प्रावधान इसमें नहीं है।

श्री जयराम ठाकुरः उपाध्यक्ष जी, मुझे भी कुछ पूछना है।

उपाध्यक्षः वैसे यह भटियात विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न है। जयराम ठाकुर जी बताइए, क्या बोलना चाहते हैं?

श्री जयराम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि यह माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से आदेश हुआ है कि सभी पंचायतों में गौ-सदन का सरकार प्रावधान करे। मैं इस बात को मानता हूं कि यह व्यवहारिक नहीं है। हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन इसमें जो व्यवहारिक पक्ष देखने का है वह जमीन का है और उसके साथ-साथ फण्ड्ज के प्रोविजन का है। क्या आपने माननीय उच्च न्यायालय के सामने इस पक्ष को रखा कि

हम इस मसले को लेकर गंभीर हैं लेकिन उसके बावजूद भी सभी पंचायतों में गौ-सदन बनाना संभव नहीं है। नम्बर एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किया है तो क्या किया है? इसके अलावा, जब मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इस तरह का बजट प्रावधान किया ही नहीं है तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की मंशा हमें पालनी ही नहीं चाहिए कि सभी पंचायतों में हम गौ-सदन बना पाएंग।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

03.03.2016/1145/जेएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2702:-----**जारी**-----

श्री जय राम ठाकुरः-------**जारी**---------

10 पंचायतों का 15 पंचायतों का क्लस्टर बनाईये। एक विकास खण्ड में दो-तीन जगह चिन्हित करिये। वहां पर मुझे लगता है कि जमीन को भी उपलब्ध करवाना आसान हो जाएगा। एम0पी0पी0 का जो मामला है उसका भी समाधान हो सकता है और बजट प्रोविज़न का भी समाधान हो सकता है। जो व्यवाहारिक है, मैं यही मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि क्या व्यवाहारिक चीज की जा सकती है? यह महत्वपूर्ण विषय है। उसके लिए आपने कुछ नीति बना करके माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बात रखी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं मेरे चुनाव क्षेत्र में जो हमारा जंजैहली से ऊपर का इलाका शिकारी माता के साथ पड़ता है वहां पर बड़ी तादाद मात्रा में पशु छोड़ देते हैं। हमने प्रयत्न किया कि इन पशुओं को सब्जी के मौसम में वहां से ला करके गौ सदन में रखें। जंजैहली में रखें, लेकिन उसके बावजूद उसको जल्दी-जल्दी बनाया गया। 50 से ज्यादा पशु वहां पर उसके अन्दर मर गए। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि क्या आप इस बात को ले करके जो व्यावहारिक पक्ष है उसके लिए कोई ठोस नीति बना करके उस बारे में उच्च न्यायालय को भी अवगत करवाएंगे। इसी के साथ जो एक ज्वलंत मुद्दा है कि गौ सदन बनने चाहिए। आवारा पशु शब्द भी ठीक नहीं है। जो पशुधन इस प्रकार से छोड़ दिया गया है उसको इकट्ठा करने के लिए हम उसके लिए

कोई नीति बनाएं ताकि संरक्षण देने की स्थिति में हो पाएं।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, आवारा पशु को आवारा कहना गलत है। अवारा वह है जिन्होंने पशु को छोड़ा है। वह आवारा पुरूष है, जब उसके पास वह पशु इस्तेमाल नहीं हुआ और उसे छोड़ दिया। गाय, बैल, बछड़ा जो लोग डण्डा मार कर बाहर भेजते हैं, वे लोग आवारा हैं। कईयों के ऊपर तो बहुत सारे जख्म हो जाते हैं। मैं यह भी कहता हूं कि हर पंचायत के अन्दर पशुशाला हो यह व्यवाहारिक नहीं है। हमको

03.03.2016/1145/जेएस/एजी/2

क्लस्टर बनाना पड़ेगा। एक चुनाव क्षेत्र के अन्दर एक या दो वहां की आबादी के मुताबिक हमें बनाना पड़ेगा और वह व्यवाहारिक है। यह कहना कि हर पंचायत में पशुशाला खोली जाए वह व्यवाहारिक नहीं है। वह न तो ठीक से चलेगी और न ही उसके लिए संसाधन होंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि जिन्होंने अपनी जमीन के लिए पशु तैयार किए हैं वे आज सड़कों में घूम रहे हैं। वे एक खेत से दूसरे खेत में और एक गांव से दूसरे गांव में जख्मी होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज़ है। अभी हाल ही में सरकार ने गौवंश बोर्ड का गठन किया है उसके लिए शुरू में सरकार ने 10 करोड़ रूपया दिया है इसमें जितनी भी आगे धन की आवश्यकता होगी उसको बढ़ाया जाएगा। मेरी यह राय है और माननीय सदन भी इसमें अपनी राय दे सकता है कि बजाय एक-एक पंचायत में पशुशाला हो उसको हम क्लस्टर में बनाएं ताकि प्रदेश में एक चुनाव क्षेत्र में एक पशुशाला हो या दो हो। इतना तो कर सकते हैं और पंचायतें तो हमारी 3226 हैं इसलिए इतनी पंचायतों में पशुशाला चलाना सम्भव नहीं होगा। इस बारे में सरकार अपनी राय हाई कोर्ट में रखेगी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मुख्य मंत्री महोदय ने इन्टरवीन किया है इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात भी है कि बेसहारा पशु केवल प्रदेश से ही नहीं पड़ौसी राज्यों से ला करके छोड़े जाते हैं और

जहां-जहां से एन्ट्री होती है वहां पर क्या प्रदेश सरकार उस एन्ट्री को बन्द करने का कदम उठाएगी कि शरारती तत्वों को वहीं रोका जाए ताकि उन पशुओं को यहां आने से रोका जा सके?

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं जो आवारा पशु है उसमें विस्थापित पशु हिमाचल के भी हैं और पड़ौसी राज्यों से भी पशु रात को गाड़ियों में ला कर हिमाचल में छोड़े जाते हैं। जहां-जहां से ये पशु आते हैं उन रास्तों में हम चौकियां बना करके उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

03.03.2016/1150/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2702 क्रमागत

श्रीमती आशा कुमारीः उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी ने जवाब दिया है कि यह हर पंचायत में व्यावहारिक नहीं है। यह मसला प्लान की मीटिंग में भी उठा था और मुख्य मंत्री महोदय ने विभाग को रिव्यू पीटिशन फाइल करने के लिए आदेश दिये थे। मैं एक तो मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उस रिव्यू पीटिशन का क्या हुआ जोकि फाइल करने के लिए आपने आदेश दिये थे?

नम्बर-2, उसी मीटिंग में मैंने यह इश्यु रेज़ किया था कि जो मंदिर न्यास हैं यानी टैम्पल कमेटीज़ हैं वे गौसदन चलाना चाहती हैं। उनको एंक्रेज करने के लिए लैंड ट्रांसफर करने के संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं? उपाध्यक्ष महोदय, गौसदन बनाना ही ज़रूरी नहीं है। केवल एक बिल्डिंग खड़ी कर देना ज़रूरी नहीं है। उसमें डैडिकेटिड लोगों की ज़रूरत है। गाय की देखभाल करने के लिए लोगों में डैडिकेशन भी चाहिए। इस तरह से पंचायत में सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर देना सही नहीं है। श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी की कांस्टीचुऐंसी में सम्लेऊ में इन्होंने एक गौसदन बनाया भी है। वह चालू भी हुआ। लेकिन उसको चलाने के लिए फंडस ही नहीं हैं। कोई डैडिकेटिड ही नहीं है जोकि गाय की देखभाल करे। जो देखभाल करने के लिए विशेष करके मंदिर न्यास आगे आ रहे हैं उनको लैंड स्थानांतरित करने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ने आदेश दिये

थे उस पर विभाग ने क्या कार्रवाई की है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय सदस्या ने जिसका ज़िक्र किया है, चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था जोकि हाई कोर्ट के साथ इसका तालमेल कर रही है। साथ में हमने एक स्ट्रे कैटल पॉलिसी 2014-15 में बनाई थी और उसके अंदर हमने जितने भी मंदिर और दूसरे ट्रस्ट थे उनके माध्यम से पैसे का प्रावधान किया था। परन्तु जैसे ही हाई कोर्ट का इंटरवैंशन हुआ, हाई कोर्ट ने इसमें कई डिपार्टमैंटस जैसे कि पी0डब्ल्यू0डी0, एनीमल हस्बैंडरी, यू0डी0 और आर0डी0 इत्यादि शामिल किये। जब सभी डिपार्टमैंटस इसमें शामिल हो गये तो यह केवल एक विभाग की कार्यप्रणाली न रह कर हाई कोर्ट द्वारा कई विभागों की कार्यप्रणाली सुनिश्चित कर दी गई। जहां तक यह प्रश्न आ रहा है यह सारे विधान सभा के सदस्यों की चिन्ता है और हम

03.03.2016/1150/SS-AS/2

इसमें मिल बैठकर कोई फैसला करें। हम स्ट्रे कैटल सैंक्चुअरी भी बना सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर हम बिजली उत्पादन करते हैं, वहां पर बरसात में पानी ऊपर आता है लेकिन गर्मी में पानी कम होता है। वहां पर हम स्ट्रे कैटल सैंक्चुअरी भी बना सकते हैं जहां पर ग्रेजिंग पास्चर भी है। उसमें हम मिल बैठकर समाधान निकाल सकते हैं क्योंकि वह लैंड जो है जैसे बी0बी0एम0बी के नाम ट्रांसफर कर दी गई है और जैसे पानी नीचे उतरता है तो उसके सराऊंडिंग के जो लोग हैं वे वहां पर अपना अनाज पैदा करते हैं। अब अगर हम उनको रोकें तो राजनीतिक कारण बन सकता है। यह जमीन सरकार के नाम पर है। इसकी फैंसिंग करके स्ट्रे कैटल सैंक्चुअरी बना कर हम इसका उपाय ढूंढ सकते हैं। यह भी सरकार प्रयास कर सकती है। परन्तु अगर इसमें सभी का सहयोग हो तभी हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री रिखी राम कौंडलः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है यह बड़ा गम्भीर है। इन्होंने एक स्पैसिफिक पूछा था कि जहां पर गौसदन बनने हैं क्या वहां

पर सरकार जगह ट्रांसफर करेगी? हिमाचल प्रदेश के अंदर कई एन0जी0ओज़0 ऐसी हैं जोकि गौसदन खुद खोलना चाहती हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस माननीय सदन में आश्वासन देंगे कि जहां-जहां से प्रस्ताव आये हैं या सरकारी जगह चयनित की है उनको सरकार जगह ट्रांसफर करेगी और एफ0सी0ए0 की जो सारी औपचारिकताएं हैं उस पर सरकार विचार करके शीघ्र लैंड ट्रांसफर करेगी क्योंकि कई एन0जी0ओज़0 गौसदन बनाना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी, इस पर स्पैसिफिक बताएं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बात उठाई है। **बहुत से एन0जी0ओज़0 जो हैं वे लैंड ट्रांसफर करने के लिए सरकार के पास आ रहे हैं। हम उनको जमीन लीज़ पर देंगे परन्तु वह जगह सरकार के नाम पर रहेगी या वह एनीमल हस्बैंडरी या पंचायत के नाम पर रहेगी।** हम एन0जी0ओज़0 के नाम पर उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। सरकार उसको केवल लीज़ पर देने के लिए तैयार है।

03.03.2016/1150/SS-AS/3

श्री सतपाल सिंह सत्तीः उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस माननीय सदन के अंदर श्री जरयाल जी लेकर आए हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक साल पहले इसमें अपना दखल दिया था तथा आज भी मीडिया में ये लगा है कि न्यायालय ने सरकार को आदेश किया है कि कम-से-कम पांच करोड़ रुपया आप गौसदन बनाने के लिए रिलीज करें।

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2016/1155/केस/एएस/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी---

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं जैसे कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में अनेकों एन.जी.ओज़. गौसदन चलाना चाहती है और अनेकों लोगों ने इकट्ठा हो कर बहुत बढ़िया गौसदन चलाए हैं। अगर आप नालागढ़ से आगे जाएंगें तो वहां पर एक जगह लगभग 500 गऊएं रखी है और बहुत बढ़िया ढंग से रखी है, जिसको आप एक आदर्श

गऊशाला कह सकते हैं । इसी तरह से वीरेन्द्र कंवर जी ने भी अपने क्षेत्र में शुरू करवाई है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इसमें हम पहले जिन्होंने एन.जी.ओज़. चलाई है, उनके साथ सम्पर्क करके उन गऊशालाओं में संख्या कैसे बढ़ाई जा सके, उनको कैसे सुख-सुविधा दी जा सके, क्या सरकार इस सम्बन्ध में कार्रवाई करेगी?

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, जैसे जयराम जी ने कहा और हम सभी इस बात को समझते हैं कि हर पंचायत में गऊशाला नहीं खोली जा सकती है तो इस तरह से क्लस्टर बना करके सरकार समयसीमा के अंदर क्या कम से कम इस साल में कुछ आदर्श गऊशालाएं खोलेगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय उपायक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, सरकार की मन्शा बिल्कुल साफ है। जैसे मुख्य मंत्री जी ने भी कहा, हमने गौ संवर्द्धन बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड गऊ सदन के अन्दर, गायों के कल्याण के लिए काम करेगा। पशु पालन विभाग के माध्यम से भी हमने साढ़े बहत्तर लाख रुपया उनको चारे के लिए दिया है और दूसरा आपने जो प्रश्न रखा है कि उनका कार्य यह जो गौ संवर्द्धन बोर्ड हमने गठित किया है, इसके माध्यम से चैक करेंगें कि इनमें कैसे स्ट्रैंथ बढ़ाई जा सकती है, इसको कैसे हम और आगे चला सकते हैं? इस बोर्ड का काम यही होगा कि जितने भी हमारे गौ सदन बने हैं, वे सुचारू रूप से चले। कई बार गऊ सदन जो

बनते हैं, उनमें जानवरों के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं होता। गऊ सदन बनने का मतलब ही यही है कि इस बोर्ड के माध्यम से उन गऊ सदनों की रूप रेखा व कार्य

प्रणाली के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा।

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक कहा कि जो यह गौ वंश है यह आवारा नहीं है, बेसहारा जरूर है और बेसहारा के पीछे कारण है। अब बगीचे लग गए, पशुओं की जरूरत नहीं रही या कोई पशु बूढ़ा हो गया।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो ये आवारा बछड़े छोड़े गए जो आज सांड बन गए हैं और लोगों को मार रहे हैं , क्या भविष्य में कोई ऐसी नीति सरकार बनाएगी, ऐसा विधेयक लाएगी जो लोगों के ऊपर लागू होगा ताकि ये पशु फिर बेसहारा न बनें ? वरन् गौ सदन कितने भी बना दो इनकी संख्या बढ़ती ही जाएगी। क्या ऐसी कोई नीति या कोई ऐसा विधेयक लाएंगें ताकि पशुओं को आवारा छोड़ने वालों पर अंकुश लग सके?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने बात उठाई है, मैं इनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि The Panchayati Raj Department was directed to ensure the compliance of the Provision of Section 11(A) of H.P. Panchayati Raj Act. उसमें एक्ट के अंदर पंचायतों में पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया है और उसके अनुसार जुर्माना भी लगा सकते हैं और उसमें टैगिंग करें, आईडैंटिफिकेशन डिपार्टमैंट के माध्यम से होगा यह पावर्ज़ पंचायतों को दी गई है। पंचायत इस ताकत का अपने तरीके से अनुसरण करें, यही प्रयास हो सकता है जिससे कि हम उनकी पहचान कर सकते हैं

श्री वीरेन्द्र कंवरः उपाध्यक्ष जी, यह बहुत बढ़िया सुझाव है कि क्लस्टर में गऊशालाएं खोली जाए और जो एन.जी.ओ. पहले से ही गऊशालाएं चला रही हैं, वहां पर सुविधाएं बढ़ाई जाए। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने चारे के लिए कुछ लाख रुपये पशु

03.03.2016/1155/केस/एएस/3

पालन विभाग की तरफ से दिए हैं, मेरा माननीय मंत्री जी को एक सुझाव है कि चारे का जो पैसा देना है, वह एन.जी.ओज़. को ही दें क्योंकि एनिमल हस्बैंडरी बोर्ड की तरफ से जो चारा आता है अगर वे 80 क्विंटल भी बताते हैं तो 40 क्विंटल वह निकलता है। दूसरा उसमें रेत और पानी मिक्स होता है जिसके कारण पशु उस चारे को नहीं खाते हैं ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

3.3.2016/1200/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 2702-------- क्रमागत

श्री वीरेन्द्र कंवर---------- जारी

जो सुविधाएं दी जाएं वह सीधी एन.जी.ओ. को दी जाए, बीच में विभाग को न डाला जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह ठीक है और हम आपके सुझाव के ऊपर गौर करेंगे तथा ऐसा कुछ है तो इस बारे में विभाग को निर्देश दिए जायेंगे।

प्रश्नकाल समाप्त

3.3.2016/1200/av/dc/2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : उपध्यक्ष जी, मेरा एक अतारांकित प्रश्न संख्या 1078 लगा है मगर मुझे इसका उत्तर नहीं मिला है। इसके लिए लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1078 विलोप किया गया। इस प्रश्न को विलोप करने के क्या कारण है? यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण था और मुझे इसका उत्तर नहीं मिला। मैं आपसे इस बारे में जानकारी चाहता हूं।

मेरा यह प्रश्न था कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) के दिशा-निर्देशों की अनुपालना हेतु समय-समय पर शपथ पत्र दाखिल किए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सभा पटल पर रखें और इसका *ख* पार्ट है कि सरकार ने उसकी अनुपालना के लिए क्या-क्या प्रयास किए और कितनी बैठकें एवं पत्राचार किया? उनकी प्रति भी सभा पटल पर रखें। यह अत्यन्त जनहित का मुद्दा है मगर इस प्रश्न का उत्तर मुझे मिला नहीं, इसको विलोप करने के क्या कारण है?

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मुझे मेरे चैम्बर में मिलें, हम इस बारे में वहां चर्चा करेंगे।

3.3.2016/1200/av/dc/3

कागजात सभा पटल पर

उपाध्यक्ष : अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, दफ्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एफ.डी.एस.-ए (3)-12/2002 दिनांक

17.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, दफ्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः एफ.डी.एस.-ए (3)-12/2002 दिनांक 17.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

3.3.2016/1200/av/dc/4

उपाध्यक्ष : अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री कुछ दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

आबकारी एवं कराधान मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो कि निम्न प्रकार से हैंः-

i. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उपधारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर(पंचम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(1)-7/2012-लूज़ दिनांक 16.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.12.2014 को प्रकाशित;

ii. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10

के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-23/2014 दिनांक 30.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2014 को प्रकाशित;

iii. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उपधारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-7/2011-वॉल-I

3.3.2016/1200/av/dc/5

दिनांक 30.1.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 2.2.2015 को प्रकाशित;

iv. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3), (4) और (5) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-7/2011-वॉल-I दिनांक 30.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2015 को प्रकाशित;

v. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-28/2014

दिनांक 19.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.03.2015 को प्रकाशित;

vi. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि- 'क' और 'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-23/2014 दिनांक 27.04.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.04.2015 को प्रकाशित;

vii. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 15.5.2015

3.3.2016/1200/av/dc/6

द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.5.2015 को प्रकाशित;

viii. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा(3) और (4) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) अमैंडमेंट रूल्ज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 15.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.05.2015 को प्रकाशित;

ix. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-

एफ(10)-2/2015-लूज़ दिनांक 03-6-2015 तथा इसका समसंख्यक शुद्धिपत्र दिनांक 03.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06-6-2015 तथा दिनांक 04.07.2015 को प्रकाशित;

x. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याः ईoएक्सoएनo-एफ(10)-20/2014-लूज़ दिनांक 25.7.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.7.2015 को प्रकाशित;

xi. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'घ' में संशोधन जोकि

3.3.2016/1200/av/dc/7

अधिसूचना संख्याः ईoएक्सoएनo-एफ(10)-23/2014 दिनांक 30.7.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.7.2015 को प्रकाशित;

xii. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'क' के भाग-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याः ईoएक्सoएनo-एफ(10)-20/2014-लूज़ दिनांक 01.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.10.2015 को प्रकाशित;

xiii. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम,

2010 की धारा 3 की उपधारा(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 से संलग्न अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 07.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.11.2015 को प्रकाशित;

xiv. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-16/2014 दिनांक 07.11.2015 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10-11-2015 को प्रकाशित;

xv. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (पंचम संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः

3.3.2016/1200/av/dc/8

ई०एक्स०एन०-एफ(10)-7/2011-वोल्यूम-I दिनांक 14.12.2015 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15-12-2015 को प्रकाशित; और

xvi. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2015 से संलग्न अनुसूचि-'क' के भाग-2 जोकि अधिसूचना संख्याः ई०एक्स०एन०-एफ(10)-5/2010-लूज़ दिनांक 04.01.2016 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05-01-2016 को प्रकाशित ।

3.3.2016/1200/av/dc/9

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष : अब श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कुलदीप कुमार, सभापति : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्राक्कलन समिति (वर्ष 2015-16) के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के विभिन्न विकासात्मक कार्यों तथा आय-व्ययक आंकड़ों की संवीक्षा पर आधारित है; और

ii. समिति का 16वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा विद्युत विभाग से सम्बन्धित है ।

iii.

3.3.2016/1200/av/dc/10

उपाध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार, सभापति : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास

समिति (वर्ष 2015-16) की 16वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

3.3.2016/1200/av/dc/11

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह नियम 62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री बिक्रम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 29 फरवरी, 2016 को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित "जसवां-परागपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अमरोह पेयजल भण्डारन टैंक से हो रही मटमैले पानी की आपूर्ति" से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

आज हिमाचल प्रदेश में हमारे विधान सभा के अंदर अलग-अलग विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्र की बात रखते हुए इस बात का अक्सर जिक्र किया है कि पानी साफ नहीं मिल रहा है।

टी सी द्वारा जारी

03.03.2016/1205/TCV/DC/1

श्री बिक्रम सिंह-- जारी

यहां पर सदन में पीलिया के ऊपर भी डिसकशन हुआ। कई बार सरकार समाचार पत्रो के माध्यम से भी यह बात कहती रही है कि यह केवल समाचार पत्रों में ही आ रहा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हैं। शिमला और सोलन में पानी की वज़ह से पीलिया की समस्या पूर्ण रूप से बढ़ी है और प्रदेश के अन्दर बहुत से जिलों/स्थानों में इसी वज़ह से पीलिया की समस्या से लोग ग्रस्त है। पिछले दिनों किसी की मौत हो गई थी, मैं वहां

गया था और वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि हमें यहां पर जो पानी मिल रहा है, वह ठीक नहीं मिल रहा है। इससे पहले जो वहां पर विभाग के जे0ई0 हैं, उनको मैंने यह बात लगभग 15 बार कही होगी कि आप उस वॉटर सप्लाई स्कीम को देखिए। लोगों की शिकायतें आ रही है कि पानी 4-4 दिन के बाद आ रहा है और जो पानी आ रहा है, वह ठीक नहीं आ रहा है। मैंनें स्वयं ही इस स्कीम को देखने का निर्णय लिया। यह वॉटर सप्लाई स्कीम "अमरोह-गुमी-कौही" नाम से हैं और इस स्कीम के ऊपर 96 लाख रूपया खर्च हुआ है। इसकी डी0पी0आर0 2009-10 में बनाई गई थी और इसकी सैंक्शन दिनांक 23-3-2011 को हो गई थी। इसकी टेस्टिंग नवम्बर, 2015 में हुई है। इस स्कीम पर 96 लाख रूपया खर्च करने के पश्चात् जब मैंने उस स्कीम पर जाकर देखा तो उस टैंक में पानी बिल्कुल कम था। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन अधिकारियों ने इस स्कीम को अप्रूव किया, उनके विरूद्व कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे, जब हमने उस टैंक का ढकन उठाकर देखा तो उसमें जिन मजदूरों ने टैंक का काम किया होगा उनके कपड़े उसमें पड़े हुए थे। उसके बाद मैंने एक लड़के को टैंक के अन्दर जाकर देखने के लिए कहा कि इसके अन्दर और क्या-क्या पड़ा हुआ है? उपाध्यक्ष महोदय, उस टैंक में कबूतर मरे हुए पड़े थे। जिन क्षेत्रों में वह पानी जाता है, वहां पर अधिकांश लोग बीमार है। आप चाहें तो अपने अधिकारियों को भेज कर पता भी कर सकते हैं। ये सारे लोग पानी ठीक न मिलने के कारण बीमार है। इसके बाद जब अखबार में आया तो जो वहां पर जे0ई0 है, जिनका नाम रमन है। इन्होंने वर्शन दिया कि 'अमरोह भण्डारण टैंक के अन्दर मज़दूरों के कपड़े मिले हैं। शिकायत मिलने पर टैंक की सफाई कर दी गई है और कबूतर मिलने की बात सही नहीं है।' लेकिन यह बिल्कुल सच्चाई है। यह तो एक स्कीम की बात हो रही है। पिछले कल श्री इन्द्र सिंह का प्रश्न 2675 'फिल्टर बैड'

03.03.2016/1205/TCV/DC/2

के बारे में लगा हुआ था। उसमें आपने जवाब दिया हुआ है कि विभाग की 18 योजनाएं ऐसी है, जहां 'फिल्टर बैड' नहीं लगे हुए हैं। यहां सदन में जो प्रश्न लगे हैं, उनसे आपके विभाग की बहुत-सी कमियां नज़र आ रही है। अभी आपने जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से बुलवाया है, उसमें आपने पैसा खर्च करने के बारे में

बड़ी-बड़ी बातें की है। इस स्कीम के ऊपर भी एक करोड़ से ज्यादा खर्चा हो गया है। लेकिन जो यह स्कीम हैं वहां उसके सोर्स में पानी ही नहीं हैं। वह बिल्कुल सुखा हुआ है। पांच महीने पहले उसकी कमीश्निंग हुई है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि जो अधिकारी/कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं और एक विधायक के कहने पर किसी स्कीम पर जाना भी पसंद नहीं करते हैं, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र जसवां-परागपुर के लिए जो स्कीम है, कृपया उसकी ओर ध्यान दें। इस स्कीम को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? यदि वह ठीक नहीं हो सकती है, गलत बनी है, तो जिन पंचायतों को इस स्कीम से पानी उपलब्ध होता था, उनके लिए हैंडपम्प और उसके साथ मशीनें लगाने का प्रावधान किया जाये। ताकि लोगों को पानी मिल सकें। मैं चाहूंगा कि माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में आश्वास्त करें।

03.03.2016/1205/TCV/DC/3

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह(जसवां-प्रागपुर) द्वारा नियम-62 के जो विषय यहां सदन में उठया गया है, उसके बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगी। दिनांक 29 फरवरी, 2016 को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित "जसवां-परागपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अमरोह पेयजल भण्डारन टैंक से हो रही मटमैले पानी की आपूर्ति" से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

3.03.2016/1210/RKS/AG/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री.... क्रमागत

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इसकी वस्तुस्थिति से अवगत करवाना चाहती हूं। इस सम्बन्ध में सूचिव किया जाता है कि दिनांक 29.09.2016 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अमरोह पेयजल भण्डारण टैंक से मटमैला पेयजल जनता को मुहैया करवाने का समाचार बिल्कुल निराधार व तथ्यों से परे है। गांव अमरोह के लिए वर्तमान में

पेयजल योजना कस्वा कोटला से पेयजल आपूर्ति की जा रही है और जिस अमरोह टैंक का उल्लेख किया गया है वह भण्डारण टैंक नहीं अपितु अमरोह, कोई, गुम्मी आदि गांवों के लिए निर्माणाधीन पेयजल योजना का स्त्रोत रिसाव कुआं(Source Percolation Tank) है। यह अभी अडर कंस्ट्रकशन है। इय पेयजल योजना की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दिनांक 25.03.2011 को 96.32 लाख रुपये की हुई थी। योजना का 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। हम आपके सामने सच्चाई की बात कर रहे हैं। जो गलतियां हो रही है उसके बारे में हम जरूर पता करेंगे। मै आपको बताना चाहती हूं कि इस योजना के अन्तर्गत यह रिसाव कुआं हाल ही में पूरा किया गया है। अभी यह नया है। इसलिए हो सकता है कि कोई पिछली 'कान की कहानी' बातें बता रहे हो। हमें शर्म भी आती है कि लोग किस तरह की बातें बना देते हैं। इस पेयजल योजना की टैस्टिंग की जानी अपेक्षित थी। यह हम कहते हैं। जिसके लिए निर्माणाधीन रिसाव कुएं की सफाई करवाई गई व इसके अन्दर निर्माण हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री को बाहर निकाला गया था। जो गंदगी थी उसको निकाल दिया गया है। यह हमें बताया गया है। अमरोह गांव को अभी तक पुरानी पेयजल योजना कस्वा कोटला से ही पानी की आपूर्ति हो रही है, अतः उपरोक्त गांव को मटमैले पानी की आपूर्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। कौन गलत है कैसे गलत है, उसको हम सुधारेंगे।

हम आपको बताना चाहते हैं अमरोह, कोई, गुम्मी आदि गांव पेयजल योजना कस्वा कोटला के टेल एंड, दूरस्थ छोर पर होने के कारण यहां तीसरे दिन पानी की आपूर्ति की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन गांवों के लिए नई योजना

3.03.2016/1210/RKS/AG/2

अनुमोदित करवाई गई थी व इसके शीघ्र चालू होने पर इन गांवों को नियमित व सूचारू रूप से पेयजल आपूर्ति उपलब्ध होगी व इन गांवों के कटने से पेयजल योजना कस्वा कोटला के बाकी गांवों में भी अतिरिक्त जल की उपलब्धता से पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त जसवां परागपुर विधान सभा क्षेत्र सहित समस्त क्षेत्रों में पेयजल भण्डारण टैंकों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है तथा सभी पेयजल योजनाओं से स्वच्छ एवं कलोरिन युक्त पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके सैम्पल भी समय-समय पर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग भी समय-समय पर पानी के सैम्पल चैक कर रहा है जो अब तक ठीक पाए गए हैं। अगर इसमें भी आपको लगता है कि गलतियां है तो फिर से इसके बारे में गौर किया जाएगा। मैं आपको विश्वास देना चाहूंगी ये पिछली गलतियां थी, जिन्हें अब ठीक कर दिया गया है। क्योंकि मैं वहां खुद देख कर आई हूं। हो सकता है जैसा आप कह रहे हैं पहले लोग वहां गंदगी फैलाते थे, कहीं गंदे कपड़े रखे होते थे, कहीं कबतूर बैठे होते थे, वह हो सकता है। ऐसा मैंने खुद तो नहीं देखा, पर लोग कह रहे हैं। मैं आपको इतना विश्वास देना चाहूंगा कि जो बात मैंने आपको लिख के भेजी है उसका आप पूरा इस्तेमाल करेंगे। जहां गलतियां होगी वहां हम कोशिश करेंगे की काम अच्छे से हों। मैं आपको यह विश्वास देना चाहती हूं। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

03.03.2016/1215/SLS-AG-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ...जारी

आपके अभी तक जितने भी प्रश्न आए, उन पर बात नहीं हो सकी क्योंकि एक-एक प्रश्न का ही समय काफी लंबा रहा है और दूसरे प्रश्न नहीं उठ सके। हम आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको भेज रहे हैं, आप उनको पढ़ लें। उनमें आपको जो कुछ सच्चाई लगती है, वह हमें बताएं। हम थब्बे-के-थब्बे आपके पास भेज रहे हैं। कई सदस्यों ने ले भी लिए हैं और आप सब भी अपने-अपने कागज़ात ले लें। इनमें जो सच्चाई है वह सच्चाई है और जो गलती है, उसे हमें मानना है। यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूं।

धन्यवाद।

श्री बिक्रम सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसमें इन्होंने कहा है कि अगर पहले गलती हो गई हो, उसे हम ठीक करेंगे । लेकिन जो आपके पास लिखकर आता है, आप विभाग को ज़रूर यह निर्देश दें कि इसमें कम झूठ लिखें। आप कह रहे हैं कि स्कीम चली ही नहीं है जबकि मैं कह रहा हूं कि वह स्कीम चली है। ...(व्यवधान)... जब आपने बात की है तो मैं इसमें अपनी बात रखूंगा। उस स्कीम पर पंप एक घंटे से ज्यादा नहीं चलता क्योंकि वह स्कीम गलत बनी है। जहां से पानी आता था वह अब आना बिल्कुल बंद हो गया है, जिस दिन से यह सब शुरू हुआ है। अब विभाग वहां पर कोई बोर करने का प्रोविजन करेगा। वहां पर स्कीम चल रही है जबकि आप उसे 95% प्रतिशत् बता रहे हैं। जिस व्यक्ति की वहां पंप पर ड्यूटि है, जो वहां पर पानी छोड़ता है, मैं उसका नाम भी बता सकता हूं। यह ठीक है कि उसकी आलटरनेट स्कीम है जहां से पानी पूरा किया जाता है, वह टेल एंड है। लेकिन उस स्कीम के चालू होने के बाद वहां पर यह स्थिति है। जो वहां पर ऐसी चीजें मिली हैं वह कोई अच्छी नहीं है। यह मैंने नहीं लिखा बल्कि समाचार-पत्र में मैंने आपके जे.ई. का वर्जन पढ़ा। उसका नाम रमन है। उसने कहा कि कपड़े मिले हैं। कबूतर उसने नहीं देखा। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से काम करें। धन्यवाद।

03.03.2016/1215/SLS-AG-2

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : मैंने आपको सच्चाई की बात बताई है। हम चाहते हैं कि वहां ठीक कार्रवाई हो। हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। जो बात मेरे सामने है, मैं इसे जानती हूं कि किसी आदमी ने ऐसा काम किया होगा जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती। उसने कूड़ा, दूसरा सामान, सड़े हुए कबूतर ला दिये और इस तरह से बदनामी कर रहे हैं। ऐसे बदनामी करने से हमें क्या लाभ हो रहा है या आप लोगों या जनता को क्या लाभ हो रहा है? यह हम सभी को समझना है। अगर सच्चाई है तो सच्चाई से काम होगा। जो गलती करता है उसको भी समझाना पड़ेगा। आप हमारे विधायक हैं। जो

दोषियों ने काम किया है आप उसके लिए भी हमें कह रहे हैं जबकि ऐसी बात नहीं है। इसलिए बात को सच्चाई से बोलने की आवश्यकता है। जब हमारे पास कमियां हैं तो हम बोलेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। अख़बारों में जो बातें आती हैं वह तो लोग चर्चा करने के लिए लिखते हैं। वह किसी की भी बात कर सकते हैं, अख़बार वालों की मरज़ी है, जो कहें। हमें यह सब अच्छा नहीं लगता और हम इस बात को नहीं चाहते। ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष : इसमें कोई डिबेट नहीं होती। ...(व्यवधान)... क्लैरिफिकेशन हो गई है।। am not allowing you. ...(व्यवधान)... कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर है तो बताइए, otherwise there is no debate on it. ...(व्यवधान)... जय राम ठाकुर जी, ठीक है, आप अपना प्वायंट ऑफ ऑर्डर रखिए।

03.03.2016/1215/SLS-AG-3

Point of Order

श्री जय राम ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का ज़िक्र करना चाहता हूं। बार-बार सत्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ मंत्री इस प्रकार से कहते हैं कि विपक्ष के विधायक गैर-जिम्मेदाराना ढंग से बातें कर रहे हैं। यह संदेश ठीक नहीं है। जितने जिम्मेवार वहां के लोग अपने आप को समझते हैं उससे कम जिम्मेवार लोग इस पक्ष के भी नहीं हैं। इन्होंने जो बात यहां पर कही; विधायक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह स्वयं वहां जाकर आया। (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री से) मैं आपका बहुत आदर करता हूं लेकिन यह बात ठीक नहीं है। आप हमारे विधायकों को बिना वजह के इस प्रकार से गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर मुझे लगता है कि यह संदेश वरिष्ठ नेताओं की ओर से कम-से-कम नहीं आना चाहिए।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : आपको एक छोटी-सी बात को इतना बढ़ाकर नहीं करना चाहिए। हमने पहले ही कहा कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम उसको ठीक करेंगे। मैं किसी विधायक की गलती की बात नहीं कर रही थी। मैंने पत्रकार की बात

की। पत्रकारों ने जो बातें लिखी हैं वह गलत लिखी हैं। मैंने उनकी बात की। इनके बारे में मैंने कोई बात ही नहीं की। हमने वही कहा जो कहना था। सच्चाई की बात तो करनी है।

03.03.2016/1215/SLS-AG-4

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा

उपाध्यक्ष : अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी।

सबसे पहले इस चर्चा में श्री राकेश कालिया जी भाग लेंगे।

श्री राकेश कालिया जी ...गर्ग जी के पास

03/03/2016/1220/RG/AS/1

श्री राकेश कालिया : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पढ़ा और उस पर श्री जगजीवन पाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन श्री अजय महाजन ने किया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय हर बजट सत्र के आरम्भ में यहां अभिभाषण पढ़ते हैं और सरकार की कारगुजारी को यहां सदन में रखते हैं, लेकिन हमारी विपक्ष के साथी कुछ संस्कृत के दोहों का अपने तरीके से मतलब निकालकर उनके अभिभाषण को किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के तीन साल के कार्यकाल में प्रदेश में बेहतरीन कार्य हुए हैं, सैंकड़ों स्कूल खुले हैं, कई तहसीलें खुली हैं, कई कॉलेज खुले हैं, 80 वर्ष के वृद्धों के लिए पेन्शन बढ़ाकर 1100/- रुपये कर दी गई है और हॉऊसिंग सबसिडी को आपने 75,000/-रुपये बढ़ाकर कर दिया है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए माननीय

मुख्य मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो आपने वहां एक नई तहसील दी है। मैं यह कहना चाह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारी बहुत देर से लंबित पड़ी मांग को पूरा किया है और इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी के बहुत आभारी है। पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी इन्होंने तहसील के कई वायदे किए और उस समय तहसील के नाम पर नायब-तहसीलदार तीन दिन के लिए हमारे क्षेत्र में आता था, लेकिन अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लोगों ने कई कयास लगाए और कहा कि कालिया के कहने से तहसील क्या पटवार सर्कल भी नहीं मिलता। परन्तु मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हूं। इसी तरह आपने कॉलेज की साइंस क्लासिज टेक अप की है। उसके लिए भी आपके बहुत आभारी हैं। इसका भी पहले आधा-अधूरा सरकारीकरण हुआ था। बाद में पांच साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लारोलप्पों में निकल गई। तो आपने यह भी एक कृपा की है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। कहते है कि अगर किसी भी कौम को आगे ले जाना हो, उसको शिक्षा नाम की दौलत दे दें, तो वह कभी भी पीछे नहीं रह सकती। शिक्षा के लिए आपने बहुत कुछ किया है उसके लिए आपका मैं बहुत आभारी हूं।

03/03/2016/1220/RG/AS/2

उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमारा स्वां नदी चैनेलाइजेशन का प्रोजैक्ट जानबूझ कर हमारे कुछ साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में रुकवा रखा है। मुझे बहुत दुःख से कहना पड़ता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं श्री अनुराग ठाकुर, वे हमारे माननीय सांसद हैं। वे भी इसकी वकालत कभी नहीं कर रहे हैं। एक भी बयान स्वां नदी चैनेलाइजेशन के ऊपर उन्होंने कभी नहीं दिया। यह पूर्व मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल साहब का भी क्षेत्र रहा है। ये एक-एक पंचायत को जानते हैं, तो इन्होंने भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया। जब भी कोई काम मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी करते थे, तो पहले छोटी-छोटी बात पर ये कहते थे ।

उपाध्यक्ष : धूमल साहब कुछ कहना चाहते हैं, कृपया आप बैठिए।

प्रो.प्रेम कुमार धूमल : उपाध्यक्ष महोदय, श्री राकेश कालिया जी मेरे मित्र हैं मैं इनको इन्ट्रप्ट नहीं करना चाहता था। ऊना के लोग आकर मुझे मिले थे और जो पेमेन्ट रुकी हुई है, मैंने उसके लिए माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को पत्र लिखा है और पत्र का उत्तर भी आया है। जिन संबंधित लोगों ने रिप्रेजैन्ट किया था उनको भेज भी दिया है और वह कॉपी मैं इनको भी भिजवा दूंगा।

श्री राकेश कालिया : धूमल साहब, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वे कहते हैं कि यह लव लैटर नहीं लिखने चाहिए, हमें तो असर होना चाहिए, हमें काम होने से मतलब है। वह आपका भी क्षेत्र है, हम चाहते हैं कि आप उस काम को करवाएं, न कि आप पत्र लिखें, हम पत्र देखें, प्रैस में पत्र आ जाए। इस पत्राचार से मैं समझता हूं कि हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। आपने पत्र लिखा है, तो आप वहां इसकी पैरवी कराइए और अनुराग जी को भी कहिए ताकि हमारा काम हो सके। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि यह बहुत लंबे समय से रुका हुआ है। अगर यह नहीं हो सकता, तो आप कोर्ट में चले जाएं। क्योंकि हरोली में भी लगभग यह काम पूर्ण हो चुका है, चिन्तपुरनी एवं ऊना में भी यह काम पूर्ण हो चुका है। यह सारी मार एक छोटे से विधायक के ऊपर है। मेरे क्षेत्र के ऊपर यह मार है। अब यह 200-300 करोड़ रुपये का काम रहता है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी और मैं तो यह भी कहूंगा कि मंत्री जी का काम हो गया, शायद

03/03/2016/1220/RG/AS/3

पता नहीं तब ये इन्ट्रस्ट नहीं ले रहे या धूमल साहब मुझसे ज्यादा नाराज हैं इसलिए इन्होंने दिल्ली में जाकर काम रुकवा दिया है।

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2016/1225/MS/AS/1

श्री राकेश कालिया जारी------

आप मेहरबानी करके जल्दी-से-जल्दी इस कार्य को करवाने की कृपा करें, चाहे विपक्ष

है या सत्ता पक्ष है। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हम बड़े सार्थक हैं। -(व्यवधान)- मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं हूं लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में इन्होंने रूकवा रखी है। इसलिए मेहरबानी कीजिए। अगर आप चाहे तो -(व्यवधान)- ये तो भाजपा के नेताओं ने-(व्यवधान)- मैं तो हमेशा इल्जाम लगाता हूं कि आपने रूकवाई हुई है।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वां नदी और उसके साथ बहते हुए नालों के तटबंधन का प्रश्न है, इसके लिए हिमाचल सरकार और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से बातचीत हुई। उसके पश्चात भारत सरकार ने इस परियोजना को इस अनुपात में फण्ड करने के लिए हरी झण्डी दी और एक वर्ष के अंदर वह पैसा भी आया। मगर इस वक्त क्या हो रहा है कि अभी का जो भारत सरकार का करन्ट बजट है, अभी नया बजट पास होना है। परन्तु जो पिछला बजट है उसमें स्वां नदी के लिए और नालों के तटबंधन के लिए पैसा दिया था। मगर उसकी जो मंत्री हैं वे कहीं बाहर दौरे पर गई और उन्होंने अपने सचिव को कहा कि मैं अभी फलां जगह दौरे पर गई हूं, उनको पैसा दिया जाए। सचिव ने यह नोट किया है कि यह पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए पास हुआ है। यह पैसा अन्यत्र खर्च नहीं किया सकता। बाद में कुछ ठेकेदारों ने जिन्होंने वहां पर काम किया था, उन्होंने जब मुकदमा किया, they were paid their dues. मगर जो इस काम को आगे चलाने के लिए पैसा दिया जाना चाहिए था और जो भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के बजट में प्रावधान था उसको नहीं दिया गया।

श्री राकेश कालियाः उपाध्यक्ष जी, यह पैसा इसलिए रोका है क्योंकि भाजपा के नेताओं ने उनको रोकने के लिए कहा है। आपने मुख्य मंत्री जी ठीक कहा, इसमें पूरी राजनीति हो रही है। केन्द्र के प्रोजैक्टों के पैसे कोई रोकता नहीं है।

03/03/2016/1225/MS/AG/2

मुख्य मंत्रीः यह बात गलत है। राज्य के अंदर कोई राजनीति नहीं हो रही है। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से करन्ट फाइनैंशियल ईयर का पैसा नहीं आया है। जो ठेकेदार थे उन्होंने दावा किया कि हमारा पैसा नहीं मिला इसलिए उनके बिलों की पेमैंट

हुई है। जो काम चलाने के लिए पैसा आना चाहिए था वह नहीं आया है। हालांकि उनके बजट में प्रावधान था। राजनीति दिल्ली में हुई है यहां नहीं हुई है।

श्री राकेश कालियाः मैं तो बार-बार यही कह रहा हूं कि स्वां चेनेलाइजेशन राजनीति का शिकार हुई है। पैसा यहां से नहीं बल्कि दिल्ली से रूका है। मंत्री जी बार-बार अपने अधिकारियों को कहती हैं कि यह पैसा यहां नहीं देना है बल्कि इसे मैं गंगा नदी के ऊपर खर्च करना चाहती हूं। मोदी साहब के पास नोट छापने की प्रैस है, वे और छाप लें और पैसा वहां लगा दो। गंगा के सारे घाट पक्के कर दीजिए। हम भी गंगा में जाकर नाहना चाहते हैं और अपने पाप दूर करना चाहते हैं। आप भी जाकर अपने पाप दूर कर लेना, अच्छा रहेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो आपने मुझे 20 उच्च और माध्यमिक पाठशालाएं दी हैं। कई स्कूलों में सांईस ब्लॉक भी हैं उसके लिए भी आपका आभारी हूं और लगभग 4 करोड़ रुपये विभिन्न भवनों के लिए पैसा दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लगभग 12 सड़कें हमारे क्षेत्र में बनाई जा रही हैं और पांच पुलों के ऊपर काम चल रहा है। इसी तरह से मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी दयालुता के साथ कॉलेज और तहसील का काम करवाया है। आजकल शेरों का बड़ा मौसम है तो मैं भी एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूं। यह शेर माननीय मुख्य मंत्री महोदय के लिए है।

हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है,
मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

माननीय मुख्य मंत्री जी लगातार हमारे क्षेत्र को और पूरे प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि आपने पैंशन बढ़ाई है और उसके लिए जो भाजपा सरकार के समय में मापदण्ड रखे गए थे, उनको भी बदला है। इसके

03/03/2016/1225/MS/AS/3

अलावा हाउसिंग सब्सिडी के लिए भी आपने बड़ी छूट दी है। मैं यहां विधान सभा में बड़े

लम्बे समय के बाद यह बात बोल रहा हूं । जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी उस समय मैं चिन्तपूर्णी से विधायक था। जब मैं पहली बार विधायक बना, तब मैं 11000 वोटों से जीता और दूसरी बार लगभग 16000 वोटों के मार्जन से विधायक बना। जब मैं चिन्तपूर्णी से विधायक था उस समय मेरे समर्थकों के ऊपर झूठे मुकदमें बनाए गए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------
03.03.2016/1230/जेएस/डीसी/1

श्री राकेश कालियाः-------**जारी**-------

एक इनके संघ का बहुत पुराना कार्यकर्त्ता है। सप्तदेवी बाबा के मंदिर चिन्तपूर्णी में चलाते है। उन्होंने एक विवादित जमीन खरीद ली और उसमें पिता-पुत्र का झगड़ा था। पिता जो थे वे बाबा के पास गए कि मैं जमीन पुत्र को नहीं देना चाहता हूं आपको बेचना चाहता हूं, लेकिन पुत्र का कब्जा था वह छोड़ नहीं रहा था और बाबा ने वह डिस्प्युटिड जमीन खरीद ली। जब वह कब्जा लेने गया तो वहां पर पिता-पुत्र का विवाद हो गया। गांव का प्रधान वहां पर गया वह कांग्रेस पार्टी से संबंधित था। मुख्य मंत्री जी मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जो पिता-पुत्र का झगड़ा था और जमीन खरीद ली भाजपा के एक संत ने जो कि आर0एस0एस0 के हैं। जब कब्जा लेने गए तो पुत्र ने उन्हें जमीन में आने नहीं दिया। हमारे वहां पर प्रधान थे कुरलई के कुलदीप शर्मा जी, उन्होंने भी रोका कि जो आपकी लड़ाई है, विवाद है आप इसे कहीं कोर्ट में निपटाओ या लड़ो। वह झगड़ा बढ़ते-बढ़ते बढ़ गया और बाबा और उनमें थोड़ी-बहुत मारपीट हो गई, कहासुनी हो गई। बाद में कॉम्प्रमाईज लिखने बैठे तो एक वकील बुला लिया। एक-दो समर्थक और आ गए। जो वकील थे वह कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी थे। कॉम्प्रमाईज हो रहा था और जब कचैहरी में कॉम्प्रमाईज होता है तो जो हमारे चेयरमैंन बी0डी0सी0 के थे वह भी वहां पर शामिल हो गए। ठीक है, उसकी थोड़ी पिटाई हुई है, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर 307 का मुकद्मा बनाया गया। एक मास्टर नेक मुहम्मद माइन्योरिटी से थे उनके ऊपर तो धार्मिक भावना भड़काने का मुकद्दमा बनाया गया और 307 धारा लगाई गई। बाबा जी अस्पताल में लम्बे पड़ गए। दिल्ली से और नागपुर से फोन आए कि जो हमारे कांग्रेसी है, जिनमें एक कांग्रेसी प्रधान है, हमारा जनरल

सेक्रेटरी, श्री राकेश चौधरी और प्रधान के पिता जी, उन लोगों के ऊपर झूठे मुकद्दमें बनाए गए। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अब इन केसिज को वापिस लो। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटिड है। यह 324 का मुकद्दमा नहीं बनता था। जो इन्होंने 307

03.03.2016/1230/जेएस/डीसी/2

धारा लगाई और देशद्रोह का मुकद्दमा बनाया। वह मास्टर रिटायर्ड थे और पुरी उम्र उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेवा की है। उनके ऊपर भी केस बना दिया। इसी तरह से मैं धूमल साहब के ऊपर भी एक शेर सुनाना चाहता हूं।

दिलो में खुन्दक,चेहरों पर मुस्कान रखते हैं,

वे नज़रों में छुपाकर तीर कमान रखते हैं,

मौका मिलते ही खंजर से वार करते हैं,

गज़ब है, फिर भी मिठी ज़बान रखते हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने भी यह आश्वासन दिया था कि केस ऐसे नहीं बनेंगे लेकिन आप कर नहीं पाए परन्तु पता नहीं आपकी क्या मज़बूरियां रही होंगी। धूमल जी, मंत्री नहीं बनना है। मैंने स्टेट मिनिस्टर के पद से रिजाईन किया है। आप माननीय मुख्य मंत्री जी को पूछो कि मैं कभी इनके पास गया कि सर, मुझे मंत्री बना दो। मैंने रिजाईन किया और अपनी मर्ज़ी से सी0पी0एस0 की पोस्ट से रिजाईन किया। मुझे नहीं बनना मैंने तो कभी बोला ही नहीं। माननीय धूमल जी आप मेरी प्रार्थना सुनो जो मैं बोल रहा हूं। एक और बात सुना रहा हूं। मैं दो बार एम0एल0ए0 बना और दोनों बार ही हाईएस्ट मार्जन से जिता। लोयर बैल्ट में ऐसा कोई कांग्रेस का एम0एल0ए0 नहीं है जितने बड़े मार्जन से मैं जिता हूं। दूसरी बार जब मैं बना तो चुनाव में हल्की से कहासुनी एक थानेदार के साथ हो गई। उस समय कोई केस दर्ज़ नहीं हुआ। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी और शिमला से फोन आए कि राकेश कालिया के ऊपर केस बनाओ।

एस0पी0 को फोन गया। थानेदार ने मेरे ऊपर केस बनाया। 186 का केस बनाया। 186 क्या होता है डियुटि रोकने के लिए होता है। वह केस बना। मैंने किसी को नहीं बताया और न ही मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह जी को बताया और न ही किसी और के पास गया। मैंने चुपचाप अपनी ज़मानत करवा ली। इन्होंने उसे एवार्ड देने के लिए, होता यह है कि जो कांग्रेस ने ऑफिसर्ज लगाए होते हैं उनको बी0जे0पी0 नहीं लगाती। वह अम्ब का एस0एच0ओ0 था ईनाम देने के

03.03.2016/1230/जेएस/डीसी/3

लिए गगरेट का एस0एच0ओ0 लगाया और वह रिटायर भी वहीं से हुआ। जो एस0पी0 ऊना का उस समय का था उसको भी एवार्ड देने के लिए इन्होंने उसे एस0पी0 कांगड़ा लगाया। इस तरह की मेहरबानियां ये हमारे साथ करते रहे हैं। अब इनको लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। मुख्य मंत्री महोदय के ऊपर भी ये केसिज बनाते हैं। आपको ये चाहिए कि जब आपकी सरकार होती है अगर आप भी अपने साथ वैसा व्यवहार चाहते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही करिये। हम भी यहां पर चुने हुए विधायक हैं। मेरा एक एक्सीडैंट हो गया 6-7 महीने के बाद तो मेरे ड्राईवर के ऊपर और मेरे ऊपर एक और मुकद्दमा बना दिया। आपके लोकल लीडर करते होंगे आप नहीं करते होंगे। वहां पर इस तरह का माहौल हमेशा बनाया जाता रहा है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार के समय हमारे ऊपर ज्यादतियां होती रही हैं। अब तो केन्द्र में इनकी सरकार है और अच्छे दिन आने वाले थे। सब लोग कह रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। प्रधान मंत्री जी एक सिर के बदले दस सिर लाने वाले थे, लेकिन उनके बर्थडे केक काटने के लिए रास्ते में इस्लामाबाद में ही उतर गए। सुषमा स्वराज जी बड़ा तीखा भाषण देती थी। हमारे नेताओं के ऊपर ऐसी टूटती थी जैसे वह दुर्गा माता का अवतार है। अब जा करके वहां केंडल नाईट डिनर और हमने तो अब सुना कि केंडल नाईट डिनर भी होता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

03.03.2016/1235/SS-DC/1

श्री राकेश कालिया क्रमागतः

ये हिन्दुत्व की बात करने वाले कैंडल लाइट डीनर करने जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप कामों में रोका-टोकी करने के बजाय प्रदेश व देश के विकास के ऊपर ध्यान दें। देश में बहुत-सी ऐसी बातें हो रही हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। मैं उन पर बोलना नहीं चाहूंगा। हरियाणा में क्या हुआ? वहां आपकी सरकार है। देश में क्या हो रहा है? उसे आप भलीभांति जानते हैं। मुख्य मंत्री महोदय आप बेहतरीन काम करे हैं। यह पहली बार होगा और मेरा ब्रह्म वाक्य है कि यहां कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी और आपको (विपक्ष) केन्द्र की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुख्य मंत्री महोदय, बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और सीमित साधनों में चला रहे हैं। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

अंत में मैं यहां पर जगजीवन पाल जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव लाए हैं उसका दिल की गहराईयों से समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

समाप्त

03.03.2016/1235/SS-DC/2

उपाध्यक्षः अब श्री महेन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 25 फरवरी, 2016 को जो अभिभाषण इस माननीय सदन के बीच में पढ़ा है उस पर हो रही चर्चा में मैं अपने आपको शामिल करने जा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजह है, क्या कारण है कि अभिभाषण में जो सारी बातें शामिल होनी चाहिए थीं वे नहीं हैं। लेकिन बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो इस अभिभाषण के अंदर विभिन्न विभागों के दर्शाये गये हैं वे सरासर गलत हैं। बहुत-सी ऐसी बातें हैं। आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे ही 2012 में सत्ता सम्भाली थी तो इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरैंस की बात कही थी। हम इस अभिभाषण के अंदर उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरैंस के ऊपर सवा तीन वर्ष का कार्यकाल वर्तमान सरकार का बीत रहा है लेकिन

उसमें कितने मामले कहां-कहां, किन-किन विभागों और मंत्रियों के खिलाफ आज तक उजागर हुए हैं। विपक्ष ने उजागर किये हैं, हमारे प्रैस के बंधुओं ने किये हैं, प्रदेश के विभिन्न लोगों ने आगे उजागर किये हैं उनके ऊपर हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखी है। न इसके ऊपर अभिभाषण में कहीं लिखा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी पीछे प्लानिंग की बैठक हुई थी। मैंने उसमें एक बात कही थी कि मौसम का मिजाज़ बदला है। मौसम के मिजाज़ बदलने के साथ-साथ विशेष करके सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को कमर कसनी पड़ेगी। अभी तो मार्च का महीना शुरू हुआ है और भयंकर गर्मी हमारे सामने है। भयंकर सूखा चला हुआ है। उसकी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर पीने के पानी की एक गम्भीर समस्या पैदा हो सकती है और वह समस्या वर्तमान में पैदा हो भी चुकी ही है। उस समस्या की वजह से आज जितने भी हमारे पेयजल योजनाओं पर फिल्टर बैड बनने चाहिए थे वे नहीं बनें। जहां पर फिल्टर बैड बने हुए हैं वे काम नहीं कर रहे हैं। जो सीवरेज की स्कीमें या एस0टी0पीज़0 बने हुए हैं वे ऑवर लोडिड हैं। उनसे सीवरेज वैसे ही बह रहा है। जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर शिमला से लेकर सोलन और पूरे मंडी जिला में पीलिया फैला हुआ है। वह एक महामारी का रूप धारण करने जा रहा है। माननीय मंत्री जी, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र के अंदर भी जो पीने के पानी की स्कीमें हैं उसमें आपने बहुत स्कीमों पर ठेकेदारों को ठेके कर दिए है।

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2016/1240/केस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी-----

जिन ठेकेदारों को ठेके दिए गए हैं वे कहते हैं कि हमने तो एक साल में इतना पैसा लेना है। हम पानी दें, न दें। हम मशीनों की मेंटिनैंस करें, राईज़िग मेन की मेंटिनैंस करें या उन स्टोरेज टैंकों तक पानी पहुंचाए या न पहुंचाए, यह हमारा सिरदर्द नहीं है, हमारा तो सिर्फ इतना है कि हमने एक वर्ष का जितना अमाऊंट लेना है, वह हमें मिलेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदया का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं

कि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के अंदर उठाऊ पेयजल योजना नगैणी-खेड़ी, नौणु-तनियार, रियूर-डिडणू-ध्वाणी-काँढा पतन-धवाली, अवाह देवी, सज्याओपिपलू, टौर-खोला ये स्कीमें तो ऐसी हैं कि इनमें 15 से लेकर 45 दिनों के बीच में सिर्फ एक बार पानी मिलता है। जो आई.पी.एच. विभाग के अंदर पीने के पानी के लिए पाइपें खरीदी जा रही है, मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदया जी से विशेष आग्रह रहेगा कि जो जी.आई. पाईप लिए जा रहे हैं, वे इतने घटिया किस्म के हैं कि जहां पर उनमें बैंड डालते हैं उस जगह वे एकदम टूट जाते हैं। तो जो-जो पाइपें खरीदी जा रही हैं, उस पर भी कौन उनको खरीदता है, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन खरीदती है या आई.पी.एच. विभाग खरीदता है, वह हमें नहीं मालूम लेकिन हम इतना जरूर आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि जो खरीद पाइपों की हो रही है उसमें दाल में काला-काला बहुत दिखाई दे रहा है और उसकी वक्त रहते छानबीन कर लें क्योंकि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टोलरैंस की बात कही है।

उपाध्यक्ष जी, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी के पास होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट भी है और इस विभाग में बड़ी अनोखी सी बात देखने को मिली है कि वर्ष 2013-14 में आपने प्राईवेट नर्सरियों से, ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, विधान सभा के अंदर विधायकों ने जो प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब में आपने कहा है कि वर्ष 2013-14 में आपने सेब के और दूसरी प्रजातियों के 13,73,268 पौधे खरीदे और वर्ष 2014-15 में 16,84,146 पौधे खरीदे। उपाध्यक्ष जी, आप स्वयं बागवान है, मुख्य मंत्री जी भी और उद्यान मंत्री जी भी बागवान है और छोटा-मोटा बागवान मैं भी हूं। एक बीघा के अंदर पहले तो 25 प्लांट लगते थे लेकिन

03.03.2016/1240/केस/एजी/2

अब क्योंकि ड्वार्फ वैरायटीज़ आई है इसलिए 40 प्लांट लग सकते हैं । मैंने जो कैल्कुलेशन की है कि अगर 40 प्लांट्स भी एक बीघा में लगते हैं तो दोनों वर्षों को मिलाकर आपने 30,57,414 पौधे प्राईवेट नर्सरियों से खरीदे हैं। इन पौधों को लगाने के

लिए 10 लाख 20 हजार बीघा जमीन की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ये पौधे वाकई में प्राईवेट नर्सरियों में पैदा किए गए हैं और उनसे क्रय किए गए हैं? और फिर क्रय करने के बाद अगर इनकी प्लांटेशन हुई है तो कहां हुई है? मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी जगह है कि इतनी प्लांटेशन दोबारा से की जा सकती है। तो यह हमारा इस सम्बन्ध में आपके ऊपर आरोप है । पिछले साल आपने कहा था कि एप्पल बॉक्सिज़ की जो पैकिंग है, उसमें गत्ते की जो हमारी पेटी है, उसमें हम 16-17 या 18 किलो से ज्यादा सेब भरने की अनुमति नहीं देंगें लेकिन वह घोषणा ही रह गई उस घोषणा पर आगे कोई अमल नहीं हुआ, इस पर भी चिन्ता करने की आवश्यकता है।

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरा माननीय उद्यान मंत्री जी से एक और निवेदन रहेगा कि एच.पी.एम.सी. और हिमफैड है, वहां जो हमारे बागवान इस प्रदेश के हैं उनकी लायबिलिटी 2014 की 60 लाख 41 हजार रुपये देने को है एच.पी.एम.सी. की और 2015 की 1549.72 लाख रुपया अभी आपको लायबिलिटी देने के लिए है। वर्ष 2016-17 अब शुरू हो चुका है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.3.2016/1245/av/ag/1

श्री महेन्द्र सिंह --जारी

तथा अगला सेब का सीजन आने वाला है। इसलिए मैं आपको इस बात से आगाह करना चाहता हूं कि यह सारी-की-सारी पेमैंट आप कब करेंगे? पेड़ों के कटान की बात चली हुई थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिन्होंने ऐनक्रोचमैंट करके अपने मकान या गौशाला बनाई हुई है उनके बिजली/पानी के कनैक्शन काटे जा रहे हैं। हमने कहा था कि केवलमात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सम्बंधित मकानों के ही

बिजली/पानी के कनैक्शन काटे जा रहे हैं। उस पर आपने कहा था कि मुझे वह लैटर देना। मैं आपको यह लैटर दे रहा हूं और सारी कार्रवाई को इस सदन के पटल पर रखने जा रहा हूं। इसमें मैं मार्क कर रहा हूं कि इन सीरियल नम्बर में यानि बीच-बीच में बिजली और पानी के कनैक्शन काटे गये हैं और उसमें एक जैसी पारदर्शिता नहीं अपनाई गई है।

मण्डी जिला एक बहुत बड़ा जिला है और कांगड़ा जिला के उपरांत यह दूसरे नम्बर पर आता है। दूसरा जिला होने के नाते हमारे इस जिले से तीन मंत्री सम्बंद्ध रखते हैं। आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी एक बड़े प्रभावशाली मंत्री है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि श्रद्धेय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश जैसे एक छोटे राज्य को एम्ज जैसा संस्थान दिया है। उसके लिए जिला बिलासपुर में जगह भी चिन्हित कर दी गई है। आज तक जमीन का हस्तांतरण उस संस्थान के नाम क्यों नहीं हो रहा है? इसके लिए अगर आप कह रहे हैं कि हो चुका है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। यदि नहीं हुआ है तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसको जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी करने की आवश्यकता है। दूसरा, ई.एस.आई. मैडिकल कॉलेज के बारे में पिछले कल इस हाउस के अंदर एक बड़ी लम्बी चर्चा हुई और मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहता। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नेरचौक मैडिकल कॉलेज और अस्पताल को जैसे-कैसे चालू करो। यह प्रदेश सरकार का

3.3.2016/1245/av/ag/2

दायित्व है। आपने पिछले कल कहा है कि हम वहां अगस्त के महीने में क्लासिज चालू करेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अभी वहां बिल्डिंग का पोर्शन अधूरा है। उसमें अभी बहुत ज्यादा काम शेष रहता है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस ओर विशेष ध्यान दे। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने निजी कॉलेज चलाने की अनुमति प्रदान की है। जब आपने उसको चलाने की अनुमति

दी तो उसमें हमें एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपने उसमें हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा क्यों नहीं की है? इस बारे में विधान सभा के अंदर एक प्रश्न लगा है। इस प्रश्न में यह लिखा है कि केवल एक निजी मैडिकल कॉलेज खुला है। इसमें आपने 50ः 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया है। फीस स्ट्रक्चर का तुलनात्मक विवरण भी दिया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जिसने स्टेट कोटा से ऐडमिशन लेनी है उसे 5 लाख रुपये प्रति वर्ष विकास शुल्क देना पड़ेगा जबकि पंजाब में दो लाख रुपये हैं और हरियाण में इससे थोड़ा ज्यादा है। आई.आर.डी.पी. के व्यक्ति को 30 हजार रुपये देने होंगे। मेनेजमैंट कोटे में मु0 9 लाख रुपये प्लस 5 प्रतिशत शुल्क देना पड़ेगा। पंजाब में जब 6 लाख रुपये प्लस शुल्क कोई नहीं है तो हिमाचल प्रदेश के जिन बच्चों ने इस संस्थान के अंदर ऐडमिशन लेनी है उनको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करके 5 लाख रुपये की राशि को कम करो। दूसरा, आपने आई.जी.एम.सी. में एस.आर.एल. लैब को किसी प्राइवेट कम्पनी को दे दिया।

टीसी द्वारा जारी

03.03.2016/1250/TCV/AS/1

श्री महेन्द्र सिंह----- जारी
आपने उसके 'ग' भाग में लिखा है कि बी0पी0एल0,आई0आर0डी0पी0 और कैंसर जैसे रोगियों का मुफ्त परीक्षण इस लैब में किया जाता है। इसके लिए आपको बधाई। लेकिन जो रेट्स वहां पर लिए जा रहे हैं, उसके लिए भी हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करें। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी यहां पर नहीं है। मैं उनसे कुछ बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय हर हफ्ते एक नई स्टेट्मैंट डाल देते हैं कि इस हफ्ते आपको फ्लांनी दाल दी जाएगी। इस महीने आपको गंदम नहीं दी जाएगी, आटा दिया जाएगा और इस महीने शुगर आपको फ्लां मार्किट की दी जाएगी। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है।

माननीय मंत्री महोदय ने जब इस विभाग का चार्ज़ लिया था, उस समय 2012 में प्रदेश की जनसंख्या 68 लाख थी। आज इस प्रदेश के अन्दर जो राशन कार्ड बने हैं, उन राशन कार्डों के माध्यम से 77 लाख लोगों को राशन बांटा जा रहा है। यह माननीय मंत्री महोदय ने हाऊस के अन्दर स्टेट्मेंट दी है। वह स्टेट्मेंट दिसम्बर, 2013 की है। लेकिन 2013 के बाद आज 2016 हो गया है और उस वक्त के राशन कार्डों और आज के राशन कार्डों में एक लाख राशन कार्डों का और इज़ाफा किया गया है। इसका मतलब है 80 लाख लोगों को हिमाचल के अन्दर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राशन बांट रहा है। वे कौन ऐसे लोग हैं और कौन-से ऐसे जाली राशन कार्ड है, जिनको राशन दिया जा रहा है? आज पूरे प्रदेश के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है। दाल की जगह दाल नहीं मिल रही है। आटे की जगह आटा नहीं मिल रहा है। आप पूरे प्रदेश के अन्दर गंदम क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर गंदम दी जाती है। हमारे प्रदेश के लोग उस गंदम को साफ करेंगे और साफ करने के बाद हिमाचल प्रदेश के अन्दर जो छोटी-छोटी चक्कियां है उसमें वे उस गंदम को पिसाएंगे। जिससे हमारा गांव में बैठा हुआ छोटा-मोटा कारोबार करने वाले व्यक्ति को आमदन हो जाएगी। लेकिन बड़ी-बड़ी फ्लोर मीलों के साथ इनकी सैटिंग हुई होगी। ऐसा हम महसूस करते हैं। यह हमारा वर्तमान सरकार के ऊपर चार्ज़ है कि इस परम्परा को बन्द करो । इसके साथ

03.03.2016/1250/TCV/AS/2

जो चीनी ली जा ही है वह चीनी शुगर मीलों से क्यों नहीं ली जा रही है? जो चीनी ली जा रही है वह भी कुछेक व्यापारियों से ली जा रही है और वह भी 2.50 रूपये प्रति किलो के हिसाब से ली जा रही है। ये भी हमारा वर्तमान सरकार/मंत्री के ऊपर चार्ज़ है। आप बड़ी-बड़ी मील वालों को एक क्विंटल में बीस किलो की उड़ान माफ कर रहे हैं। आप हमारे हिमाचल प्रदेश के जो छोटी चक्की वाले हैं उनको 20 किलो माफ कर देगें तो ज्यादा बेहतर होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी हम एक बात जरूर बताना चाहते हैं कि एच0आर0टी0सी0 के अन्दर जो नीली बसें जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के तहत ली गई है, उन बसों के ऊपर जो मटीरियल लगाया है, वह घटिया मटीरियल है। यह हमारा आपके ऊपर आरोप है। धर्मपुर में आज जो पांच बसें खड़ी है, उनमें बहार से जो गत्ता लगा हुआ है, वह इतना घटिया किस्म का है कि यदि आप उसमें जोर से मुक्का मारोगे

तो वह गत्ता टूट जाएगा। हमारे टाईम में एक बस बॉडी फैब्रीकेशन के साथ 18-19 लाख में पड़ती थी। लेकिन ये बसें 38-39 लाख रूपये में ली जा रही है। आपने वॉल्वों बसें खरीदी है। मैं एक दिन दिल्ली से आ रहा था। लेकिन उसमें फुट-रेस्ट तक नहीं था। माननीय मंत्री जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी धर्मपुर में गये और वहां पर घोषण कर दी कि आपके बस स्टैंड के लिए मैं एक करोड़ रूपया दे रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वह एक करोड़ कहां गया?

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

3.03.2016/1255/RKS/AS/1
श्री महेन्द्र सिंह क्रमागत...

क्या वह 1 करोड़ रुपया वहां पर पहुंचा है? अगर नहीं पहुंचा है तो आपने झूठी घोषणा वहां पर क्यों की? वह एक करोड़ रुपया कहां गया? यहां पर बिजली विभाग के मंत्री महोदय बैठे हैं, आप बहुत शरीफ हैं। इस बात के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। लेकिन जो विभाग आपके पास है, वह बहुत बड़ा विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है। आदरणीय धूमल साहिब ने यहां पर एक बात रखी थी कि जो आपके विभाग ने सामान क्रय किया था वह 331 करोड़ रुपये का सामान दो वर्षों में क्रय किया गया था। उसमें से अगर हम प्रति महीना निकालें तो 14 करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया है। भावा में भी घटना घटी है। वहां पर 2 करोड़ का सामान वर्ष 2013-14 में खरीदा गया। माननीय मंत्री जी आज ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बिजली विभाग की है। कहीं ट्रांसफार्मर लग रहा है तो वह तीन दिन के अंदर खराब हो जाता है। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जैस बारिश होती है और पताशा गल जाता है। पताशा के ऊपर जब बारिश की बूंद पड़ती है तो पताशा गल जाता है। वैसे ही आपकी डिस्कें फट जाती हैं। जो आपने मीटर खरीदे उसके लिए भारत सरकार से पैसा आया। भारत सरकार के पैसे से आपने मीटर खरीदे। आपने सर्विस वायर बदली। लेकिन जो लाखों मीटर पहले लगे थे, क्या वे फॉल्टी थे? अगर वे मीटर गलत थे तो आपको उनकी इन्क्वायरी करनी

चाहिए थी। अगर गलत नहीं थे तो नए मीटर लगाने की क्या आवश्यकता थी? आपने कहा कि नए मीटर लगाने से बिजली की सही रिडिंग आएगी। हम आपके ध्यान में ला रहे हैं कि जो नए मीटर लगाए गए हैं, उनमें से बहुत से मीटर खराब निकले हैं। जो नए मीटर लगाए गए हैं उनकी बिजली की रिडिंग 30-35 प्रतिशत ज्यादा आती है। अब हम पुराने मीटरों को ठीक मानें की नए मीटरों को ठीक मानें। अब आपने लाखों पुराने मीटर निकाले। जब आपके नए मीटर लगे तो पुराने मीटर निकाल दिए गए। वे कहां हैं? किन स्टोरों में रखे हुए हैं? क्या आपने उन मीटरों की ओक्सन की? क्या उनको नई जगह लगा रहे हैं? यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह आपके विभाग के ऊपर है। मैं इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन इसमें कोई न कोई तो दोषी है कि वे पुराने मीटर कहां चले

3.03.2016/1255/RKS/AS/2

गए? जो आज से 30 साल पहले सर्विस वायर लगी थी वह ठीक वर्किंग ऑर्डर पर थी। जो सर्विस वायर आपने नई लगाई है, जब उनके गुच्छों को सीधा करते हैं तो वह टूट जाती है। इस तरह की वायर हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ता को लगानी पड़ रही है। इन मीटरों व सर्विस वायर खरीदने के लिए श्याम इंडस कंपनी को 6 टैंडर दे दिए गए। हाईटैक पावर कंपनी को 5 टैंडर दे दिए गए। इसके अतिरिक्त 3 काम एक-एक कंपनी को दिए हैं। माननीय मंत्री जी एक बहुत ही संवेदनशील मामला आदरणीय धूमल जी ने प्रदेश सरकार के सामने लाया और हम भी इस मामले को आपके सामने ला रहे हैं। आप इसकी पूरी छानबीन करें। छानबीन करने के उपरांत जो दोषी हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह हमारा आपसे अनुरोध है। (घण्टी) वन मंत्री महोदय आपने वर्ष 2011 में प्रदेश में 5, 59,51,079 पौध लगाए हैं। यह पौधे कहां लगाए गए हैं? मेरे ख्याल से ये सारे पौधे आपने पूरे प्रदेश के अंदर लाए हैं। आज अगर सबसे बड़ा स्कैंडल इस प्रदेश के अंदर है, वह कोई आपके समय का ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह आपके समय का है। हिमाचल प्रदेश की वन भूमि में आज तक जितनी भी

प्लांटेशन की गई, अगर उस सारी प्लांटेशेन को हम जोड़ें तो ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा ट्राइबल है और जहां पर वैजिटेशन है ही नहीं,

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

03.03.2016/1300/SLS-DC-1

श्री महेन्द्र सिंह ....जारी

उस वैजिटेशन न होने वाली जगह पर भी हर ईंच पर पौधा लगाया हुआ है। क्या कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हम जो प्लांटेशन कर रहे हैं, इसका सरवाईवल रेट क्या है? मेरा आपसे अनुरोध है और साथ में आरोप भी है कि जो यह प्लांटेशन हो रही है इसको वैरिफाई करिए कि जहां-जहां प्लांटेशन हुई है वह ठीक है या नहीं।

पिछले कल ही बंदरों की बात आई थी। उनकी नशबंदी के जो आंकड़े आपने दिए हैं वह आपके ही आंकड़े हैं, हमने उसमें कोई नई बात नहीं जोड़ी है। ऐसा नहीं है कि हमने घर से आंकड़े लिए हैं या ये कोई संभावित आंकड़े हैं। यह सारे आंकड़े विधान सभा पटल पर रखे गए प्रश्नों पर या हाऊस कमेटीज मीटिंग्ज में दी गई सूचना पर आधारित हैं। माननीय मंत्री जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आपने बंदर पकड़े। ऊना में एक पीताम्बर दत्त शर्मा है, उसको आपने बंदर पकड़ने का 28,70,800 रुपया दे दिया। एक राजेन्द्र सिंह जो ऊना से है, उसका पता नहीं दिया है कि उसका गांव, डाकखाना क्या है। आपने उसको 22,96,640 रुपये दे दिए। उद्धम सिंह है उसको आपने 6,45,930 रुपये दे दिए। रामदेव को 8,61,240 रुपये दे दिए। गगन सिंह को आपने 5,02,390 रुपये दे दिए। मैं केवल बड़े-बड़े नाम पढ़ रहा हैं। उद्धम सिंह को आपने दोबारा 7,98,000 रुपये दे दिए। एक सुरेन्द्र कुमार है जिसका केवल नाम दिया है। उसको 13,77,305 रुपये दे दिए। इनमें से किसी के भी पते नहीं दिए गए हैं। हम कहना चाहते हैं कि मंकीज स्टरलाईजेशन के लिए जो काम हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हमारे सामने आया है। प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि किस काम के लिए कितने पैसे

दिए गए? यह पैसे तो पकड़ने वालों के लिए हैं। आपने कहा कि 52,404 बंदरों का स्टरलाईजेशन हुआ है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में 1,02,000 से भी ज्यादा स्टरलाईजेशन केसिज आपने दर्शाए हैं। हम आपको सही माने या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को

03.03.2016/1300/SLS-DC-2

ठीक माने? जिन बंदरों को पकड़ कर स्टरलाईजेशन स्टेशन पर ले गए और वहां से वापिस लाया, वह एक और स्कैंडल हो सकता है। या तो इसमें आपको देनदारी देने को है या इसमें स्कैंडलाईज करके कुछ है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री इस सारे स्कैंडल की छानबीन करें क्योंकि उन्होंने जीरो टौलरैंस की बात कही है।

मिड हिमालयन प्रोजैक्ट भी इस प्रदेश के लिए एक कैंकर जैसा रोग है। हम नहीं जानते कि जो-जो पंचायतें इस मिड हिमालयन प्रोजैक्ट के अंतर्गत आई हैं, वहां पर क्या काम हो रहा है। मैं ऐसा देखता हूं कि वहां पर मात्र इस योजना को डकारने का काम चला हुआ है। स्वां जलागम परियोजना में 11 करोड़ रुपये पौधरोपण के पर 1200 हैक्टेयर ज़मीन के ऊपर ख़र्च किए गए हैं। वहां पर लगाए गए पौधों की संख्या 8,11,50,454 है और 2,73,38,355 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 11 करोड़ से 12 करोड़ पौधे वहां पर लगाए गए हैं। ...(व्यवधान)... यह एक प्रश्न का उत्तर है। मैंने यह घर से नहीं लाया है। आप वन विभाग के मंत्री हैं। ...(व्यवधान)...क्या 12 करोड़ पौधे स्वां चैनेलाईजेशन के किनारे लगने की गुंजाईश है? अगर इतनी गुंजाईश नहीं है तो फिर यह पौधे कहां और कैसे रोपे गए? इतना बड़ा स्कैंडल किसके कहने पर हुआ है? यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

Deputy Speaker: Please windup.

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। पीछे भारी बरसात हुई है और उससे जो नुकसान हुआ है वह पूरे प्रदेश के अंदर हुआ

है। इस नुकसान से सड़कों की हालत खराब हुई है। मेरे क्षेत्र में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि बसों के 30 रूट्स बंद कर दिए गए हैं।

जारी ...गर्ग जी

03/03/2016/1305/RG/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह-----क्रमागत

मेरे क्षेत्र में जो वर्ष 2013, वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए, यदि सड़कों के लिए पैसे दिए होंगे, तो सड़कों के लिए कितने पैसे दिए, ज्यादा-से-ज्यादा दो करोड़ रुपये दिए। लेकिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, जिनके मकान, गौशाला, पशुधन, जमीनें और जिनके मकान खतरे में हैं उनके लिए जो पैसा मिलना चाहिए था, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है।

Deputy Speaker : Please, windup now.

श्री महेन्द्र सिंह : इसलिए हमारा आपके ऊपर आरोप है कि इन प्रदेश में इन सड़कों की हालत जितनी जल्दी हो सके, उसको ठीक करने की कोशिश करें। उपाध्यक्ष जी, आपके आदेशों की पालना की जाएगी। आप इस चेयर पर सुशोभित हैं, आपसे कोई गिला-शिकवा नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं, अच्छा होता यदि इन्होंने इस अभिभाषण में जो दस नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग श्रद्धेय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने, एन.डी.ए. की सरकार ने सौगात के रूप में दिए हैं, उनको आप इसमें दर्शाते, अच्छा होता कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग के लिए जो आपको दस गुणा ज्यादा धनराशि मिली है, आप उसको इसमें दर्शाते, आप ऐम्स जैसी सौगात को इसमें दर्शाते। आप भूल गए कि स्मार्ट सिटी हिमाचल प्रदेश को मिला है। आप उस स्मार्ट सिटी की बात भी अगर इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दर्शाते, तो अच्छा होता।

उपाध्यक्ष : कृपया अब आप समाप्त करिए।

श्री महेन्द्र सिंह : आप यह भूल गए कि चंबा, नाहन और हमीरपुर में मैडिकल कॉलेज के लिए पैसा भारत सरकार ने दिया है, आप उसको भूल गए और दो महत्वपूर्ण फोरलेनिंग का काम जो इस प्रदेश में चला हुआ है। उन सड़कों के लिए जो फण्डिंग

एन.एच.ए.आई. के माध्यम से आ रही है, भारत सरकार की तरफ से आ रही है--(घण्टी)--उसको आप भूल गए। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है।

मुख्य मंत्री : ऐसा है कि आप गलतफहमी में मत रहो। मैडिकल कॉलेज, चंबा, मैडिकल कॉलेज, हमीरपुर और मैडिकल कॉलेज नाहन के लिए जो पैसा आया है, वही आया है जो कांग्रेस सरकार के समय में आया है। अभी तक इसके अतिरिक्त नहीं आया। उम्मीद करेंगे कि आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया।

03/03/2016/1305/RG/DC/2

श्री महेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे भाई श्री महाजन जी ने कहा कि हमें नूरपुर के लिए 37,42,59,000/-रुपये मिला हुआ है। यह भारत सरकार का पैसा है, नरेन्द्र भाई मोदी जी का पैसा है, सी.आर.एफ. का पैसा है, इन्टरस्टेट कनैक्टिविटी का पैसा है।

मुख्य मंत्री : यह मोदी जी का नहीं, भारत की जनता का पैसा है।

श्री महेन्द्र सिंह : इसको आप भूल गए, भारत सरकार ने जो पैसा दिया, आप उसके लिए मोदी सरकार का धन्यवाद करना भूल गए, एन.डी.ए. की सरकार का धन्यवाद करना आप भूल गए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करिए। आप बहुत बोल चुके है, आप तीस मिनट बोल चुके हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष जी, एक मिनट। यहां पर श्री धनीराम शांडिल जी, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं इनके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। तहसील वैलफेयर ऑफिसर, सरकाघाट के ऑफिस में जो पहले तहसील वैलफेयर ऑफिसर वहां था, उसने जो सामाजिक सुरक्षा पेन्शन के केसिज वहां आए, उन सामाजिक सुरक्षा पेन्शन एवं अन्य केसिज को रद्दी में फेंका हुआ था। जो नया तहसील वैलफेयर ऑफिसर आया, उसने मुझे सूचना दी कि तीन बोरियां पुराने पेन्शन केसिज की वहां पड़ी हुई हैं। मैं उनको ठीक करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करें,ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए जो गरीबों के साथ इस प्रकार का अन्याय करते हैं। जो कंपेशनेट ग्रॉउन्ड के केसिज़ हिमाचल प्रदेश सरकार के पास लंबित हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि आप उनको करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन की एक बहुत बड़ी फौज आपने प्रदेश में खड़ी की हुई है, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। जब वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस बड़ी फौज को खड़ा करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे नुकसान-ही-नुकसान होने वाला है। मित्रों आपको मेरी बातें कड़वी लगी होंगी। अगर मैंने गलत बोला होगा, तो माफी चाहूंगा। मेरे आंकड़े जो हैं, मैं उनको चेलेन्ज करके कह रहा हूं कि कोई मंत्री या कोई विभाग मेरे आंकड़ों को अगर चेलेन्ज कर दे।

उपाध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करिए। अब कोई रिकॉर्ड नहीं होगा।

03/03/2016/1305/RG/DC/3

श्री महेन्द्र सिंह : तो शर्त है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपके पास थोड़ा सा समय बाकी बचा हुआ है। अगर थोड़े से समय में आपने अपने आपको सुधार लिया, तो शायद थोड़ा-बहुत सुधार हो जाएगा। अन्यथा आने वाला समय आपके लिए बहुत अन्धकारमय होगा। तो उस अंधेरे से बचने के लिए आप कोशिश करो। सही रास्ते पर आ जाओ और सही रास्ते पर आकर आप काम करो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

एम.एस. द्वारा उपाध्यक्ष शुरू

03/03/2016/1310/MS/AS/1

उपाध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

03.03.2016/1405/जेएस/एजी/1

(सदन **बैठक भोजनोपरान्त**, माननीय **उपाध्यक्ष, श्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में अपराह्न 2.05 बजे पुनः आरम्भ हुई**)

उपाध्यक्षः अब श्री राजेश धर्मणी जी, मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेश धर्माणीः (मुख्य संसदीय सचिव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2016 को जो माननीय राज्यपाल महोदय ने इस माननीय सदन को सम्बोधित किया और उनके अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे साथियों ने यहां से प्रस्तुत किया है उस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

उन्होंने एक श्लोक से अपने अभिभाषण की शुरूआत की थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने जो प्रेरित करने की कोशिश की थी कि असत्य से सत्य की तरफ चलने की बात कही थी और अंधकार से, अज्ञानता से उजाले की तरफ जाने की बात कही थी, लेकिन जैसा भाषण हमारे विपक्ष के सदस्यों ने दिया पहले तो उसका मतलब गलत निकाला गया।

श्री एस0एस द्वारा जारी---

03.03.2016/1410/SS-AG/1

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

इसके spiritual meaning को तोड़-मरोड़ करके राजनीतिक मीनिंग निकालने की कोशिश की गई। लेकिन जो संदेश महामहिम राज्यपाल महोदय ने दिया, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की बात कही थी, अज्ञानता छोड़ने की बात कही थी, ऐसा लगता है कि हमारे जो विपक्ष के साथी हैं उनको महामहिम राज्यपाल महोदय के शब्दों से कोई प्रेरणा नहीं मिली। इन्होंने न तो असत्य का मार्ग छोड़ा और न ही इन्हें सत्य का प्रकाश दिखाई दिया। अज्ञानता को छोड़ने की बात कही थी और ज्ञान हासिल करने की बात कही थी, इन्होंने न उस तरफ जाने की कोशिश की। कम-से-कम राज्यपाल महोदय का इतना तो आदर करते। पूरी तरह से झूठ पर आधारित भाषण दिये गये। और जो सीनियर मैम्बर, श्री महेन्द्र सिंह जी हैं जिन्होंने मुझ से पहले बोला,

इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये। एक-एक हमारे जो मंत्री हैं जिस सीक्वैंस में बैठे हैं उसी सीक्वैंस में आपने सभी को कवर किया। शायद बीच में दो को छोड़ दिया। अब पता नहीं इनकी इनके साथ क्या दोस्ती है? परन्तु बाकी सब पर बोला। लेकिन वह सारा-का-सारा झूठ पर आधारित था। ऐसा लगता है कि इनका पूरा अनुभव जो अभी तक का है उसको इन्होंने यहां पर व्यक्त किया। इससे पहले भी माननीय सदस्यों ने बोला, वे बड़े सीनियर लोग हैं। उनका भाषण भी लगभग मिलता-जुलता था। एक सनसनी फैलाने के उद्देश्य से, पॉलिटिकल स्कोर हासिल करने के उद्देश्य से सारा भाषण दिया गया। यह सिर्फ राज्यपाल महोदय के श्लोक का अर्थ गलत नहीं निकाला गया बल्कि आप चाहे हिन्दु धर्म की बात है या चाहे राष्ट्रवाद की बात है, हमेशा गलत रास्ते अपनाते गये। गलत मतलब निकालते गये और लोगों को गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। महात्मा गांधी जी का रास्ता जो सत्य और अहिंसा का था, जो सही राष्ट्रवाद का था, जो देश को आगे ले जाने और मानवता की बात करता था, आप उस रास्ते को छोड़ कर नत्थूराम गोड़से के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। कई तो आपके काडर से जुड़े हुए लोग आज गोड़से के मंदिर को बनाने की बातें करते हैं। जो हिन्दुस्तान के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इसी के चलते पिछले दिनों जे0एन0यू0 का एक बड़ा बवंडर खड़ा किया गया। --(व्यवधान)--जो आपने किया है उसके बारे में तो बोलना पड़ेगा। यह सच्चाई है। जे0एन0यू0 का एक बड़ा बवंडर खड़ा किया गया। --(व्यवधान)--

03.03.2016/1410/SS-AG/2

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य (श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी), please don't disturb. I have not allowed you to speak. Please sit down. आप बैठ जाईये।

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिवः जे0एन0यू0 के मामले में अब जो फॉरैंसिक रिपोर्ट आई है आप उसके कंटैंट्स पढ़ो। उसमें क्लीयकट लिखा गया है कि जो सी0डी0 जारी की गई, वह फैबरिकेटिड है, मैनिपुलेटिड है। आपके प्रधान मंत्री वैसे तो सब के आदरणीय हैं लेकिन जो उनकी सोच है वह बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है कि जैसे वे प्रजातंत्र के अंदर चुने हुए प्रधान मंत्री नहीं हैं बल्कि एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं। उसका शिकार सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी, आनंद शर्मा जी या अजय

माकन जी या सीताराम येचुरी नहीं हुए हैं जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकद्दमा लगाया। आपकी पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ऐसा फैसला किया। जिस परिवार के दो-दो सदस्य शहीद हुए हों उन पर आप देशद्रोह का मुकद्दमा दर्ज़ करने की बात करते हैं,

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2016/1415/केस/एएस/1

श्री राजेश धर्माणी जारी-----

इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात हो सकती है। अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस तरीके का गलत प्रयास किया जा रहा है। ---(व्यवधान)---- हम गवर्नर एड्रैस पर ही बोल रहे हैं। आपको जो रास्ता महामहिम् राज्यपाल महोदय ने दिखाया आप उस रास्ते पर नहीं चले। हम यही कह रहे हैं। न तो आप सत्य के रास्ते पर चले और जो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश डालने की बात कही न आपने उस तरफ कोई कदम उठाया।----(व्यवधान)---- राहुल गांधी जी के अंदर सत्ता का कोई लालच नहीं है। सत्ता का लालच होता तो वे पिछले टैन्योर में ही प्रधानमंत्री बन जाते। ----(व्यवधान)---- यह आप तय नहीं करेंगें, देश की जनता तय करेगी और यह तय है कि अगली बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और वे प्रधानमंत्री बनेंगें। नरेन्द्र मोदी की हालत खराब होगी, आप यह देख लेना क्योंकि जिस हिसाब से वे चलें हैं और जो उनका तरीका है, जब विदेश जाते हैं, इसी बात से खुश हो जाते हैं कि बराक ओबामा ने हाथ मिला लिया और एक जो उनका फौरन डिग्निटरीज़ के साथ गले पड़ा स्टाईल है, जब वे देश में आते हैं तो डिक्टेटर बन जाते हैं। आज जो आपके केन्द्रीय मंत्री हैं, वे बड़े दुखी हैं। वे प्राईवेट सैक्रेटरी भी अपना नहीं लगा सकते। हमारी भाजपा के एक सांसद से बात हो रही थी, वे कह रहे थे कि इन्होंने तो पूरी की पूरी पावर एक जगह सैंट्रेलाईज़ कर दी है और उसका नतीजा क्या हो रहा है, जो स्टेट से प्रोजैक्ट जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से जो प्रोजैक्ट एक साल के अंदर गए, कोई प्रोजैक्ट वहां से फाईनल

नहीं हो रहा है। बहुत बुरी तरह कुंडली मार कर उसके ऊपर बैठ जाते हैं या उसके ऊपर बिना प्रमाणिक तथ्यों के विपरित लटकाने के उद्देश्य से उस पर ऑब्जैक्शन लगाकर उसको वापिस भेज देते हैं। इस तरीके का प्रचलन हमारे फैडरल सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी अगर प्रधान मंत्री हैं तो राज्यों को मिलाकर ही देश बनता है और उस भारतवर्ष के ही वे प्रधानमंत्री हैं। भारत सरकार की वर्किंग सीधे तौर पर हिमाचल सरकार को भी प्रभावित करती है क्योंकि जो प्रोजैक्ट यहां से जाते हैं, उनको वे रोक देते हैं। मैं पिछले कल ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से बात कर रहा था कि यहां पर पहले टारगेट फिक्स किए गए, 4688 गरीब लोगों को मकान देने थे लेकिन

03.03.2016/1415/केस/एएस/2

बाद में रिवाईज करके उनको 2665 कर दिया गया। एक साल के अंदर वे ही रिवाईज़ हो रहे हैं। आप लोग एम्ज़ की बात कर रहे हैं हालांकि यह कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय की नीति थी कि प्रत्येक स्टेट के अंदर एक-एक एम्ज़ खोला जाए और 6 राज्यों में केन्द्र में हमारी सरकार के समय में एम्ज़ खुले हैं और साथ लगते राज्य उत्तराखण्ड में भी खुला है । ----(व्यवधान)---- यह ठीक है कि इसकी अनाऊंसमैंट हिमाचल के लिए डॉ0 हर्षवर्धन जी ने की है जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, यह सच है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह सांसद अनुराग ठाकुर जी ने बिलासपुर में आ कर स्टेटमैंट दी थी कि हषवर्धन जी ने इसकी घोषणा की थी और मैने कराई थी। अब सच क्या है, नड्डा जी न कराई या अनुराग ठाकुर जी ने वह आप जानें लेकिन यह पॉलिसी हमारी सरकार के समय की थी और हमें इस बात का फ़ख हैं कि आपको इस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने के लिए हमारी सरकार ने ऐजुकेशन डिपार्टमैंट के ऊपर पूरी तरह से उसको प्रायोरिटी लिस्ट पर रखा है। आज कई स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, नए इंस्टिट्यूट खोले गए हैं और हिमाचल प्रदेश में आज काफी प्रीमियर ऐजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले हैं। कोई ऐसा विधान सभा क्षेत्र नहीं है जहां पर आई.टी.आई. नहीं है। कोई ऐसा जिला

नहीं है जहां पर पोलिटैक्निक कॉलेज नहीं है। आज चार-पांच स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज यहां फंक्शनल हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

3.3.2016/1420/AV/AS/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव)क्रमागत

और आने वाले समय में जैसे बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज तथा दूसरे कॉलेज खुलने हैं, हम उसकी ओर भी अग्रसर है। हम इसके लिए मुख्य मंत्री जी और अपने मंत्री मण्डल के सभी मंत्रियों को बधाई देते हैं कि उनके प्रयासों से हमारे ऐजुकेशन सैक्टर में काफी काम हो रहा है। यह ठीक है कि कई जगह रिक्तियां हैं और उसके लिए एस.एम.सी. का प्रावधान किया गया है। लेकिन आपके ही कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं और उस प्रोसैस को रोकने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि अब पॉलिसी चेंज की है। सोहन लाल ठाकुर जी ने डिमाण्ड की थी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि जहां 6 महीने तक लगातार वेकैंसी रहेगी वहां पर एस.एम.सी. के माध्यम से भरने की इजाजत मिलेगी। इसी तरह से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत पिछली सारी की सारी पैंडिंग लिस्ट क्लीयर कर दी गई तथा सभी को पैंशन लगाई गई है। इसमें 70 प्रतिशत से ऊपर के अंपग व्यक्ति तथा 80 साल से ऊपर बुजुर्ग लोगों को आय की सारी सीमा खत्म करते हुए उनको 1100 रुपये प्रति माह की दर से पैंशन दी जा रही है। बाकी श्रेणियों को साढ़े छः सौ के हिसाब से दी जा रही है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब जहां आपकी पार्टी की भागीदार सरकार है, यहां पर वहां से ज्यादा पैंशन दी जाती है। वहां ओल्ड एज पैंशन ढाई सौ प्रति माह है। हम हिमाचल में उससे ज्यादा दे रहे हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। यहां लगभग 10,000 से ज्यादा मकान बनाने के लिए 75 हजार रुपये प्रति परिवार के हिसाब से हाउस के लिए सब्सिडी दी जा रही है। आपने एक चीज बंद कर दी थी। पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय रिपेयर के केसिज बंद कर दिए थे। हम माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने न केवल उसको चालू किया बल्कि जनरल केटेगरी में बी.पी.एल. श्रेणी के लोगों

को भी रिपेयर के लिए 25-25 हजार रुपये प्रति परिवार स्वीकृत किए जा रहे हैं। (---व्यवधान---) वैलफेयर में भी शुरू किए है।

पिछले कल यहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव बिन्दल जी कैंसर मरीज की बात कर रहे थे। यह सचमुच में एक गम्भीर मसला है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी काफी ऐक्टिव हैं और यहां पर नई-नई स्कीमें लाते हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करेंगे कि कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए जितनी मदद कर सकते हैं; करनी चाहिए।

3.3.2016/1420/AV/AS/2

हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। यहां पर पूर्व परिवहन मंत्री जी बैठे हैं। पहले कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लिए एच.आर.टी.सी. बसों में जो एक अटेडैंट के साथ फ्री ट्रैवलिंग की फेसिलिटी थी, वह भी आपने बंद कर दी थी। मैं हर बार इस प्रश्न को उठाता था कि मेहरबानी करके जो अति असहाय और परिस्थितियों के विपरीत जी रहे हैं आप उनके ऊपर इतना अत्याचार मत करो। हम अपनी सरकार के परिवहन मंत्री और मुख्य मंत्री जी के धन्यवादी हैं कि उसको सरकार बनने के एकदम बाद शुरू कर दिया है। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। इसी तरह से अगर हम यहां पर स्वास्थ्य विभाग की बात करे तो मैं यहां पर दिल्ली की बात करूंगा। आप बोल रहे हैं कि दिल्ली की बात क्यों की? हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के पैंडिंग बिल क्लीयर नहीं हो रहे थे। आपकी सरकार यह क्लीयर नहीं कर पा रही थी कि इसको लेबर मिनिस्ट्री के अंडर रखना है या हैल्थ मिनिस्ट्री के अंडर रखना है। उसके लिए आपने एक साल का समय निकाल दिया। एक साल के अंदर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिन हजारों लोगों को फायदा मिलना था उससे उनको उससे वंचित रहना पड़ा। उसको आज भी स्ट्रीम लाइन करने की जररुत है। अगर केंद्र में आपकी पार्टी की सरकार उस ओर ध्यान दे तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। यहां पी.डी.एस. सिस्टम को बेहतर बनाने की बात हुई। हम अपने मंत्री महोदय और सरकार के धन्यवादी है कि डिजिटल कार्ड बनाये जा रहे हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर डी.बी.टी. का बड़ा विरोध करती थी। डायरैक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर जो एल.पी.जी. से शुरू की गई थी जिसमें

कनज्युमर के खाते में सब्सिडी को सीधा डालने की बात की गई थी। इसको आपने इलैक्शन के दौरान भी बड़ा मुद्दा बनाया था। आज अरुण जेटली जी को उसी बात को मानना पड़ा। आज सरकार कांग्रेस पार्टी के समय चली सारी की सारी स्कीमों को अडॉप्ट कर रही है। उसका नाम बदल रहे हैं , उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उन स्कीमों को बेहतर मान रहे हैं, यह हमारे लिए खुशी की बात है।

श्री TCV द्वारा---- जारी

03.03.2016/1425/TCV/AS/1
मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी) ----- जारी

भारत सरकार की तरफ से महंगाई का बहुत बड़ा तोहफ़ा हमें मिला था और जो दालें 40-50 रूपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी, वह आपकी मेहरबानी से मोदी जी के अच्छे दिनों की मेहरबानी से वह 200 और 250 रूपये प्रति किलो के हिसाब से भी बिकी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में उसका इंपैक्ट बहुत कम पड़ा, क्योंकि यहां पर सबसिडाईज्ड दालें पी0डी0एस0 सिस्टम के माध्यम से मिलती है। इसलिए महंगाई का इंपैक्ट यहां पर कम पड़ा है। अगर यह सिस्टम नहीं होता तो हमारे यहां पर लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता था। इसमें भी माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि दो-तीन दालें क्यों मिलती है। ये तो अच्छी बात है। आपको पता नहीं क्यों बुरी लग रही है। आपकी सरकार के समय में लोगों को काले चने दिए जाते थे। लेकिन अब हमारी सरकार द्वारा लोगों को दालों की वेरायटी दी रही है। इससे लोग खुश हैं। आप तो घोड़े वाले चने देते थे। लेकिन अब तो काबली चने भी मिलते हैं। उसी तरीके से हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग है, श्रीमती विद्या स्टोक्स जी जिसकी माननीय मंत्री हैं। हमारे इन तीन सालों के अन्दर काफी सी0ए0 स्टोर और कोल्ड स्टोर बने हैं। इसके अलावा घुमारवीं और नादौन में इंटेग्रेटिड पैक हाऊस बने हैं। लेकिन आपके पांच साल बीत गये। उसके लिए आपने ज़मीन मुहैया नहीं करवाई। उसके लिए एच0पी0एम0सी0 ने जो टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी थी, वह आपने नहीं होने दी। हम अपनी सरकार (कांग्रेस सरकार) के धन्यवादी है कि अब उस पर काम हो रहा है और 5-7 महीने के अन्दर वे फंक्शनल हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारा अर्बन डिवैल्पमैंट डिर्पाटमैंट है। उसके मंत्री जी बड़े ही स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। इन्होंने हर घर को सीवरेज

कनैक्शन से जोड़न का कार्य शुरू किया है। जोकि एक अच्छा प्रयास है। हमारे यहां पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या थी। हम धन्यवादी है कि इन्होंने सब जगह पार्किंग के लिए पैसे दिए हैं। जहां तक भारत सरकार एल0ई0डी0 की बात कर रही है हिमाचल प्रदेश में यह स्कीम 'रिश्ता' नाम से पहले ही शुरू हो चुकी है। कुछेक शहरों को स्लैक्ट किया गया है और वहां पर एल0ई0डी बल्ब लगाने की बात कही गई है। यहां पर समग्र और संतुलित विकास की बात की गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश का समग्र एवं संतुलित विकास हुआ है और आगे भी होगा। हम इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी के धन्यवादी हैं। आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी

03.03.2016/1425/TCV/AS/2

ऐसा विधान सभा क्षेत्र नहीं होगा जहां पर काम नहीं हुआ है। सब जगह काम हुआ है। सभी जिलों में डिस्पेंसरियां और स्कूल खुले हैं। मेरे ख्याल से 10 के करीब फायर स्टेशन मंजूर किए हैं। हम आपके समय को भी याद करते हैं जब घुमारवीं में फायर स्टेशन खोलने की पूरी तैयारी थी लेकिन लास्ट टाईम में इसको बदल कर कहीं और ही खोल दिया गया। यह ठीक है कि सारे के सारे काम कोई सरकार नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आपकी सरकार (कांग्रेस) की और हमारी सरकार (भाजपा) की तुलना की जाये तो 90:10 का रेशो है। 90 परसेंट क्रेडिट हमें और 10 परसेंट आपको मिलता है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अच्छी सोच को लेकर चलता है और उनको सरकार चलाने का पूरा एक्पीरियंस है। जिसका फ़ायदा देश और प्रदेश के लोगों को मिलता है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

3.03.2016/1430/RKS/DC/1
मुख्य संसदीय सचिव(श्री राजेश धर्माणी) क्रमागत...

यहां हमारे मिड हिमालय प्रोजैक्ट की जो बात है इसमें अच्छा काम हो रहा है। इसमें जो कुछ आपत्तियां थी, उन पर विभाग को जरूर कार्य करना चाहिए। जैसे प्लांटेशन के

आंकड़े के बारे में बताया गया। लेकिन ऑवर ऑल इसमें देखा जाए तो जो एक्सट्रनल एजेंसीज ऑडिट करती है उनके अनुसार इसके ऊपर अच्छा काम हुआा है। वाटर सप्लाई में बहुत कुछ हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां करोंड़ों रुपये की स्कीमें मंजूर नहीं हुई हैं। कुछेक स्कीमें भारत सरकार को भेजी गई हैं। हालांकि हमें कुछ स्कीमों के लिए लोन भी लेना है। जायका से लोन लेना है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है। आपकी सरकार ने इसे रोका हुआ है। फल्ड प्रोटैक्शन की बात है। चाहे बिलासपुर की बात है, चाहे ऊना की बात है। हमने सीर खड्ड चैनेलाइजेशन जिसके लिए अभी पैसा भी नहीं आया था, बिना फॉरमैल्टीज पूरे किए उसका फाऊंडेशन रखा था। आज तक भी उसके लिए पूरा पैसा नहीं आया है। कर्नल इन्द्र सिंह जी कह रहे थे कि आगे के पैसे की बात करें। यह बात तो बाद की है। अभी पिछले पैसे भी नहीं आए हैं। जो बिलासपुर में काम हुआ, उसके लिए भी पूरे पैसे नहीं आए हैं। सडकों की बात है। अब जो 3226 ग्राम पंचायतें रह गई, उसमें से 3,117 पंचायतें ऐसी हैं जिनके हैड क्वार्टरज को सड़कों से जोड़ दिया गया है। 93 सड़कों के ऊपर काम चल रहा है। बड़ी तेजी गति के साथ हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जो हमारी फोर लेनिंग सड़के बन रही है, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे, जो वर्ल्ड बैंक फंडिड प्रोजैक्ट हैं उनमें भी अच्छा काम हो रहा है। नाबार्ड फंडिड प्रोजैक्ट बन रहे हैं। एस.सी.पी. में भी बन रहे हैं, पी.एम.जी.एस.वाई. में भी बन रहे हैं। लेकिन जो कुछेक लिंक रोड है उनको बनाने की जरूरत है। उसमें लैंड की भी समस्या है। जो छोटी सड़के हैं उनके लिए विधायक निधि या मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना पर्याप्त नहीं हो पाती है। एम्बूलैंस रोड, जैसे शिमला में एम्बूलैंस रोड बनाए जाते हैं। हो सकता है एम्बूलैंस रोड के नाम से फंडिग न मिले । तो ट्रैक्टरएब्ल रोड या जीप एबल रोड बनाने की जरूरत है। क्योंकि कई जगह 5 मीटर या 7 मीटर लैंड नहीं मिल पाती है। छोटे लिंक रोडज बनाने के लिए जो बजट आपने प्रस्तुत करना है उसमें

3.03.2016/1430/RKS/DC/2

थोड़ा सा प्रोविजन होना चाहिए। इस तरह यह एक अच्छा कदम हमारे गांव में सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए होगा। बिजली की बात की गई बिजली में पिछले एक साल से समस्या आई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि मंत्री जी बहुत ईमानदार और अच्छी सोच वाले हैं। जो हमारी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, जिसके अधीन

हमें पैसा मिलता था, जब सरकार बदली तो एक पैसा भी हमें नहीं मिला। अब उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम बदल कर दीन दयाल रख दिया। नाम चाहे जो मर्जी रख दो अटल जी के नाम से रख दो, धीमान साहब के नाम से रख दो धूमल साहिब के नाम से रख दो (घण्टी)।

उपाध्यक्षः प्लीज वाईंड अप नाऊ।

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव)ः चाहे किसी के नाम भी रख दो, पैसा आना चाहिए। उसकी तरफ आप ध्यान दिया करें। हमें इस बात की खुशी है कि अगर हिमाचल प्रदेश की तुलना यू.पी. जैसे बड़े जिला से करें और जो वहां पर उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रकचर है अगर उसकी तुलना हिमाचल से करें तो हिमाचल बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम लोग काफी चीजों में बहुत बेहतर हैं। लेकिन अभी हम ओर आगे जाने की सोचते हैं, जिसके लिए हम कार्यरत हैं। यह सारी सरकारें करती हैं। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। यह ठीक है कि 90-10 की रेशो है। उसकी अलग बात है । हिमाचल छोटा सा राज्य है। यहां पर आई.आई.टी, एन.आई. आई.टी, ट्रीपल आई.टी और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजिज हैं। 6-7 मेडिकल कोलेजिज यहां पर हैं। एम्स की स्थापना हो गई। आई.आई.एम सिरमौर में स्थापित किया जा रहा है । 90 से ज्यादा हमारे पास डिग्री कॉलेज है। 15,000 से ज्यादा यहां पर स्कूल हैं। केंद्रीय विद्यालय हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंन अब जवाहर नवोदय विद्यालय का ओर प्रोविजन रखा है। इसकी जरूरत है। क्योंकि जवाहर लाल नेहरू के प्रति आपकी भावना ठीक नहीं है। लेकिन आपने जे.एन.वी. खोलने के लिए अच्छा काम किया है। इसी तरह यहां पर एन.आई.एफ.टी., सेंट्रल

3.03.2016/1430/RKS/DC/3

यूनिवर्सिटीज है। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एण्ड टैक्नोलोजी जिसका संस्थान बद्दी में है। ये सब काम कांग्रेस पार्टी के हैं। चाहे ये किसी भी सरकार के काम हो परन्तु हिमाचल के

लिए एक बहुत बड़ा बदलाव इन संसथानों की वजह से आ रहा है। सोलन में यूनिवर्सिटी है, पालमपुर में युनिवर्सिटी है।

श्री एस.एल. एस. द्वारा ....जारी

03.03.2016/1435/SLS-AG-1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव) ....जारी

जो एग्रीकल्चर तथा हार्टिकल्चर एंड फौरैस्ट्री युनिवर्सिटज हैं। बाकी भी प्राईवेट युनिवर्सिटीज और प्राईवेट इंस्टिच्युशन्ज हैं। यह हिमाचल के लिए अच्छी बात है और हमें इसके लिए काम करना है। कुछ पैंडिंग प्रोजैक्ट्स हैं। कल भी यहां पर ESI Medical College की बात हुई। मैं भी मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा था और आप भी करें कि अगर इसको ESI स्वयं चलाए तो इससे बढ़िया बात नहीं होगी। कई जगहों पर वह चला रहे हैं। मैंने पीछे अख़बारों में ऐड पढ़ी जहां उन्होंने फैकल्टी के लिए ऐप्लिकेशन्ज इनवाईट की थीं। हालांकि हम माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी के धन्यवादी हैं। इन्होंने यह कहा है कि हम खुद चलाएंगे। जिम्मेवारी को उठाने की इन्होंने बात कही है। जब कांग्रेस पार्टी के समय में ही वह सैंक्शन हुआ था तो उसको चलाने में भी कोई हर्ज़ नहीं है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। हमारे जो बहुत सारे फोर लेनिंग के प्रोजैक्ट्स हैं वह पैंडिंग हैं जिन्हें स्पीड अप करने की ज़रूरत है।

AIIMS के बारे में भी अख़बारों में पढ़ने को मिला कि अभी तक उसको डिले किया जा रहा है। बाकी स्टेट्स में प्रॉयरिटी मिल रही है लेकिन यहां पर नहीं मिल रही है हालांकि मंत्री जी हमारे जिले और प्रदेश से हैं। उनको इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।

NH बहुत ज्यादा डिक्लेयर हुए हैं। ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि 10 के करीब बने हैं। इनकी संख्या बढ़ रही है लेकिन शिमला धर्मशाला रोड कब से बना है, मण्डी

पठानकोट कब से NH डिक्लेयर हुआ है लेकिन इनके लिए फंड्ज जब तक प्रॉपर नहीं आएंगे, तब तक इनसे लाभ नहीं मिलेगा।

Deputy Speaker: Hon'ble Member, please wind up now.

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव): जो रेलवे बजट पीछे पारित हुआ है उसमें हिमाचल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है; इसमें कोई लाभ नहीं हुआ है।

03.03.2016/1435/SLS-AG-2

Deputy Speaker: Please wind up.

श्री राजेश धर्माणी(मुख्य संसदीय सचिव) : मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। आपका धन्यवाद।

हमारे लगभग 12023 करोड़ रुपये के एक्सटर्नल एडिड प्रोजैक्ट्स पर इस समय काम चल रहा है।

लैंड रिकॉर्ड्स में माड्रनाईजेशन की बात कही गई है। यह बहुत अच्छा कदम है।

हम भी अनुरोध करेंगे और आप भी इस बात पर सहमत होंगे कि विधायक निधि की राशि को, जितने भी संशाधन आपको अलौ करते हैं, इसको बढ़ाकर एक-डेढ़ करोड़ के आसपास किया जाए। सी.एल.पी. मीटिंग में भी हमने इसके लिए अनुरोध किया था।...(व्यवधान)... चलो, दो करोड़ के लिए आप कह देना। इसके लिए मुख्य मंत्री महोदय कदम उठाएंगे।

हिमाचल प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार द्वारा और तेज गति से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि पर्यटन अकेले में विकसित नहीं होगा जब तक कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। यहां पर अच्छी हवाई पट्टियां बनें, रोड अच्छे बनें और रेलवे की भी अच्छी सुविधा हो।

राज्यपाल महोदय ने आपसे कहा कि असत्य छोड़ कर सत्य के मार्ग पर चलो और अज्ञानता के अंधकार को छोड़कर ज्ञान के प्रकाश की ओर चलो। जो वास्तविकता है,

जो हिमाचल प्रदेश में विकास हो रहा है, जो यहां पर थोक में काम हो रहे हैं, उनको एप्रिशियेट करने के लिए भगवान् आपको सद्बुद्धि दे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

03.03.2016/1435/SLS-AG-3

श्री बिक्रम सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण 25 फरबरी, 2016 को दिया गया, जिसका धन्यवाद प्रस्ताव श्री जगजीवन पाल जी ने किया और अनुसमर्थन भाई अजय जी ने किया, आपने मुझे उस पर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

काफी विधायकों ने इस अभिभाषण पर चर्चा में भाग लिया। लेकिन जो शुरुआती 2 विधायक थे, वह दोनों मेरे मित्र हैं। झूठी बात को सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये क्या करते, उसमें था तो कुछ नहीं? भाई जगजीवन जी ने देखा कि अगर इसके ऊपर कुछ बोलेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए ये आस-पास के राज्यों में घूमते रहे। कभी पंजाब में चले गए तो कभी हरियाणा में चले गए और कभी जे.एन.यू. में चले गए। फिर क्योंकि इनको माहौल गर्म करना आता है, इसलिए जब देखा कि शोर मच गया, इन्होंने धन्यवाद किया और मस्त हो गए। मेरे दूसरे मित्र अजय जी बहुत शरीफ़ हैं। जब वह बोल रहे थे, बोलते-बोलते उनका सांस चढ़ रहा था। मेरे से आयु में भी छोटे हैं। मैंने कइयों को पूछा कि क्या समस्या है। फिर मैंने उनसे भी पूछा कि क्या हुआ? कहते हैं कि मैंने कभी उम्र भर झूठ नहीं बोला, इसलिए मेरा सांस चढ़ रहा था। दोनों ने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी और रखनी भी चाहिए।

जारी ...गर्ग जी

03/03/2016/1440/RG/AG/1

श्री बिक्रम सिंह-----क्रमागत

आज भाई साहब ने भी, ये भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने भी इधर-उधर हाथ लगाए, लेकिन बाद में लाईन पर आ गए। आपको जो किताब दी है, आप इसके ऊपर बात करिए कि इसमें किया क्या है? इसमें जो लिखा है उसको सिद्ध करने की भी कोशिश करिए। कल मेरे एक भाई बोल रहे थे कि जिस समय पंचायतों के चुनाव हुए हैं इनमें हमें 80% सफलता मिली है। कोई 70% बता रहा है। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि वह 70 कहां हैं? हमारे यहां जो पंचायतों के चुनाव हुए, तो बी.डी.सी. के चेयरमैन हमारे, प्रधान हमारे, जिला परिषद का चेयरमैन हमारा, हां, आपने कोशिश जरूर की है। जो कुछ नेता आपने चुनाव क्षेत्रों में छोटे-मोटे छोड़े हैं, जहां आपको नेता नहीं मिलते, वहां छोड़े हैं। हां, खरीदने की कोशिश जरूर की है। मेरे प्रागपुर की एक महिला जीती है बख्शीश कुमारी, उसको कहते हैं कि दो लाख रुपये ले लो, हमें वोट दे देना। इस प्रकार की कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंदर जो मेनडेट जनता ने दिया है, वह आपके खिलाफ दिया है। कुलदीप जी कह रहे थे कि लोगों ने हमें जिताया है, लेकिन ये भूल गए कि जिताने के बाद हराया भी है। आप लोक सभा में हारे हैं और अभी जो चुनाव हुए हैं इन चुनावों के नतीजे हैं। यह जरूर है कि ये चुनाव पार्टी चिह्न के ऊपर नहीं होते और अगर आप 80% सीटें भी जीते हैं, तो आज आपको धर्मशाला में क्या समस्या हो गई? आप वहां पार्टी चिह्न के ऊपर चुनाव क्यों नहीं करा रहे? आप क्यों कायदे-कानून बदल रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि यह जमीन खिसक रही है और इसलिए कोई-न-कोई बहाना है और खरीद-फरोख्त करने के लिए यही ढंग आपके लिए बहुत अच्छा है। इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी भाईसाहब ने शिक्षा के बारे में बहुत बातें कीं कि बहुत सारी संस्थाएं खुल गईं। इसमें भी लिखा है कि हमने 21 नए प्राथमिक स्कूल खोल दिए, 39 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल बना दिया, 92 को हाई स्कूल बना दिया और 58 को सीनियर सैकण्डरी स्कूल बना दिया और एक प्रश्न के उत्तर में सरकार का जवाब है कि हमारे प्रदेश में पांच या पांचवीं कक्षा से कम, विद्यार्थियों के 411 स्कूल हैं, 6 से 10 वाले 725 हैं और 943 प्राईमरी स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक टीचर है। ठीक है विधान सभा में नेताजी जाते हैं, हम लोग मांग करते हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ती है, लेकिन उसके

साथ-साथ बाकी चीजों की तरफ भी ध्यान दें। मैंने पढ़ना फिजिक्स है, लेकिन वहां टीचर पॉलिटिकल साइंस का है, फिजिक्स का टीचर ही

03/03/2016/1440/RG/AG/2

नहीं है। क्वालिटेटिवली हम कहां जा रहे हैं? आप 5-5 किलोमीटर के ऊपर स्कूल खोल रहे हैं, अच्छी बात है आप खोलिए। मैं कहता हूं कि 4 किलोमीटर के ऊपर खोलिए, लेकिन उसके साथ-साथ टीचर और भवन भी दीजिए, वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर भी दीजिए।

उपाध्यक्ष जी, मुझे तो बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, मुझे भाईसाहब ने चिट भेजी कि आप ऐसे ही डाडासीबा की बात करते हैं। अब डाडासीबा में कॉलेज चल रहा है, तो वह प्राईमरी स्कूल में चल रहा है। जहां कॉलेज चाहिए, वहां कॉलेज खोलना नहीं है। आज माननीय मुख्य मंत्री यहां नहीं हैं। यदि अंदर होते, तो उनसे चार बातें और होनी थीं। मेरे चुनाव क्षेत्र में कॉलेज बंद कर दिए। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में केस जीत लिया। पहली बार देखा है कि किसी प्रदेश की सरकार का मुखिया या वह सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि वहां कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। लेकिन इस सदन में मैं बहुत जोर से बता देना चाहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी हारेंगे और वहां कॉलेज खुलेगा, पक्का खुलेगा। यह मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां सभी बहुत गुणगान कर रहे थे। भाई कालिया जी को मैंने कभी गुणगान करते नहीं देखा, परन्तु इन्होंने भी बहुत गुणगान किया। अच्छा लगा कि चलो ठीक है अपने नेता का गुणगान करना चाहिए। लेकिन जो कमियां हैं उनके बारे में बंद कमरे में जाकर तो उन्हें बताओ कि ये कमियां हैं, इनको ठीक करो। हम सभी धन्यवाद करते हैं। श्री जगजीवन पाल जी ने अपने भाषण में 16 बार धन्यवाद किया और श्री महाजन जी ने 11 बार धन्यवाद किया। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रशंसा करना कोई बुरी बात नहीं है। --(व्यवधान)--कालिया साहब, जब आप बोल रहे थे, तो हमने आपको कुछ नहीं कहा। आपने बहुत अच्छी बातें कीं, आपने हम पर कटाक्ष भी किए। यह कोई बुरी बात नहीं है, करना भी चाहिए। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि केवल यह जो स्वां चैनेलाइजेशन की बात है, आपके साथ वहीं पर ही धोखा नहीं हुआ, आप जब से राजनीति में आए हैं, तब से आपके साथ धोखा हो रहा है। आपको कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया, मेरे मित्र हैं, मेरे पड़ोस में हैं। मंत्री आपको नहीं बनाया, आपको सी.पी.एस. बनाया, फिर आपने त्याग-पत्र दे दिया क्योंकि गाड़ी भी अच्छी नहीं थी और

दफ्तर भी अच्छा नहीं था। तो ठीक है, आपके साथ धोखा हुआ है, मैं आपके साथ हूं। अगर आपने इस सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करना है, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप चिंता न करें।

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2016/1445/MS/AG/1

श्री बिक्रम सिंह जारी-------

मैं यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एजुकेशन के बारे में ये बातें अखबारों में भी आई हैं। "टीचर है नहीं पूरी कैसे होगी पढ़ाई" यह खबर दैनिक भास्कर में आई है। धर्माणी जी जो एस0एम0सी0 वाला विषय है मैं चाहता हूं कि इसमें भी थोड़ी अमेंडमैंट करें। अच्छी बात है जहां टीचर नहीं हैं वहां एस0एम0सी0 के द्वारा टीचर लगने चाहिए। लेकिन आप एक ऐसा कायदा-कानून बना देते हैं जिसमें सुबोर्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड से टैस्ट पास किया हुआ व्यक्ति वहां पर ड्यूटि नहीं दे सकता, ज्वाइन नहीं कर सकता। ऐसे काम मत कीजिए। जिसने टैट क्वालिफाई किया है, उसको लगाइए। एक ऐसा जो हमारा रिश्तेदार है उसको हम एस0एम0सी0 पर लगा रहे हैं क्योंकि उससे न तो टैट क्लीयर हुआ, न सुबोर्डिनेट सर्विसिज सिलैक्शन बोर्ड में वह पास हुआ। हम ऐसे-ऐसे लोगों को वहां लगा रहे हैं कि 80 प्रतिशत वाला पीछे रह रहा है और 50 प्रतिशत वाला लग रहा है। इसलिए इसके ऊपर भी ध्यान दें। क्वालिटेटिवली ये सारी चीजें देखें ताकि हमारे बच्चे आगे निकले और सारी बातों को समझें। अब कॉम्पीटीशन का जमाना है।
स्वास्थ्य के ऊपर भी यहां बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें हुईं। माननीय कौल सिंह जी सदन से बाहर चले गए हैं। -(व्यवधान)- बिना टैट पास किए हुए लोग कहां-कहां लगे हैं, यह भी मैं बता देता हूं। जगजीवन पाल जी आप इस चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको बता दूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र 103 किलोमीटर लम्बा है और उस एरिये में जो बी0एम0ओ0 है उनके पास न गाड़ी है और न ही ड्राइवर है। उन्होंने सारे एरिये को देखना होता है लेकिन उनके वाहन की सुविधा नहीं है। जो वहां पर पी0एच0सी0 कस्बा कोटला है वहां

पर एलोपैथी का डॉक्टर ही नहीं है और आयुर्वेदिक डॉक्टर छुट्टी पर चल रहा है। इसी तरह से प्रागपुर में जिस भी डॉक्टर को लगाते हैं वह या तो ट्रेनिंग पर रहता है या डैपुटेशन पर रहता है। सिविल अस्पताल गरली की बात करूं तो नाम उसका सिविल अस्पताल गरली है लेकिन कोई स्पैशलिस्ट डॉक्टर वहां नहीं है। मेरा 103 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें जितनी भी पी0एच0सीज0 या सी0एच0सी0 हैं कहीं पर भी स्पैशलिस्ट

03/03/2016/1445/MS/AG/2

डॉक्टर्ज नहीं हैं। छः ऐसे स्वास्थ्य उप केन्द्र हैं जिनमें न मेल हैल्थ वर्कर है न फीमेल हैल्थ वर्कर है और आप कह रहे हैं कि मोतियों वाली सरकार बड़ी अच्छी है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। काम कहां हो रहा है? जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता को मिलनी चाहिए, उससे आम लोग वंचित और परेशान हैं। इसी कारण से ये परिणाम आपके खिलाफ आ रहे हैं। आप यहां पर बैठकर बोल रहे हैं कि मेरा तो ब्रह्म वाक्य है कि आप ही मुख्य मंत्री बनेंगे। अब मुझे नहीं पता कि ये ब्रह्म वाक्य आप कहां से निकाल रहे हैं। आप अच्छे काम करो, अच्छी तरह प्रदेश को लेकर जाओ और विकास करो। लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस चमचागिरी पर जोर दिया हुआ है। अब किसी ने कुछ नहीं बनना है। जो सी0पी0एस0 है वह सी0पी0एस0 ही रहेगा और जो कुछ नहीं है वह कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप ऐसे चक्कर में मत पड़ो। आप काम करो और काम करके आगे बढ़ो। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जीतकर यहां आएं। अच्छी बात है। लेकिन जीतना कैसे है? ऐसा करके नहीं जीतेंगे कि मुख्य मंत्री मेरे क्षेत्र के अंदर आए और मैंने गले तक हार पहना दिए और उसके बाद बढ़िया बैंड बाजा बजा दिया और कालिया साहब तो और आगे चले जाते हैं उनको हाथी पर घुमाते हैं। इसलिए काम कीजिए तभी यहां वापिस आएंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो वापिस नहीं आएंगे। पूरे ब्लॉक में तीन एक्सरे प्लांट हैं और तीनों पर कोई भी रेडियोग्राफर नहीं है। तो यह स्वास्थ्य विभाग का हाल है।

माननीय वन मंत्री जी यहां बैठे हैं। मेरा आपसे वही प्रश्न है जो माननीय बिन्दल जी ने किया था। लैंटाना घास की जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमने इस पर बड़े पैसे खर्च कर दिए। आप ये काम कहां कर रहे हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछ नहीं

हो रहा है बल्कि यह घास बढ़ रहा है। इसलिए आप इसका स्पष्टीकरण जरूर दें कि ये काम आपने कहां लगाया हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भी गोलमाल हो रहा है? जैसे महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि आप इतने पेड़ों को कहां लगा रहे हैं। आप करोड़ों में पेड़ लगा रहे हैं। आज तक आपने अपने समय में जहां-जहां वन महोत्सव मनाया आपको उसका भी सर्वाइवल रेट पता नहीं होगा बाकियों की बातें तो छोड़ दो। क्योंकि आपने कहीं जाना ही नहीं होता है। आप किसी और ही काम में लगे हुए हैं। जो काम आपको दिया हुआ है आप

03/03/2016/1445/MS/AG/3

उस काम में नहीं लगे हैं। आपका ध्यान कहीं और है इसलिए आप उस ध्यान को ठीक करें।

पेयजल के बारे में सुबह भी चर्चा हुई और उसमें मुझे भी बोलने का मौका मिला। परन्तु पेयजल की स्थिति बड़ी गम्भीर है, इसको ठीक कीजिए। एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसके ऊपर पहले भी लगा था और मैंने उसमें भी बोला था कि चिन्तपूर्णी के साथ लगते क्षेत्रों में यह बहुत ज्यादा समस्या है। वहां पर पीलिया पहले ही फैल चुका है,

जारी श्री जेके0 द्वारा-----

03.03.2016/1450/जेएस/एजी/1

श्री बिक्रम सिंहः------जारी-------

वहां के जो रिजल्ट्स हैं यह चिन्तपूर्णी का जितना भी हमारा होटलों का पानी आता है वहां पर सीवरेज न होने के कारण है और विभाग का ज़वाब बड़ा ज़बरदस्त है, वे कहते हैं कि हमने 16.4.2012 को 8.5 करोड़ की डी0पी0आर0 अप्रूव करके भेज दी है। अब मझ में नहीं आ रहा है कि वह कहां पर है और वह गन्दा पानी लोग पी रहे हैं। शिवपुरी समरोली के अन्दर गन्दा पानी है और जितने भी वहां पर सोर्सिज है उनकी पीएच 1.9 है और जब कि नॉर्मल 6.5 और 7.5 के बीच में होनी चाहिए और जो वहां की टी.डी.एस. है जितने भी वह डिजॉल्व सोलिड्ज़ हैं वह बिलो नॉर्मल है। इम्पयोरिटी बहुत ज्यादा है और वहां पर बहुत बीमारियां फैल रही है और यहां पर विभाग पता नहीं कहां से ज़वाब

ले आते हैं? अब मैडम जी को क्या कहना, हमसे डबल उम्र के हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पर जवाब तो ठीक तरीके का आए। मैं वहां पर जा कर आया हूं। वहां का स्पॉट चैक करके आया हूं। वे कह रहे हैं कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं और अखबारों में आने के लिए कह रहे हैं। अखबारों में आने के और भी कई तरीके हैं। अगर आप मूल काम नहीं करेंगे, आपके विभाग की हालत इतनी खराब है, मेरे क्षेत्र के अन्दर कोई भी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ढंग से नहीं चलती है। जब हम प्रश्न करते हैं तो ज़वाब आ जाता है कि थोड़ी देर में ठीक कर देंगे। वह ठीक तो हुई नहीं। इसलिए इन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा आपसे बार-बार निवेदन रहेगा कि ये जो पीलिया वगैरह हो रहा है , ये सारी चीजें इसी कारण से हो रही है। बाढ़ के ऊपर भी विषय आया था। मैंने आज से तीन साल पहले सेक्रेटरी, आई0पी0एच0 को पत्र लिख कर और पर्सनली मिल कर क्योंकि मेरे क्षेत्र के अन्दर बाढ़ के कारण बहुत नुकसान होता है। वहां पर बहुत से नदी-नाले और खड्डें हैं उनकी चैनेलाईजेशन के लिए तीन साल पहले और बार-बार रिमाईंडर दे चुका हूं लेकिन आज तक उसकी डी0पी0आर0 नहीं बनी। यह जो स्थिति है इस स्थिति के कारण मुझे लगता है कि सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। सड़कों की हालत तो इतनी ज्यादा खस्ता है कि एक मेरे मित्र यहां शायद गैलरी में बैठे हो, प्रैस वाले गलती से मेरे क्षेत्र में चले गए वहां से जा करके उन्होंने

03.03.2016/1450/जेएस/एजी/2

फोन किया और मैंने पहले पहचाना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं फ्लां व्यक्ति बोल रहा हूं कि यहां पर सड़कों की इतनी बुरी हालत है। मैंने कहा यह बिल्कुल सच है। हमने सड़कों को ठीक करने के लिए आंदोलन किया। आप लोगों ने केस बनाए। हमने वहां पर पदयात्रा की। आपने हमारे ऊपर केस बनाए लेकिन सड़कों की हालत बहुत ज्यादा पतली है। आज चिन्तपूर्णी से तलवाड़ा तक आप चले जाईये। आप तलवाड़ा से लेकर उसके बाद डाडासीबा तक चले जाईये, ये जो हमारे गांव है कुंदणी बगैरह उसमें चले जाईये कहीं पर भी सड़कें ठीक नहीं है । इसलिए यह कहना कि हमने तो लाखों रूपये खर्च कर दिये। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। आज किसी ने मुख्य मंत्री जी को याद करवाया कि आपने बोला था कि जो काम नहीं

करेगा उसको मैं एक्सिअन से एस0डी0ओ0 बना दूंगा। एस0डी0ओ0 से जे0ई0 बना दूंगा। अब कहते हैं कि नहीं नहीं वह तो सिर्फ डराव था। उनको कोई डराव नहीं है। आप अब डरो। आप के कहने पर जो अधिकारी हैं वे भी काम नहीं करना चाहते हैं। उनको पता है कि आप कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए अधिकारी आपकी इन्स्ट्रक्शन्ज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। इण्डस्ट्री के ऊपर भी काफी चर्चा हुई है। इसमें तीन-चार प्रश्न भी हमने किए थे। मेरा विधान सभा क्षेत्र के अन्दर संसारपुर टैरेस इण्डस्ट्री एरिया पड़ता है। आज भी उसमें एक प्रश्न लगा है कि पॉल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा कितनी इण्डस्ट्रीज का निरीक्षण किया गया? इसमें ज़वाब आया है कि 234 बार किया गया और एक लम्बी लिस्ट दी है कि इनके ऊपर हमने एक्शन करने के लिए बोला है । लेकिन ऐसा वहां पर फील्ड में कुछ नहीं है। माननीय अग्निहोत्री जी, उद्योग मंत्री जी यहां नहीं है। मैंने कभी भी उनके मुख से इस सदन में नहीं सुना कि संसारपुर टैरेस इण्डस्ट्री एरिया के लिए वे कोई योगदान देना चाहते हैं। ठीक है, कन्दरोड़ी में खुले, अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि वह इण्डस्ट्री मिनिस्टर केवल हरोली के ही इण्डस्ट्री मिनिस्टर बन करके रह गए हैं। हर चीज हरोली में। हर चीज हरोली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर। ठीक है उनकी सैटिंग है और भाई रतन सिंह की भी

03.03.2016/1450/जेएस/एजी/3

सैटिंग है लेकिन दूसरे क्षेत्र भी देखो। इनको दफ्तर दो बढ़िया,बढ़िया और ये एस0डी0एम0 का ऑफिस लाए हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जिनको 70 किलोमीटर दूर से एस0डी0एम0 ऑफिस जाना पड़ता है। केवल यही बात है कि वहां से कांग्रेस का केंडिडेट हार गया। आप मेम्बर पार्लियामैंट का चुनाव कभी जीते नहीं, यही कारण है। इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता के साथ यदि आप चलेंगे तो काम नहीं बनेगा। श्री रवि जी ने जो सैन्टरल युनिवर्सिटी की बात कही है वह बिल्कुल ठीक कही है। मैंने तो दोस्ती के नाते अपने भाईयों को समझाया भी है कि आस-पास के विधान सभा क्षेत्रों के जितने भी नुमाईंदें हैं जो अन्दर से सैन्टरल युनिवर्सिटी का

विरोध कर रहे हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

03.03.2016/1455/SS-AS/1

श्री बिक्रम सिंह क्रमागतः

उनके लिए अच्छे दिन नहीं आयेंगे। उनकी हालत पतली होगी। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, जिस समय मैं रतन जी से बात करता हूं। हम चाहते हैं कि वहां पर सैंट्रल यूनिवर्सिटी बने। भाई सुधीर जी, इस तरह से बिना मतलब से पंगे लेने से कोई फायदा नहीं है। आप मुख्य मंत्री जी को ऐसे विषयों में बहुत कंफ्यूज करते हैं, इस चीज़ के पीछे क्यों लगे हो? स्मार्ट सिटी बनाओ, कुछ और करो जो काम करना है। वहां पर बहुत बढ़िया ग्राऊंड है वहां पर बढ़िया-बढ़िया मैच करवाओ। लेकिन आप इन कार्यों में लगे हुए हैं और हमारी यूनिवर्सिटी को खराब कर रहे हैं। इसलिए आप उनको सुजैस्ट करो, मैं देखता हूं कि वे आपका बड़ा कहना मानते हैं। जिस समय उनको समझ नहीं आता तो वे आपकी तरफ देखते हैं। इसलिए इसका ज़रूर ध्यान रखा जाए।

अवैध खनन के बारे में बड़ी भारी बातें हुई हैं। अवैध खनन में आप कहते हैं कि आप अवैध खनन को देख रहे हैं। मेरे हिसाब से आप खनन को कुछ नहीं देख रहे। कांग्रेसियों का जो खनन है वह वैध है और अगर बी0जे0पी0 वाला अपना ट्रैक्टर लेकर जाता है तो वह अवैध है। आप चालान निकलवा कर देख लीजिये कि सारे के सारे चालान एक ही पार्टी के समर्थकों के हुए हैं। यह बात गलत है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। भाई राकेश कालिया जी भी बोल रहे थे कि सभी को मिल कर चलना चाहिए। जब आप इधर होते हैं तो अच्छी बात करो और जब हम इधर होंगे तो अच्छी बात करें। कैसे करें भाई? जब आपने हमारे चालान किये तो क्या हम आपके नहीं करेंगे? हम पूरा गेड़ा देंगे जब हम

सरकार में आयेंगे, अगर आप ऐसा काम करेंगे तो। हमारे चालान कर रहे हैं, बी0जे0पी0 के लोगों को पकड़ा जा रहा है, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें भी वही करना पड़ेगा।--(व्यवधान)--भाई जी, आप बी0जे0पी0 के हैं। आप कांग्रेस के नहीं हैं, यह आपको पता नहीं हैं। ये जो सारे विषय मैंने लिये हैं, मैं यह केवल इसलिए बता रहा हूं कि अभी भी आपके पास टाइम है अच्छा काम करने का। इसलिए कुछ जो विधान सभा क्षेत्रों के अंदर आपने पैराशूटी नेता भेजे हुए हैं और वे जो मुख्य मंत्री जी को बोल देते हैं वे उसको मान जाते हैं। आप अच्छा-बुरा तो देखो। जैसा किसी

03.03.2016/1455/SS-AS/2

ने बोला वैसा मान लिया, यह सही नहीं है। यह तो देखो कि यहां करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।

मैं एक बात और करना चाहता हूं। यहां पर आदरणीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। जब भी किसी विधान सभा क्षेत्र के अंदर जाते हैं। लोग आपसे डिमांड करते हैं आप उसको पूरा करिये। लेकिन आपको अपनी उम्र के मुताबिक बोलना चाहिए। छः बार आप मुख्य मंत्री रहे हैं आपने मंच के ऊपर खड़े हो कर बोलना क्या है उसका स्तर तो बनाईये। और साथ में जो मेरे दोस्त जाते हैं वे भी उनको नहीं समझाते हैं कि ये बातें अच्छी नहीं होतीं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात बाद में करता हूं। मेरे दो भाई इधर बैठे हैं। सतपाल सिंह सत्ती जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। वीरेन्द्र जी, तीसरी बार एम0एल0ए0 बने हैं। इनके विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं तो कहते हैं कि ये धूमल जी के बंधुआ मजदूर हैं। क्या बोल रहे हो आप? हमें आप क्या सीखायेंगे? जिस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कई बातें मुझे नहीं बोलनी चाहिएं लेकिन मैं उन्हें बोलूंगा। ये कहते हैं कि मेरे को चार-पांच बी0जे0पी0 के एम0एल0ऐज़0 काम नहीं करने देते। वे सदन के अंदर शोर मचाते हैं और जो उनका सरगना है वह बिक्रम ठाकुर है। भाई, जो व्यक्ति मेरे कॉलेज को बंद करेगा, उसके लिए अगर मुझे सरगना भी बनना है तो मैं सरगना बनूंगा। अगर कोई व्यक्ति मेरे क्षेत्र में सड़कों का सुधार नहीं करेगा, उसके

लिए अगर मुझे सरगना बनना पड़े तो मैं सरगना बनूंगा। लेकिन बात का एक स्तर होता है। कोई उनको देखता नहीं है कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में क्या बात करनी है या क्या नहीं करनी है। जो unconstitutional authorities हैं, वे कुछ भी बोलते हैं तो उसे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन रहेगा कि अभी आपका आगे भी टूअर आना है, हमने वहां पर आपका स्वागत ही किया है। पहली बात तो यह है कि आप लोग हमें कार्यक्रमों के अंदर बुलाते नहीं हैं लेकिन हमने वहां पर आपके बारे में कोई अपशब्द प्रयोग नहीं किये। अगर आपने ऐसे ही सरगने बनाने हैं, ऐसे ही बंधुआ मजदूर बनाने हैं तो अगली बार तैयार हो कर आना और रतन जी आप मत साथ आना। अमूमन आप ही आते हैं तो मुश्किल होगी।

03.03.2016/1455/SS-AS/3

अंत में, मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। मैंने तो कभी सुना नहीं था लेकिन आज राकेश कालिया जी ने भी शेर सुना दिया। ये भी शायर हैं। इनके ससुराल मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, मैं इनके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता। आप शायर अभी बने या पहले जवानी में भी थे। इनके कारण से मुझे भी मुख्य मंत्री जी से एक शेर बोलना पड़ेगाः-

"ये दुनिया इंसानों की बसती है फरिश्ता मत बन,
ये दुनिया इंसानों की बसती है फरिश्ता मत बन,
लोग पत्थर से तूझे मारेंगे शीशा मत बन,
ऐसा कुछ कर कि तूझे सारा ज़माना देखे
अपनी पहचान बना भीड़ का हिस्सा मत बन।"

उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2016/1500/केस/डीसी/1

श्री विनय कुमार(मुख्य संसदीय सचिव)ः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय जगजीवन

पाल जी ने लाया व जिसका अनुसमर्थन श्री अजय महाजन जी ने किया, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पूर्व वक्ता भाई विक्रम जी ने कहा कि आप बार-बार धन्यवाद करते हैं और उपलब्धियां कुछ नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि जगजीवन पाल जी और अजय महाजन जी ने शायद धन्यवाद कम किया है, मैं अभी बहुत ज्यादा धन्यवाद करने जा रहा हूं। जो उपलब्धियां माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी की सिरमौर जिला के लिए रही हैं सबसे पहले मैं शुरूआत करना चाहूंगा कि जब सबसे पहले मुख्य मंत्री महोदय सिरमौर दौरे पर आए तो उन्होंने हमारी कुछ नई तहसीलें बनाईं । उनमें तीन उप-तहसील जो बनाई उनमें हरिपुरधार, नारग और पजोता है जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं, आप गिनते रहना कि मैं कितने धन्यवाद करता हूं। उसके बाद दोबारा जब मुख्य मंत्री जी सिरमौर के दौरे पर आए तो उन्होंने शिलाई विधान सभा क्षेत्र में एस.डी.एम. कार्यालय खोला। वह बहुत ही दूर-दराज का क्षेत्र है और रोनाहट से लेकर लोगों को पांवटा जाना पड़ता था। एस.डी.एम. अभी वहां पर ज्वाईन करेंगें आप चिन्ता न करें। लोगों को शिलाई में इसकी सुविधा मिली है। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आई.आई.एम. सिरमौर जिला को दिया। इसके लिए भूमि का चयन भी हो चुका है और धौलाकुंआ में एक हजार दस बीघा जमीन दे दी गई है और इसकी क्लासिज़ भी शुरू कर दी गई है जो कि अभी पांवटा में चल रही है। इसके अलावा नाहन में मैडिकल कॉलेज खोला गया जिसके लिए सरकार

03.03.2016/1500/केस/डीसी/2

ने 190 करोड़ रु0 का प्रावधान किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसका नामकरण डॉ0 वाई.एस. परमार जी के नाम से किया गया है क्योंकि वे हिमाचल के निर्माता हैं और सिरमौर जिला से सम्बन्ध रखते हैं। मैं इसलिए भी धन्यवाद

करता हूं कि उनके चुनाव क्षेत्र का नेतृत्व अब मैं कर रहा हूं। नाहन हॉस्पिटल के नज़दीक इसके लिए 21 एकड़ भूमि का प्रावधान करवाया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि हमारे जिला में उन्होंने तीन डिग्री कॉलेज खोले और तीनों के लिए 13-13 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है। नाहन डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के लिए उन्होंने लगभग 20 करोड़ 38 लाख रुपये का प्रावधान किया है । हमारे जिला में लगभग 144 नए स्कूल खोले गए हैं व अपग्रेड किए गए हैं जिनमें से 31 नए प्राईमरी स्कूल है । हमारा जो सब काडर एरिया है, शिलाई और रेणूका का एरिया हार्ड एरिया है और आज भी वहां पर प्राईमरी स्कूल खोलने की बहुत जरूरत है । हमारे छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए खड्डों से होकर दूर-दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.3.2016/1505/av/ag/1

श्री विनय कुमार (मुख्य संसदीय सचिव) जारी

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो बहुत अर्से से लटके हुए कॉलेज थे; जैसे शिलाई का और संगड़ाह का कॉलेज है। उसको अपने कार्यकाल के दौरान पूरा करवाया और उसके लिए ऐडिशनल फंड्ज का प्रावधान किया। मैं अपने संगड़ाह कॉलेज की बात बताना चाहता हूं। उस कॉलेज को जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था तो उस समय इसके लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। मगर पिछली सरकार के कार्यकाल के समय उस कॉलेज में कोई भी कार्य नहीं करवाया गया। उस कॉलेज की 6-7 वर्षों के गैप के कारण कॉस्ट बढ़ गई। इस वजह से उस कॉलेज को 6 लाख रुपये ऐडशिनल बजट के रूप में और दिया तथा इन दोनों कॉलेजों का उद्घाटन भी किया। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी तरह से राजगढ़ का कॉलेज जो लटका हुआ है, उसके लिए भी धनराशि का

प्रावधान किया गया है। उसका कार्य प्रगति पर है और माननीय मुख्य मंत्री चंद दिनों में उसका उद्घाटन करेंगे। हमारे नाहन शहर में सबसे ज्यादा पीने के पानी की समस्या है। उसके लिए पहले भी रेणुका चुनाव क्षेत्र के नहर सवार नामक स्थान से एक बहुत बड़ी स्कीम नाहन सिटी के लिए बनी है परंतु वह इस वक्त कम पड़ रही है क्योंकि वहां पर पोपुलेशन ज्यादा हो गई है। उसके बाद रेणुका गिरि नदी से 7 बोर करके 53 करोड़ रुपये की एक नई डी.पी.आर. तैयार की गई है। उसके ऊपर लगभग 22 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा। पांवटा साहिब के लिए सिवरेज सिस्टम की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई गई है जिसके लिए ढाई करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है। हमारे सिरमौर जिले में जो भूमिहीन लोग थे उनमें 11 लोगों को पिछले टूअर के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तीन-तीन बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाई। मैं यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने पिछली केबिनैट की मीटिंग में मेरी नौराधार पी.एच.सी. को सी.एच.सी. का दर्जा दिया है। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि कौशल विकास भत्ते में

3.3.2016/1505/av/ag/2

सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हुई है। मैं उसके लिए अपने जिले के सभी लोगों को बधाई देता हूं। उसके लिए लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अभी पीछे पांवटा साहिब में 29.30 करोड़ रुपये की लागत से राज्य बिजली बोर्ड के डिजास्टर सैंटर का निर्माण किया गया तथा उसका उद्घाटन हो चुका है। वहां माननीय पठानिया जी भी साथ आए थे। हमारे यहां कुल 228 पंचायतें हैं जिसमें से 226 पंचायतें सड़कों से जुड़ी हुई है। केवल दो पंचायतें शेष रहती है मगर उनके लिए भी सड़कों का काम चला हुआ है। इसके अतिरिक्त नाहन में एक शूटिंग रेंज खोली गई है जिसके लिए 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारे जिले में ऐसी बहुत सारी योजनाएं चली हुई है। यहां बहुत सारी बातें प्रश्न काल के

दौरान भी हुई है जैसे अधूरे भवनों का उद्घाटन, अधूरी स्कीमों का उद्घाटन। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इन अधूरे भवनों के उद्घाटन की रीत आप लोगों ने शुरू की है। यह भाजपा की सरकार ने शुरू की है। हमारे पूर्व सी.पी.एस.; मैं उनको बोलता रहा। मेरे अपने गांव में रजाना रैस्ट हाउस में दरवाजे नहीं लगे थे। उसके अंदर फर्नीचर और पर्दे नहीं थे। उसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ था तथा उसकी छत रीस रही थी।

टी सी द्वारा जारी

03.03.2016/1510/TCV/AG/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री विनय कुमार) ----- जारी

मैंने उसका विडियो बनाया भी और दिखाया भी। मैंने कहा इसका उद्घाटन आपसे ही करवाएंगे लेकिन अभी इसका कार्य तो पूरा होने दो, कम से कम दरवाज़े तो लगने दो, लेकिन दरवाज़े तक नहीं लगने दिए और रेस्ट हाऊस का उद्घाटन कर दिया। माननीय महेन्द्र सिंह जी आप मेरे चुनाव क्षेत्र में आए। आपने मेरे दो ऐसे रोड़ों का उद्घाटन किया जिसमें आप स्वयं शरीक नहीं थे। लेकिन आज भी फट्टे आपके नाम से लगे हैं। मेरे स्वर्गीय पिता श्री प्रेम सिंह जी जब विधायक थे, एक भराड़ी गांव है, ठाकुर साहिब वहां पहुंच गये और जब इधर-उधर देख रहे थे तो इनको एक मन्दिर दिखाई दिया। इन्होंने पूछा कि यह कौन-सा मन्दिर है? लोगों ने बताया कि यह शिरगुल महाराज का मन्दिर है। इन्होंने कहा कि 'मैं शिरगुल महाराज जी की कसम खाता हूं कि इस सड़क को मैं भराड़ी से संगड़ाह पहुंचा दूंगा'। लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनी है और इन्होंने शिरगुल महाराज की कसम खाई है। पिछली सरकार ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र और जिला के बहुत सारे स्कूल डी-नोटिफाई कर दिए थे। मैं सरकार का और माननीय वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करूंगा कि बाद में इन्होंने उन स्कूलों को नोटिफाई किया और फिर से मेरे चुनाव क्षेत्र के 9 स्कूल दोबारा खोले गये। साईंस क्लालिसज़ और कॉमर्स क्लासिज़ हमारे कॉलेज में नहीं थी। वह भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने करवाई। अभी बहुत सारी वैकेंसिज़ पी0एच0सी और सी0एच0सी0 में थी, जिनको अब भर दिया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी का

धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय परिवहन मंत्री श्री बाली जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे चुनाव क्षेत्र के लिए दो बसें एक संगड़ाह से शिमला और दूसरी संगड़ाह से चंडीगढ़ के लिए लगाई। मैं यहां मान्य सदन को बताना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग बहुत गरीब हैं और इलाज़ के लिए उन्हें या तो शिमला आना पड़ता है या फिर चण्डीगढ़ जाना पड़ता है। लेकिन अब बस की सुविधा होने से वह सुबह आते हैं और शाम को वापिस लौट जाते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी पिछले दिनों जब प्रवास पर संगड़ाह आये थे तो उन्होंने रेणुका चुनाव क्षेत्र में एक आई0टी0आई0 हमें दी है। मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एस0एम0सी0 के तहत हमारे सिरमौर जिला में कम से कम 310 बेरोज़गार युवा

03.03.2016/1510/TCV/AG/2

को लगाया। एस0एम0सी0 पॉलिसी से हमें दो तरह के फायदे हुए हैं। एक तो हमारे जो बेरोज़गार युवा है,उनको अपने घर में नौकरी मिली है और दूसरा हमारे जो बच्चे हैं, उनको टीचर मिला है। पर्यटन की दृष्टि से हमारे सिरमौर जिला में अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से अगर हमें अपने जिला को विकसित करना है तो उसके लिए सबसे पहले सड़कों का ठीक होना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछली सरकार ने जो हमारी दो मुख्य सड़कें थी उन दोनों को डिमोट कर दिया था। इनमें एक सोलन-मिन्स जो दो स्टे्टों को कनैक्ट करती है और यह बहुत मेन रोड़ हैं। ये रोड़ स्टे्ट हाईवे था। इसे डिमोट किया गया। आज की डेट में ये एम0डी0आर0(मेजर डिस्टिक्ट रोड) है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा----जारी

3.03.2016/1515/RKS/AS/1

श्री विनय कुमार (मुख्य संसदीय सचिव)क्रमागत...

दूसरा कालाअम्ब, ददाऊ, चोपाल रोड़ बहुत अच्छा रोड़ है। इस रोड़ से लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। पिछली सरकार द्वारा इस रोड़ को भी डिमोट किया गया। ये भी

एम.डी. आर. है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन दो रोड़ों को किसी प्रोजैक्ट में लाया जाए ताकि जो हमारे क्षेत्र में पर्यटन की संभावना है उसको गति मिल सके। चूड़धार में ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। चूड़धार में आधे रास्ते तक लगभग 18 -20 किलोमीटर का पैदल रन है। उसमें 6-7 किलोमीटर तक सड़क बन जानी चाहिए। उसके बाद फॉरेस्ट का एरिया है। लोगों को सड़क बनने से बहुत सुविधा मिलेगी। हमारे चुनाव क्षेत्र में वाईल्ड लाइफ सैंक्चयूरी एरिया है, उसमें से कुछ एरिया चूड़धार का डीलीट हुआ था। हमारा देवना गांव अभी भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चयूरी एरिया में है। मैंने मुख्य मंत्री महोदय और वन मंत्री को इसके बारे में लिख के भी दिया है। रेणुका जहां झील है, उसका जो सराऊंडिंग एरिया है उसको भी इस वाइल्ड लाईफ सैंक्चयूरी एरिया से डीलीट किया जाए। ताकि जो वहां पर टूरिज्म से संबंधित एक्टिविटीज हैं, वह हम लोग कर सकें। लॉयन सफारी रेणुका की बहुत मशहूर थी। वहां पहले 18-20 शेर हुआ करते थे। एक-एक करके वे सारे शेर खत्म हो गए। आज वहां कोई भी शेर नहीं है। इस मैटर को नेशनल जू अथॉरटी से भी हमने टेकअप किया था। मेरा वन मंत्री जी से निवेदन है और आपने पिछे भी आश्वासन दिया था कि एक टाईगर का पेयर वहां पर लाया जाएगा। ताकि जो बाहर से पर्यटन, सैंक्चयूअरी एरिया को देखने के लिए आते हैं, लॉयन सफारी को देखने के लिए आते हैं वह खाली पड़ी है। लोगों को वहां कुछ देखने को नहीं मिलता। मैं विपक्ष से भी निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि सेंटर में आप लोगों की सरकार है। हमारा जो रेणुका डैम प्रोजैक्ट है, वैस तो यह प्रोजैक्ट छोटा सा है। 40 मेगावाट का प्रोजैक्ट है। इसमें सारी क्लीयरेंसिज हो चुकी है। ग्रीन ट्रिब्यूनल की भी क्लीयरेंसिज हो चुकी है। इसका जो केस है वह बिल्कुल तैयार पड़ा

3.03.2016/1515/RKS/AS/2

हुआ है। परन्तु कोई भी पैसा सैंटर से उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह बहुत मेन मुद्दा है। रेणुका डैम प्रोजैक्ट से पानी दिल्ली पहुंचना है। इसमें माननीय मुख्य जी ने भी पहल की

थी, पत्र लिखा था और माननीय सुजान सिंह पठानिया जो मंत्री है, ये स्वयं सैंटर में मिनिस्टर को मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था। कैबिनेट नोट भी पड़ा है। परन्तु पता नहीं मामला कहां रुका पड़ा है? मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, माननीय धूमल साहिब से भी निवेदन है कि रेणुका प्रोजैक्ट का कार्य तेजी से प्रारम्भ करवाया जाए। यहां बहुत सारी उपलब्धियां ओर भी हैं पर मैं समझता हूं कि सभी भाई लोगों का समय मिलना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

उपाध्यक्षः Thank you. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर।

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

03.03.2016/1520/SLS-AS-1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं भी अपने स्थान पर खड़ा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातः काल जब ठाकुर महेन्द्र सिंह जी अपनी बात रख रहे थे उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी तथ्यों को सुनकर इतनी बौखलाहट में आ गए कि जाते-जाते न जाने क्या कुछ कह गए जिससे ऐसा लगा कि सदन से वॉकआऊट कर रहे हैं। इसी तरह गत वर्ष मनाली के विंटर कार्निवॉल में माननीय मुख्य मंत्री जी आए थे। हडिम्बा माता के मंदिर के सामने मैं भी उनका स्वागत करने के लिए खड़ा था। मैंने गुलदस्ता लिया था। वह गाड़ी से उतरे। मनाली का विधायक होने के नाते मैंने कहा कि मैं यहां पर आपका अभिनंदन करता हूं और उनको गुलदस्ता दिया। उन्होंने मेरा गुलदस्ता पकड़ा नहीं और कहने लगे कि यहां तो गुलदस्ता दे रहे हो लेकिन विधान सभा में उछल-उछल कर नारे बोलता है। उपाध्यक्ष महोदय, आखिरकार तब तो क्या होना था। मैंने कहा कि आप राजा हैं तो मैं भी ठाकुर हूं। तब तो जो बात होनी थी हो गई। उसी पर मैं दो लाइने ज़रूर कहूंगा -

सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है,

मगर जब गुफ्तगु करता है तो चिंगारी निकलती है,
लबों पर मुसकराहट दिल में बेजारी निकलती है,
बड़े लोगों में ही अक्सर ये बीमारी निकलती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस माननीय सदन में चर्चा चली है। राज्यपाल का यह अभिभाषण सरकार के द्वारा पेश किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। केवल मात्र पहला पैराग्राफ है जिसमें यह कह सकते हैं कि उसमें ठीक लिखा है। आखिर में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि प्रदेश के लोगों का जीवन सुखी और संपन्न हो, यह शुभ-कामनाएं देता हूं। इसके अतिरिक्त यह सब-का-सब झूठ का पुलिंदा है।

ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। प्रदेश की जनता ने बड़े उत्साह के साथ इन पंचायत चुनावों में भाग लिया और 58% महिलाएं जीत कर आईं।

(श्री सुरेश भारद्वाज जी सभापति के रूप में पदासीन हुए)

03.03.2016/1520/SLS-AS-2

सभापति महोदय, आखिरकार जनता ने कितने उत्साह से भाग लिया, यह जानकारी मैं आपको देता हूं। पहली बार कुल्लू जिला के मनाली विधान सभा क्षेत्र की 4 ग्राम पंचायतों के लोगों ने इन चुनावों का बहिष्कार किया। उस बहिष्कार का नेतृत्व अगर कोई कर रहे थे तो जो स्वयं को मुख्य मंत्री जी का बहुत घनिष्ट कहते हैं, वह थे। जब भी आप आते हैं वह साथ-साथ रहते हैं। वह सब लोग गांव-गांव में जाकर यह चर्चा कर रहे थे कि आज मनाली की 4 पंचायतें, पूरा ब्लॉक और पूरा कुल्लू जिला ग्राम पंचायत चुनावों का बहिष्कार करेगा। सभापति महोदय, ऐसे समय में मैने स्वयं वहां का विधायक होने के नाते लोगों को इकट्ठा कर पत्रकार वार्ता करके लोगों को यह कहा कि लोकतंत्र में आस्था रखिए। सरकार से जो नाराजगी है वह होगी, लेकिन चुनावों में पार्टिसिपेट कीजिए। पूरे जिले में ग्राम पंचायत चुनावों का बहिष्कार न हो, इस दिशा में मैंने काम

किया। अब ये कहते हैं कि कितने उत्साह से काम किया। इनका अपना उत्तर है जो इन्होंने कहा है कि NGT के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए ठीक प्रकार से आवाज नहीं रखी। इसलिए जनता ने सरकार के विरुद्ध होकर कहा कि हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। तो कितना उत्साह? फिर यह भी कहा गया कि पंचायतों के अंदर 76% लोग कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए।

जारी ...गर्ग जी

03/03/2016/1525/RG/DC/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर-----क्रमागत

सभापति महोदय, अब कुल्लू जिले का थोड़ा सा दृश्य देखें। जिला परिषद के 14 वाड्र्ज हैं। 8 में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते, एक हिलोपा से जीते, एक सी.पी.आई.एम. का उम्मीदवार जीता, एक इंडिपैडेंट जीता और 14 में से कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत थे वे तीन ही जीते। कुल्लू जिले के पांच विकास खण्डों में से नगर विकास खण्ड, बन्जार विकास खण्ड, आनी और निरमण्ड, पांच विकास खण्डों में से चार विकास खण्डों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। यानि बिल्कुल सीधा-सीधा झूठ का पुलिन्दा खुल गया। एक बात और है कि हमने बहुत उत्साह से पर्टिसिपेट किया। आखिरकार मुझे लगता है कि किन लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई? इसी विधान सभा में मेरा एक प्रश्न था, मैंने पूछा था कि कुल्लू जिले में ग्राम पंचायत के चुनावों में कुल कितने सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों की डियुटी लगी थी? तो मुझे जो यहां जवाब दिया गया उसमें कहा गया कि 2709 लोगों को डियुटी पंचायत चुनावों को करवाने के लिए सौंपी गई थी। हमने यह भी पूछा था कि उन सब पढ़े-लिखे लोगों में से कितने लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, तो सरकार का जवाब है कि 1364 कर्मचारियों-अधिकारियों ने अपने मत का प्रयोग किया। यानि 1465 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से

चाहूंगा कि इस बात की जांच होनी चाहिए। लगभग 60% अधिकारी-कर्मचारी जिन अधिकारियों की मनमानी से अपने मत का प्रयोग लोकतंत्र में नहीं कर पाए, तो यह कहां तक न्याय है?

सभापति महोदय, आखिरकार मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हूं। कहने के लिए बहुत कुछ है। एक बात हम अक्सर कहते हैं कि भून्तर-कुल्लू के एयरपोर्ट पर नाइट लैण्डिग होनी चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए। श्री सुधीर शर्मा, माननीय शहरी विकास मंत्री जी अध्यक्षता में अनेक बैठकें होती हैं और जवाब भी आता है। लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक बात जो हमको बताई गई कि इसके विस्तारीकरण के लिए केन्द्र सरकार ने माना है कि विस्तार करने के लिए जितनी राशि है, हम उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन भूमि का प्रबन्ध प्रदेश सरकार करके दे। जो प्रदेश की सरकार को करना है कि इसमें लगभग 350 बीघा भूमि आनी है जिसमें 270 बीघा निजी भूमि है। मेरा इस सरकार पर यह आरोप है कि कुल्लू जिले में पंचायत चुनावों में श्री वीरभद्र सिंह जी को जो दर्शन करा दिए हैं। लगता है कि हमसे अनदेखा, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जिस पर कोई 250 करोड़ रुपये खर्च होने हैं।

03/03/2016/1525/RG/DC/2

वह केवल मात्र कुल्लू जिले के लिए ही नहीं है, रोहतांग तक अगर सबसे अधिक पर्यटक देश और दुनिया का आता है, तो कुल्लू जिले से होकर आता है। लेकिन प्रदेश सरकार ने 250 करोड़ रुपये का प्रबन्ध करने से इनकार किया। इसलिए हमसे सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

सभापति महोदय, सन् 2010 में हमने 50 करोड़ रुपये का टूरिजम मेगा प्रोजैक्ट स्वीकृत करवाया था जिसके लिए डी.पी.आर. बनाने के लिए वर्ष 2012 में सरकार को कहा। कुछ पैसा आया है जिसमें 33 करोड़ रुपये की मंजूरी प्राप्त हो चुकी है। पर्यटन विभाग ने अभी तक उस 33 करोड़ रुपये को खर्च करने के लिए इनको कहा है कि डी.पी.आर. बनाकर भेजो। लेकिन कोई भी डी.पी.आर. बनाकर नहीं भेजी है।

सभापति महोदय, एक विषय और है, ये कहते हैं कि वृद्ध और गरीब आदमी का ये ध्यान रखते हैं। मैं तो यहां इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि कुल्लू-मनाली में छोटा कारोबार करने वाले सबके सब लोग इस सरकार ने बेराजगार कर दिए हैं। कुछ महीने पहले जब

मुख्य मंत्री जी ने जो लोग अपने विधान सभा क्षेत्रों में चुनाव जीत नहीं सकते, ऐसे चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन की फौज खड़ी कर दी है। उनके पास काम कोई नहीं होता। कहीं भी जाते हैं, घूम आते हैं, कुल्लू-मनाली की सैर कर आते हैं और तुगलकी फरमान जारी करके आते हैं। मैं एक दिन मनाली गांव में गया, वहां करीब सौ लोग मेरे पास आए। मैंने कहा कि क्या करते हैं, तो कहने लगे कि मैं पट्टू लगाने का काम, किसी ने कहा कि मैं रीवर क्रॉसिंग का काम करता हूं, किसी ने कहा कि मैं बूट बेचने का काम करता हूं,

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2016/1530/MS/AG/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जारी-------

कोई कहता है कि मैं पट्टू बुनने का काम करता हूं, मैं रिवर राफ्टिंग का काम करता हूं, मैं बूट बेचने का काम करता हूं और किसी ने कहा कि वह लाठी बेचने का काम करता है। उन्होंने बताया कि अभी दो-चार दिन पहले वाइस चेयरमैन श्री हरीश जनार्था जी शिमला से यहां आए थे और वे क्लब हाउस के बाहर ताला लगवाकर चले गए कि इसके आगे कोई नहीं जाएगा। जो लोग कई सालों से वहां बैठकर रोजी-रोटी कमाते थे वे अब मुश्किल में आ गए हैं। सभापति महोदय, मैं वहां का विधायक हूं। मैं स्वयं लोगों को लेकर वहां गया। हमने वहां कहा कि या तो तुम ताला खोलो नहीं तो हम ताला तोड़ देंगे और अगर एफ0आई0आर0 लॉज करनी है तो कर लो। तब जाकर उन्होंने कार्रवाई शुरू की। मनाली के साथ लगते वन विभाग के जंगल में 200-250 परिवार, जिनमें कोई जुराबें बेचने का काम करता है तो कोई मफलर इत्यादि बेचने का काम करते हैं। वहां पर भी आजकल सुना है कि गेट पर ताला लगा दिया है। उसमें कहते हैं कि वन विभाग के अधिकारी ने किया है और अधिकारी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के ऑर्डर हैं। कोई

जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आखिरकार इसका कौन बेली-वारिस है? इसको कौन सम्भालने वाला है?

यहां पर सुजान सिंह पठानिया जी बैठे हैं। मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैंने यह बात प्लानिंग की मीटिंग में भी कही लेकिन मुख्य मंत्री जी सुनने को तैयार नहीं थे। माननीय मुख्य मंत्री जी तीन साल से विंटर कार्निवाल में आ रहे हैं और हर बार एक घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि इस क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए बिजली बोर्ड के प्रीणी सब-स्टेशन को ए0डी0 हाइड्रो के सब-स्टेशन से जोड़ेंगे और पहले बिजली कुल्लू जिला को मिलेगी, फिर बाहर जाएगी। तीन साल से ऐसा बोल रहे हैं लेकिन अभी तक आगे कोई बात बढ़ी नहीं है। जब मैंने इस बार पूछा तो कहते हैं कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। सुजान सिंह पठानिया जी आपके अधिकारी हर बार यह एनाऊंसमैंट क्यों करवाते हैं? मुख्य मंत्री जी से एनाऊंसमैंट आप करवाते हैं। मैंने कहा कि मैं बीजेपी का विधायक हूं मेरे कहने पर आप एनाऊंसमैंट करने वाले

03/03/2016/1530/MS/AG/2

नहीं है। लेकिन आपके लोग एनाऊंसमैंट क्यों करवाते हैं? सोजल में 100 मैगावाट बिजली के सब-स्टेशन का आदरणीय धूमल जी ने वर्ष 2011 में शिलान्यास किया था। आज तक यह सरकार जिसके पांच साल बीतने को हैं उसको प्रारंभ नहीं कर पाई है क्योंकि ए0डी0 हाइड्रो जैसी प्राइवेट कम्पनियों के प्रभाव में यह सरकार रहती है। इसीलिए माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि या तो सरकार और मुख्य मंत्री जी ये एनाऊंसमैंट्स करना बन्द कर दें या इन कामों को करे।

जहां तक सड़कों का संबंध है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि अब कुल्लू-मनाली में पर्यटक सीजन प्रारंभ होने वाला है और साथ-साथ में अब सेब का सीजन भी शुरू होने वाला है। लेकिन हमारे लैफ्ट और राइट बैंक की सड़कों की दशा ऐसी है कि जब

भी पर्यटक आता है तो वह कहता है कि कुल्लू-मनाली को घूमने लायक बनाने के लिए करें तो क्या करें? जहां पर आपके ग्रीन टैक्स बैरियर्ज लगे हैं जिनसे एक साल में 4-4 और 5-5 करोड़ रुपये इकट्ठा हो रहे हैं उन ग्रीन टैक्स बैरियर्ज के पास ही सबसे ज्यादा उखड़ी हुई सड़के हैं। ये छोटी-छोटी बातें आखिरकार बतानी किसको है और करवानी किसने है?

सभापति जी, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का प्रश्न है उसमें भी ठीक वही बात है। नवोदय स्कूल का भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ। पॉली टैक्निक कॉलेज का काम वर्ष 2011 में प्रारंभ हुआ और अब बनकर तैयार हो गया है। आई0टी0आई0 की वर्ष 2013 में नोटिफिकेशन हुई लेकिन आई0टी0आई0 अभी किराये के भवन में चल रही है क्योंकि इसके भवन के लिए पैसे का प्रबंध यह सरकार नहीं कर पाई है। आज ही मेरा इस सदन में एक प्रश्न था कि दलाश और निरमण्ड की आई0टी0आइज0 की भी चर्चा करो। तो विधान सभा में प्रश्न का उत्त

र आया है कि दलाश की आई0टी0आई0 वर्ष 2007 में प्रारंभ हुई लेकिन अभी तक भूमि उसके नाम नहीं है। निरमण्ड की आई0टी0आई0 वर्ष 2011 में बनी है लेकिन वह भी अभी तक किराये के मकान में है। यानी यह सरकार किसी भी काम को तेज गति से करने में विश्वास नहीं रखती। मैं श्री जगजीवन पाल जी और राजेश धर्माणी जी, इन दोनों मित्रों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा कुछ भी करो लेकिन जिस तरह से धर्माणी जी ने आज कहा कि नाथू राम गोड़से से संबंध है, आखिरकार ये सब की

03/03/2016/1530/MS/AG/3

सब बातें आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा था, उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधान मंत्री होते हुए वह भी समाप्त हो गया था और न्यायालय ने यह कहा था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का इससे कोई संबंध नहीं। महात्मा गांधी राष्ट्र पुरूष थे राष्ट्रपिता थे और आज ही

तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री के हत्यारों को क्षमा करो। लेकिन केन्द्र में हमारे गृह मंत्री ने कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

03.03.2016/1535/जेएस/एजी/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः------जारी------

हम उसी पर टिके रहेंगे। अफज़ल गुरू को फांसी हुई है। उस समय यू0पी0ए0 की सरकार थी। अफज़ल गुरू ने पार्लियामैंट पर हमला किया था। आज लगता है कि जो अफज़ल गुरू की वकालत कर रहे हैं, मित्रों, अगर वे उस हमले में कामयाब होते तो कम से कम 40-50 लोग आज नहीं होते। हम राजनीतिक तौर पर कोई भी बात करें लेकिन इस देश के अन्दर अगर कोई भारत माँ की जय करता है। अगर भारत में रहना होगा तो वन्दे मातरम कहना होगा। यह कोई साम्प्रदायिक नहीं है। हम सब लोग कहते हैं। लेकिन मैं उसकी वकालत नहीं करता। अगर देश के न्यायालय ने कहा है कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकद्दमा दर्ज़ हो, अरविन्द केज़रीवाल पर देशद्रोह का मुकद्दमा दर्ज़ हो तो मित्रों कम से कम कुछ बातों के लिए राजनीति से हट कर चलो, वरना हम इन बातों में लगे रहेंगे। आखिर भारत माँ किसकी है, हम सब की है। इसलिए मुझे लगता है कि हम अपनी राजनीति करने के लिए कम से कम इन बातों के बारे में सोंचे। यह ठीक है कि राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा और सरकार का जितना स्तुतिगान करना है, आप करें। लेकिन कम से कम देश व धर्म के संबंध में और आखिरकार यह देखिये कि आज ही वट्सऐप पर एक संदेश आया था, एक अंग्रेज ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम पहली बार भारत पर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जब यहां पर राज़ करना प्रारम्भ किया और जब हमारा जुलूस चल रहा था भारत के लोग भी हमारा स्वागत करने के लिए तालियां बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भी भारत के अन्दर वही समय है। क्या लगता है कि कौन क्या करने आया है? न्यायालय जो फैसला करेगा वह करेगा, लेकिन देश के विरोध में इस तरह से कोई भी करेगा और मैं तो यह कहता हूं कि ऐसा देशद्रोही, चाहे वह हिन्दू धर्म का है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है

और कोई भी देशद्रोही है, धर्म के नाम पर नहीं लेकिन केवलमात्र एक भारत माँ की वन्दना करता हुआ उसे अपनाए। लेकिन धर्म के नाम पर कुछ नहीं। इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई

03.03.2016/1535/जेएस/एजी/2

यह बिल्कुल सीधा-सीधा झूठ का पुलिंदा है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी इसी प्रकार से है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अभी यहां पर नहीं है। मनाली का अस्पताल जहां पर दुनिया के लोग प्रतिवर्ष आते हैं, आज भी वहां पर सर्ज़न नहीं है, गाईनोक्लोजिस्ट नहीं है और प्राईवेट अस्पतालों की ओर दौड़ना पड़ता है। हमने कहा था कि साथ में लगते 7 बीघा भूमि को स्वास्थ्य विभाग के नाम करो। आज तीन साल के बाद एक ही ज़वाब आता है मामला विचाराधीन है। कब मामला विचाराधीन होगा और कब काम करेंगे। उसी तरह से अभी एक और मामला है। हम कहते थे कि मनाली और कुल्लू में आग बहुत लगती है । मनाली और कुल्लू के मध्य पतली कूहल में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करो। लेकिन इस सरकार का एक पत्र आया है कि वर्ष 2015 के मुताबिक विभाग ने लिखा है कि सरकार ने उसे निरस्त कर दिया है कि पतली कूहल में अग्निशमन केन्द्र नहीं बनाएंगे। सभापति महोदय, कहने के लिए अनेक विषय थे, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण से अभी जो आपके ध्यान में लाने का प्रयास किया है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां पर आयुर्वेदिक अस्पतालों में हमारे लगभग 12 डॉक्टर्ज़ की कमी है। मनाली के अस्पताल में हमें गाईनोक्लोजिस्ट, सर्ज़न की व्यवस्थता की जाए। इसके अतिरिक्त और कई बातें हैं। इसी के साथ मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं कि पिछले तीन साल से कुल्लू जिला में हाईड्रो प्रोजैक्ट मलाणा-॥ की लोकल एरिया डवैल्प्मैंट अथौरिटी लाडा की कोई मीटिंग नहीं। आज का मेरा प्रश्न था और इन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में लाडा के अन्तर्गत 270 करोड़ रूपये आने है जिसमें से 150 करोड़ रूपया आ चुका है। 125 करोड़ रूपया खर्च हो चुका है। मुझे लगता है कि किस के कहने पर 125 करोड़ रूपया कहां-कहां पर खर्च हुआ, यह सब का सब कहीं न कही जांच का विषय है। सरकार व अधिकारियों ने यह किस माध्यम से किया, कैसे टेण्डर हुए? 125

करोड़ रूपये की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात को रखने का मौका दिया। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। यह झूठा दस्तावेज़ है और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एसएस द्वारा जारी---

03.03.2016/1540/SS-AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टाः माननीय सभापति महोदय, जो यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने 25 फरवरी, 2016 को अभिभाषण दिया, जिस पर हमारे माननीय सी0पी0एस0 महोदय, श्री जगजीवन पाल जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और जिसका अनुमोदन माननीय सदस्य, श्री अजय महाजन जी ने किया, मैं भी अपने आपको उस पर बोलने के लिए शामिल करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुझसे पूर्व काफी वक्ता, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बोल चुके हैं। जैसे कि विपक्ष की ओर से जितने भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है उन सब का कहना है कि जो भी राज्यपाल महोदय ने 25 तारीख को अपना अभिभाषण इस माननीय सदन में रखा, उसमें सरकार की बिल्कुल झूठी उपलब्धियां हैं। वह वेस्ट पेपर है और राज्यपाल महोदय से सरकार ने झूठ बुलवाया है। यह विपक्ष का तर्क बिल्कुल गलत है। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। मैं कड़े शब्दों में इनकी बातों की निन्दा करता हूं। यह बात ठीक है कि विपक्ष का काम अपोज करना होता है लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि वह हर फील्ड में हो, हर क्षेत्र में हो। हर जगह अपोज ही करें। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि तीन साल में जो हमारी कांग्रेस की सरकार है उसमें कोई काम नहीं हुआ। सरकार ऐसे ही चली हुई है। मैं इन बातों की कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं। वह बात अलग है कि इनका काम अपोज करना है लेकिन जो बात अच्छी है जो तीन साल में हमारी सरकार द्वारा विकास के कार्य हुए हैं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। इनकी कांस्टीचुऐंसी में भी काम हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस एम0एल0ए0 की कांस्टीचुऐंसी में ही काम हुए हैं और इनके क्षेत्रों में काम नहीं हुए हैं, यह बात बिल्कुल गलत है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में बताना चाहूंगा कि जहां तक

राजा वीरभद्र सिंह सरकार की बात है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं हुआ। न ही किया और न ही करती है। पूरे प्रदेश में हर विधान सभा कांस्टीचुऐंसी में विकास हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहां पर पंचायती राज चुनाव का ज़िक्र हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि जो इस बार पंचायती राज के चुनाव हुए, वे बड़े शांतिपूर्ण हुए। मुझ से पूर्व विपक्ष के एक सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाले 70-80 परसैंट प्रतिनिधि पंचायत समिति में आए हैं। मैं कहता हूं कि वे अवश्य आए हैं।

03.03.2016/1540/SS-AG/2

More than 80 per cent पूरे प्रदेश में कांग्रेस विचारधारा वाले लोग पंचायती राज चुनाव में आए हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र रोहड़ू की बात कहूंगा कि वहां पर 95 परसैंट से ऊपर आये हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में चार सीटें जिला परिषद् की हैं। उन चारों सीटों पर कांग्रेस विचारधारा के उम्मीदवार आए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं। उन दोनों में हमारी कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोग चेयरमैन बने हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2016/1545/केस/एजी/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी----

इसी तरह चाहे प्रधान हो या उप प्रधान हों या सरपंच की बात करें, 95 प्रतिशत से ऊपर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार आए हैं। इसका श्रेय राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री है। साथ ही यह भी गौरव की बात है कि इस बार पंचायती राज चुनाव में लगभग 58 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन में बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में सभी वर्गों का समान विकास करती है और चहुंमुखी विकास हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो चुनावी वायदे किए थे, तीन साल के इस कार्यकाल में तकरीबन सभी पूरे किए गए हैं। इसके अलावा हमारी सरकार ने

एस.सी.,एस.टी., ओ.बी.सी. के उत्थान के लिए काफी कार्य किए हैं। जहां तक सोशल सिक्योरिटी पैंशन की बात है, 80 साल से ऊपर और 70 प्रतिशत डिसेबल्ड के लिए 1100 रुपये प्रति महीना पैंशन की गई है जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के इस कार्यकाल में हाऊस रिपेयर के लिए 25 हजार से 75 हजार रुपये बढ़ा दिए गए हैं जिसमें करोंड़ों रुपयों का खर्च हुआ है और सैंकड़ों लोगों को इसका फायदा हुआ है। लगभग 1280 बेघर लोगों को इसका फायदा हुआ है। मैं राजा वीरभद्र सिंह जी को, कांग्रेस सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण पर भी करोड़ों रुपये का खर्च हुआ है। बेटी है अनमोल स्कीम के तहत भी 300 से 1500 रुपये और 450 से 2200 रुपये प्रत्येक को दिया गया है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जहां तक ऐजुकेशन की बात है, इस पर इस माननीय सदन में काफी डिटेल में चर्चा हुई है । पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से इस बारे में बात हुई है। तीन साल का जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल रहा है इसमें लगभग 21 प्राईमरी स्कूल नए खोले गए हैं।

03.03.2016/1545/केस/एजी/2

कम से कम 21 प्राईमरी स्कूल मिडल स्कूल में अपग्रेड किए गए । 92 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है । 58 हाई स्कूलों को प्लस टू में अपग्रेड किया गया है। मैं कांग्रेस पार्टी और माननीय राजा साहब को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने इन तीन सालों में 7 नए कॉलेज खोले हैं जिसमें एक फाईन आर्ट कॉलेज भी शामिल है। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में सैंकड़ों भर्तियां हुई है और कई रिक्तियां भरी गई है। 6 नए आई.टी.आई. खोले गए हैं। हर चुनाव क्षेत्र में तकरीबन एक-एक आई.टी.आई. खोली गई है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.3.2016/1550/av/as/1

मोहन लाल ब्राक्टा----जारी

इसके अतिरिक्त 13 नये मोडल स्कूल भी इसी दौरान खोले गये हैं। यहां पर पीलिया पर काफी चर्चा हुई है, खासकर जो हमारे शिमला शहर में फैला था। उस पर अब सरकार काफी हद तक कंट्रोल कर चुकी है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हैल्थ से सम्बंधित बातें भी की थी। मैं इसमें यह बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तीन साल के कार्यकाल में 8 सिविल हॉस्पिटल खोले हैं, 16 पी.एच.सी., और चार हैल्थ सब सैंटर हैं। जिनमें लगभग 266 नये डॉक्टर्ज की भर्ती की गई है तथा साथ ही दूसरे पैरा मैडिकल स्टाफ की भर्ती भी गई गई है। हमारी सरकार ने मैडिकल कॉलेजिज में टीचिंग स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए वहां पर तैनात प्रोफैसर्ज की सेवानिवृत होने की आयु सीमा 62 से 65 वर्ष कर दी है।

मैं अब प्रदेश से हटकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात भी करना चाहूंगा। मैं यहां पर कोई बात दोहराऊंगा नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि जहां तक हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी की बात है तो इन्होंने अपने तीन साल के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में विकास किया है। आप सभी जानते हैं कि इससे पूर्व माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार एम.एल.ए. और मुख्य मंत्री रह चुके हैं। जहां तक विकास की बात है तो रोहड़ू में चाहे डोडराक्वार से शील, सुंगरी से लेकर शेखल तक; यानि हर जगह विकास के कार्य किए हैं। यह बात अलग है कि विकास की कोई सीमा नहीं है। आज हमें प्राइमरी स्कूल की जरुरत है तो कल हम उसी को मिडिल बनाने की बात करेंगे। इन तीन सालों में मेरे रोहड़ू विधान सभा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। मैं माननीय वीरभद्र सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि पिछले साल पूरे भारत वर्ष में केवल पब्बर नदी की चेनेलाइजेशन की स्कीम ही पास हुई है। यह स्कीम लगभग 191 करोड़ रुपये की है। इस नदी का चेनेलाइजेशन दमवाड़ी से हाटकोटी तक होना है। यहां पर विपक्ष की ओर से कई बातें उठाई गई। मुझे हैरानी तब हुई जब कल यहां पर बंदरों से सम्बंधित एक प्रश्न

3.3.2016/1550/av/as/2

लगा था। बंदरों की बढ़ती हुई संख्या और उनके आतंक की चिन्ता में मैं भी अपने

आपको शामिल करता हूं। यह सही है कि यह एक चिन्ता का विषय है मगर यह कहना उचित नहीं होगा कि जो भी बंदर पकड़े जाते हैं उनको नसबंदी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से सम्बंधित एम.एल.ए. के निर्वाचन क्षेत्र में छोड़ा जाता है। यह एक दुख की बात है। ऐसी-ऐसी बातें की जाती है

टी सी द्वारा जारी

03.03.2016/1555/TCV/AS/1

श्री मोहन लाल बाक्टा ----- **जारी**

जो नहीं होनी चाहिए। बाकी उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी जो केन्द्रीय सरकार है, जिसमें हमारे माननीय प्रधान मंत्री मोदी साहिब हैं। उन्होंने भी इलैक्शन से पहले काफी सपने रखे थे। जिसमें 15-15 लाख रूपये हर आदमी के खाते में आएगा,अच्छे दिन आएंगे, काला धन वापिस लाया जाएगा और देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। जहां तक महंगाई की बात है जैसे श्री धर्माणी जी ने कहा कि जो दालें 40-50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलती थी वह आज 200-250 रूपये प्रति किलोग्राम मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव है। मैं ज्यादा न कहता हुआ अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने 25 फरवरी को जो अपना अभिभाषण यहां पर दिया है, जिसका श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव) ने इस मान्य सदन में प्रस्ताव रखा है और श्री अजय महाजन जी ने अनुमोदन किया है। मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूं। धन्यवाद । जयहिन्द।

सभापतिः धन्यवाद, माननीय सदस्य श्री ब्राक्टा जी, अब इस चर्चा में श्री जय राज ठाकुर जी भाग लेंगे।

03.03.2016/1555/TCV/AS/2

श्री जय राम ठाकुरः माननीय सभापति महोदय, इससे पहले कि हम अपनी बात इस

विषय पर आगे बढ़ायें। मैं देख रहा हूं, सत्ता पक्ष में केवल 8 लोग बैठें हैं। 12 में से 2 मंत्री हैं, जो इस सदन में उपस्थित हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष के लोग कितने गंभीर है। ऐसे परिस्थितियां हमने बहुत कम देखी है, जब सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस माननीय सदन में उपस्थित न हो। मुख्य मंत्री जी तो शायद लन्च के बाद इस माननीय सदन में उपस्थित ही नहीं हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में विषय पैदा होता है कि हमको अपनी बात कहनी भी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। जब सामने कोई सुनने वाली ही न हों। ऐसी परिस्थिति में हमें विधान सभा की कार्यवाही लिखकर दे देनी चाहिए। जो मुझे बोलना है, वह मैं लिखकर दे दूंगा और वह पहुंच जाएगा। इस मान्य सदन में इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस मान्य सदन में उपस्थित रहे। मंत्रियों से तो सीधे तौर पर हमारा प्रश्न होता है और उनसें हमें उम्मीद होती है कि जिन बातों की हम चर्चा करते हैं, उनका वह संज्ञान लें और उस पर रिस्पोंड करें। वे भी इस सदन में उपस्थित नहीं है। मुझे लगता है कि यह सचमुच में बहुत चिन्ता का विषय है। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस मान्य सदन में हमारे मित्र श्री जगजीवन पाल जी ने प्रस्तुत किया और श्री अजय महाजन जी ने जिसका समर्थन किया। मैं भी उसमें अपनी बात जोड़ने के खड़ा हुआ हूं। हमें इस बात को मानकर चलना चाहिए कि जब सरकार का एक साल का कार्यकाल होता है तो उपलब्धियां ज्यादा नहीं होती । लेकिन जब सरकार का कार्यकाल दो साल का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार की उपलब्धियों की गिनती ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो जाये तो उपलब्धियां और ज्यादा होनी चाहिए थी और अभिभाषण और लम्बा होना चाहिए था। जिसमें आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय अपनी बात सरकार के विकास के बारे में यहां पर प्रस्तुत करते। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय हुआ क्या? पिछले अभिभाषण इससे लम्बे थे, उसमें लम्बी कहानियां डाली हुई थी। परन्तु जैसे तीन साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

03.03.2016/1555/TCV/AS/3

24 पेज का रह गया। इसका अर्थ सीधा निकलता है कि कुछ कहने लायक नहीं है। कहने लायक इसलिए नहीं है, क्योंकि कुछ किया नहीं है। जब कुछ किया नहीं है तो कहेंगे कैसे? उपाध्यक्ष महोदय

श्री आर0के0एस0 द्वारा--- जारी

3.03.2016/1600/RKS/DC/1

श्री जय राम ठाकुर क्रमागत...

जहां तक सरकार का जो 3 साल का कार्यकाल बिता है, विकास कार्य शून्य के कगार पर है। ऐसी परिस्थिति में उम्मीद क्या करें? मैं यह कहूंगा कि वर्तमान सरकार शून्य की रफ्तार पर है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें कहने की कोशिश की और उन बातों में इन्होंने अपने आप प्रश्न खड़े कर दिए। जिन प्रश्नों का उत्तर ये अपने आप देने की स्थिति में नहीं हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हम देने की स्थिति में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं लम्बी बात न करते हुए अनिल शर्मा जी जो यहां बैठे हैं और अल्फाबैटिकली नाम भी यहीं से शुरू करना चाहिए। हमारे अच्छे मित्र हैं, जिले के हैं, साथी होते थे, इकट्ठा भी रहे हैं। यहां पर जिक्र हुआ कि हमने पंचायत का चुनाव बहुत सफलतापूर्वक करवाया। बहुत सी चीजों का यहां पर जिक्र हुआ। पंचायत के चुनाव को लेकर बधाईयों को तांता चला। कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक जो इस माननीय सदन में बोले हैं सभी लोगों ने बधाई दी। एक बात कही कि 58 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया। हमारे समय में तो 59 प्रतिशत महिलाएं थीं। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, जिसने 33 प्रतिशत से सीधा 50 प्रतिशत किया था। माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने सरकार बनने के पहले दिन इस बात की घोषणा की थी। यह श्रेय आप नहीं ले सकते। इसलिए मेहरबानी करके इस श्रेय को हमारे साथ रहने दीजिए। हमने 58 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं को पंचायत के माध्यम से, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते इस प्रदेश में काम करने का अवर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यदि थोड़ी ओर बातों का जिक्र करें तो एक बात आई कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं। जिसके लिए नई पंचायतों का गठन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। घोषणा कर दी । नेताओं ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर घोषणा कर दी। मुख्य मंत्री जी ने अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर पंचायत की

घोषणा कर दी, जो आज तक इस प्रकार से हुआ नहीं है। हमने कहा ठीक है। हम पिछली बार पंचायतें नहीं बना पाएं। शर्मा जी आप कहेंगे की आपने क्यों नहीं बनाई? हमने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि उस वक्त आपकी यू.पी.ए. की सरकार थी। यू.पी.ए. सरकार के अंतर्गत जब सेनशस डिपार्टमेंट ने जनगणना की

3.03.2016/1600/RKS/DC/2

प्रक्रिया शुरू की तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला। उस नोटिफिकेशन के अंतर्गतन उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोई भी रेवन्यू यूनिट और डवलेपमेंट यूनिट तब तक नहीं बनेगा जब तक हमारा जनगणना का काम पूरा नहीं होगा। इस कारण से हमार कार्य स्थगित हुआ। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगभग 200 पंचायतों को नई पंचायतें बनाने का प्रोपोजल आगे बढ़ चुका था। हमको उस कारण से रुकना पड़ा। लेकिन आपके सामने इस प्रकार की कोई मुश्किल नहीं थी। आपने कहा कि पंचायतें बनाएंगे। हमारे पास लोग आए, सभी विधायकों के पास आए कि हमारी पंचायत नहीं बननी चाहिए। आप भी लिख करके दीजिए। हमने भी लिखकर दिया। पंचायत के प्रतिनिधियों ने भी लिख करके दिया। लोगों का डेप्यूटेशन चला। परन्तु बाद में वह सारी प्रक्रिया रोक दी गई और कहा कि नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। दो कदम चले और दो कदम पीछे हट गए। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो पंचायतों में कहा कि जो रिजर्वेशन का रोस्टर लागू करेंगे उसको हम फुल प्रूफ करेंगे। फुल प्रूफ में कहा कि हमने सोफ्टवेयर डवेलप किया है। उसके माध्यम से एक बटन दबाकर हम रिजर्वेशन का कार्य पूरा करेंगे। वह सोफ्टवेयर बनाया भी गया। सोफ्टवेयर बनाने के बाद वहां कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई,

श्री एस.एल.एस. ... जारी

03.03.2016/1605/SLS-DC-1

श्री जय राम ठाकुर ....जारी

और उसके बाद शायद कैबिनेट में भी चर्चा हुई। अंततोगत्वा क्या हुआ? कुछ लोगों ने कहा कि अगर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होना है तो हम किस बात के लिए हैं, इसलिए इस बात को होने से रोकिए; पंचायत का आरक्षण किस प्रकार से होना है, इसमें थोड़ी हमारी भूमिका भी रखिए। फिर जो साफ्टवेयर बनाया गया था उसको डिसकार्ड और रिजैक्ट किया गया और कहा कि पहले जिस प्रकार से मैन्वल प्रक्रिया चलती रही, उसी प्रक्रिया के आधार पर आरक्षण लागू होगा। दो कदम चले और फिर दो कदम पीछे हटा लिए। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद आगे बढ़ें। कहा कि पंचायतों के जिला परिषद् वार्डों को हम रिआर्गेनाईज करेंगे। प्रक्रिया चली और लोगों ने प्रस्ताव दिए कि हमारी यह पंचायत इस जिला परिषद् के वार्ड में पड़ती है, हमे यह जिला परिषद् वार्ड सूट करता है। ऐसे प्रस्ताव इकट्ठे होने के बाद फिर कह दिया कि जिला परिषद् के वार्ड में कोई तबदीली नहीं होगी, ज्यों की त्यों रहेंगे। फिर वही दो कदम चले और दो कदम पीछे। मैं सरकार की स्थिति का ज़िक्र कर रहा हूं। सरकार की विकास की गति क्या है? दो कदम चलते हैं फिर दो कदम पीछे हटते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, फिर चुनाव आता है और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। कहा कि हमारा इस प्रक्रिया में दखल नहीं है। सरकार की ओर से सब नेताओं की ओर से यह ज़िक्र किया गया। लेकिन किस तरह का दखल था? हमने इस बात को महसूस किया। गोहर ब्लॉक में हमारा बहुमत था। यहां माननीय विधायक विनोद जी बैठे हैं। एक बी.डी.सी. का मैंबर है। उसकी पत्नी मैडिकल डिपार्टमैंट में सरकारी नौकरी करती थी। उसके आदेश धर्मपुर के कर देते। उसको कहा गया कि तुझे कहीं भी मिले, अपने पति को लाकर यहां खड़ा करो। मुख्य मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से भी फोन किए। मंत्री जी, इसको दखल न कहें तो क्या कहें? मैं सिराज ब्लॉक की बात बता रहा हूं। सिराज ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। फिर यहां शिमला से एक कौपरेटिव का इंस्पैक्टर जाता है। एक सेल्जमैन की बहु पंचायत में बी.डी.सी. चुनाव जीतकर आई थी, उसका सारा रिकॉर्ड उठाकर ले गए और उसको कहा कि तुझे हम 5.00 लाख रुपये की पैनल्टी

कम-से-कम डालेंगे। इस तरह का दवाब डाला गया। लेकिन मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि वह सेल्जमैन, जो हमारी पार्टी का समर्थक है, और उसकी बहु, उन्होंने कहा कि जो होना है होने दीजिए, उसके बावजूद हमारा समर्थन आपको और आपकी पार्टी को ही रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सिराज विधान सभा क्षेत्र में एक बी.डी.सी. का मैंबर जीत कर आया। उसका भाई 15 सालों से अलग रहता है। उनका अलग घर और परिवार है। उसका भाई जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में जे.ई. की नौकरी करता था उसके ऑर्डर डोडरा क्वार कर दिए। फैक्स ऑर्डर आते हैं जिनके आधार पर उसको रिलीव होने के लिए कह दिया जाता है कि या तो अपने भाई को यहां लेकर आओ, यदि नहीं लाता है तो डोडरा क्वार जाओ। यही बातें और जगह पर हैं। अगर नाम चाहिए तो मैं उन कर्मचारियों के नाम भी आपको बता दूंगा। इसको निष्पक्ष चुनाव कहते हैं? यहां आप छपराण पंचायत का ज़िक्र कर रहे हैं। वहां पर किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कीं। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर बोलेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए मेहरबानी करके इस बात को मत कहिए कि हमने पंचायत के चुनावों में दखल नहीं दिया; हमने निष्पक्ष चुनाव करवाए हैं। मेहरबानी करके इस शब्द का इस्तेमाल आप मत करिए क्योंकि आपने जो करना था वह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की दादागिरी का एक और उदाहरण है। मण्डी जिला के अंतर्गत नेरचौक, जो एक पंचायत थी उसे नगर पंचायत बनाते तो भी समझ में आता लेकिन उसको नगर पंचायत नहीं बनाया गया, सीधा नगर परिषद् बना दिया। लोग हमारे पास भी आए। हमने कहा कि आप अपनी बात रखिए, मंत्री तो आपका है, मंत्री के पास रखिए। मंत्री ने कहा कि हमने जो तय कर दिया हमने कर दिया। जो हमने तय कर दिया, उसमें कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हमने नगर परिषद् का वहां नोटिफिकेशन कर दिया है, इसलिए नगर परिषद् बन कर रहेगी।

जारी ...गर्ग जी

03/03/2016/1610/RG/AG/1

श्री जय राम ठाकुर-----क्रमागत

उपाध्यक्ष महोदय, परिणाम क्या निकला? उन लोगों ने प्रस्ताव भेजा और मेरे पास भी यहां प्रस्ताव पड़े हुए हैं। ये प्रस्ताव हैं, वे लोग डी.सी. को मिले, ए.डी.सी. को मिले, ए.डी.एम. को मिले और मुख्य मंत्री को मिले, लेकन कहीं भी उनकी बात नहीं सुनी गई। क्योंकि एक प्रभावशाली मंत्री उस विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसके कारण उनकी बात को सुनने की गुंजाइश नहीं थी। परिणाम क्या हुआ? चुनाव हुए, लोगों ने कहा कि हमारी बात न तो ए.डी.सी., डी.सी. , मंत्री और न ही मुख्य मंत्री ने सुनी। इसलिए हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, विकल्प क्या बचता है कि हम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। 6 पंचायतें जो नगर परिषद, नैहर चौक में डाली गई थीं, तमाम पंचायत के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। चुनाव के दिन एक भी वोट वहां नगर परिषद के चुनाव में नहीं पड़ा। अब विषम परिस्थति वहां पैदा हो गई। 6 पंचायतें थीं, वहां न तो नगर परिषद का चुनाव हो पाया, न पंचायत का चुनाव हो पाया। अगर चुने हुए प्रतिनिधि के नाते कहीं अपनी बात पंचायत के माध्यम से कहना चाहें, अपने क्षेत्र की विकास की बात कहना चाहें, तो अब वे कहने की स्थिति में नहीं रह गए। एक नई परिस्थिति पैदा हो गई। मैंने यह जिक्र यहां इसलिए किया क्योंकि यहां कहा गया कि हमने पंचायतों का चुनाव बहुत निष्पक्ष होकर किया है, बहुत स्पष्ट तरीके से किया है। मुझे लगता है कि आपके पास यह बात कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ठीक है चुनाव हो गए, चुनाव का परिणाम निकल गया, चुने हुए प्रतिनिधि जो प्रधान बनने थे, वे प्रधान बन गए, जो जिला परिषद सदस्य बनने थे वे बन गए। लेकिन सरकार के माध्यम से जिस प्रकार का संचालन होना चाहिए था, चाहे वे नगर परिषद के चुनाव हैं, चाहे वे हमारे पंचायतों के चुनाव हैं, तो उन सारी चीजों का संचालन वह उस प्रकार से नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम और बात करें, तो यहां पर जिक्र किया गया कि हमने कौशल विकास भत्ते के लिए वर्ष 2013 के अन्तर्गत 30 दिसम्बर, 2015 तक 60,869 लाभार्थियों को 26.27 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। अब कौशल विकास भत्ते पर बात करें, तो हमने प्रश्न लगाया जिसका अभी उत्तर नहीं आया है। कौशल विकास भत्ता चुनाव के दिनों में क्या था? चुनाव के दिनों में यह बेरोजगारी भत्ता था।

03/03/2016/1610/RG/AG/2

क्या भाषण देते रहे? जो सत्ता पक्ष में आए, ये नौजवानों को गुमराह करके आए हैं और इस अभिशाप से ये बच नहीं सकते । लेकिन अब जो डेढ़-दो साल के पश्चात होने वाला है, नौजवानों का इनको ऐसा श्राप लगेगा कि हमें इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा और यहां भी ये ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। बेरोजगारों को कहा गया कि आप अपना खाता बैंकों में खोलकर रखो, हमने बेरोजगार भत्ता तय कर दिया है, राजा साहब ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में डाल दिया। ये कहते हैं कि जो प्लस टू पढ़ा है उसको 1000/-रुपये, ग्रेजुएट है को 1500/-रुपये उसके खाते में हर महीने आता रहेगा, बस आप खाता खोलो। बेरोजगार बेचारे परेशान हो गए, उन्होंने सोचा कि कुछ न सही, तो कम-से-कम जेब का खर्चा तो निकलेगा और न सही, तो मोबाईल का ही खर्चा निकलेगा। क्योंकि मोबाईल के बिना आजकल का नौजवान रह नहीं सकता। इसलिए बेरोजगार को लगा कि कम-से-कम कुछ तो राहत मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो और तीन साल बीत गए, लेकिन उनके खाते में कितना पैसा आया, उल्टा इन्होंने उस स्कीम को बदल दिया और कहा बेरोजगारी भत्ता नहीं, कौशल विकास भत्ता देंगे। तो कौशल विकास भत्ते की योजना तो पहली भी चलती रहती थी, थोड़ी अलग तरीके से चलती थी, लेकिन उसमें नया काम क्या किया? इसलिए बेरोजगार इन्तजार कर रहे हैं और वे खाता खोलकर बैठे हैं। अगली बार इनके खाते का वे इन्तजाम पूरा करेंगे। एक मुद्दा यह था जिसको लेकर यहां बहुत लंबी बात कहने की कोशिश की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरी श्री अनिल शर्मा, माननीय पंचायती राज मंत्री जी से बहुत बातें होती हैं, लेकिन मनरेगा के बारे में ये कहते हैं कि हम यहां से पैसा मांगते हैं, लेकिन केन्द्र वाले देते नहीं हैं। बजट का जो प्लान ये यहां से प्लान करके भेजते हैं उसमें कट लगता रहता है। इन्होंने कहा कि हमने पत्र लिखा, तो मात्र पत्र लिखने से समस्या का समाधान नहीं होता। आप व्यक्तिगत रूप से जाइए। हमारे समय में भी इस प्रकार से बजट पर कट लगता था। जब आपकी सरकार थी, तो आपको इस प्रकार से खुला पैसा थोड़े ही देती थी,

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2016/1615/MS/AG/1

श्री जयराम ठाकुर जारी-------

लेकिन उसके बावजूद अपना केस वहां रखिए कि प्रदेश में इस चीज की आवश्यकता है, इतने पैसे की आवश्यकता है। हमने इतनी लायबिलिटीज क्रिएट कर ली हैं। ऐसी परिस्थितियों में आपको वहां से निश्चित रूप से "मनरेगा" के अंतर्गत जो पैसा मिलना है, मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज को देख रहा था। मेरे पास एक डॉक्यूमैंट है। इसमें मैं वर्ष 2014-15 की "मनरेगा" की लायबिलिटीज देख रहा था जोकि बहुत ज्यादा हैं। मंत्री जी, आप इनको कब क्लीयर करेंगे, हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है? इसमें मण्डी जिला की वर्ष 2014-15 की जो मटीरियल, वेजिज और अन्य लायबिलिटीज हैं वे 2 करोड़ 37 लाख रुपये की हैं। पूरे प्रदेश की 9 करोड़ 10 लाख रुपये की हैं। उपाध्यक्ष जी, अगर हम आगे देखें तो वर्ष 2015-16 में मण्डी जिला में ही मटीरियल और लैबर की लायबिलिटीज 7 करोड़ 3 लाख रुपये है। यह मंत्री जी के जिले की हैं और पूरे प्रदेश की लायबिलिटीज 2015-16 की 46.22 करोड़ रुपये है। ये लायबिलिटीज उन लोगों की हैं जिन्होंने वहां जाकर अपने परिवार के लिए मजदूरी करके आजीविका कमाने का प्रयत्न किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी, इस बात को तो सुनिश्चित कीजिए कि कम-से-कम बेरोजगारों ने जो मेहनत करके पैसा कमाया है उनका पैसा समय पर मिले।

इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर नाबार्ड पर पूछे गए प्रश्न का जिक्र हो रहा था कि नाबार्ड के माध्यम से सड़कों और पुलों के लिए इतना पैसा दिया गया। सचमुच में मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले तीन सालों में जब से यह कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आई है, ये नाबार्ड साहब केवल उन्हीं विधान सभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के विधायक, नेता और मंत्री हैं। आप लोग मुख्य मंत्री जी को कम-से-कम ऐसा तो कहिए कि इस नाबार्ड साहब को हमारे विधान सभा क्षेत्रों में भी भेजो। तीन सालों में इस तरफ के लोगों का एक भी प्रोजैक्ट नाबार्ड का सैंक्शन नहीं हुआ है। अगर कहीं गलती से हो गया होगा तो पता नहीं है। सारे-का-सारा पैसा आपके विधान सभा क्षेत्रों में जा रहा है। इसकी क्या वजह है? इसको स्वीकृत

03/03/2016/1615/MS/AG/2

करने का तरीका क्या है? क्या रास्ता है? मैं बताता हूं कि इसका रास्ता कोई नहीं है। इसकासिर्फ एक ही रास्ता है कि जहां कांग्रेस का विधायक या नेता है वहीं पर इस पैसे को आबंटित करने की कोशिश हो रही है।

उपाध्यक्ष जी, पीलिया के ऊपर बहुत बड़ी चर्चा इस सदन में हुई। अभी एक बहुत बड़ी घटना इस प्रदेश में यह हुई कि पीलिया के कारण पूरे प्रदेश में हजारों लोग बीमार हुए और मौतें कितनी हुईं, इसको सरकार नहीं बता पा रही है। अखबारों में खबर आती है कि 20 लोग मर गए लेकिन मंत्री जी वहां से खड़े हो जाते हैं कि 20 लोग नहीं मरे हैं यहां 10 लोग मरे हैं या यहां कम मरे है। हम इन चीजों में नहीं जाना चाहते लेकिन यह सच्चाई है कि पीलिया का प्रकोप इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में स्वार रहा जिसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया। लेकिन अफसोस इस बात का होता है जब वरिष्ठ मंत्री वहां से उठते हैं, चाहे वे आई0पी0एच0 के हैं या अन्य विभागों के हैं और जवाब देने लगते हैं कि आपके समय में इतने पीलिया के मरीज थे। अरे, यह कोई समस्या का समाधान है? आज भी बिक्रम सिंह जी अपने विधान सभा क्षेत्र की किसी पानी की स्कीम की बात कर रहे थे। ये वहां पर उस स्कीम को स्वयं देखकर आए कि वहां पर टैंक में कबूतर मरा हुआ मिला और वहां टैंक के अंदर सड़े हुए कपड़े मिले और उस स्थिति में भी मंत्री जी जबरदस्ती क्लैरिफाई किये जा रहे हैं, किये जा रहे हैं। इतने वरिष्ठ मंत्री से हमें इस प्रकार की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उनको तो आदेश करना चाहिए,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

03.03.2016/1620/जेएस/एएस/1

श्री जय राम ठाकुरः -------**जारी**----

उनको तो आदेश करना चाहिए अगर विधायक इस बात को लेकर बात कर रहे हैं तो इसमें सच्चाई हो या न हो लेकिन इनको कहना चाहिए कि हम इसकी जांच करेंगे। अगर ये इस बात को कहते तो हमें अच्छा लगता। लेकिन गलत बात को भी ठीक कह

रहे हैं। पिछले कल यहां पर ई.एस.आई. मेडिकल कॉलेज की बात आई उसको ले करके किस प्रकार से सारी पृष्ठभूमि और फिर जब हम अपनी बात कहने लगते हैं हम कुछ बातों को पृष्ठभूमि में ले जाने की बात करते हैं तो हमें चेयर की तरफ से कम इजाज़त मिल पाती है। हमको समय कम मिल पाता है। लेकिन सत्ता पक्ष से जो बोलने वाले होते हैं ये आधे घण्टे की पृष्ठभूमि बना लेते हैं। क्या जरुरत थी उस पृष्ठभूमि में जाने की कि पीलिया के रोग के मामले आपकी सरकार के दौरान इतने आए। अरे, वर्तमान में तो स्थिति यह है कि इसमें हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा। हाई कोर्ट का दखल सरकार के हर काम में इस वज़ह से भी आ रहा है क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है, करने की स्थिति में नहीं है और कुछ करना नहीं चाहती है इसलिए हाई कोर्ट हर बात को लेकर दखल दे रहा है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि हर बात पर दखल और पीलिया की बीमारी के लिए हाई कोर्ट दखल दें यह कोई बात बनती है। यहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार है। इससे पहले कि हाई कोर्ट दखल देता सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। जो भी उसमें काम करना था वह सारी की सारी चीजें सरकार के स्तर पर होनी चाहिए थी। उससे संदेश अच्छा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी हट-फिर के वहीं बात आती है। इसलिए हमको अफ़सोस होता है। जब यहां पर विपक्ष के माननीय सदस्य बात करने की कोशिश करते हैं और जब वरिष्ठ मंत्रियों से हमें संतोषजनक ज़वाब नहीं मिल पाता है तब ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार से होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर दो-तीन चीजों के बारे में बतलाना चाहता हूं। यहां पर बात आ रही हैकि चाहे एम्ज का इंस्टिट्यूट है, हम उम्मीद करते हैं कि वह

03.03.2016/1620/जेएस/एएस/

जल्दी से बनें और वह हिमाचल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसी के साथ-साथ मैं उन सारी चीजों में नहीं जाना चाहता जो केन्द्र सरकार ने दी है लेकिन एक बात को ले करके जब दो साल पहले आपकी यू0पी0ए0 की सरकार दिल्ली में थी तब क्या

बोलते थे कि आपकी सरकार जो हिमाचल प्रदेश में है वर्ष 2008 से 2013 तक रही, वह सरकार दो कदम चलने की स्थिति में नहीं थी अगर यू0पी0ए0 सरकार ने मदद न की होती। क्या अब यह सरकार बदल गई? उस सरकार के बदलने के बाद क्या अब परिस्थिति बदल गई ? आज भी हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर केन्द्र सरकार, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी, जिनका हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष लगाव है, अगर वो इस प्रकार खुली मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं करते, हर मामले में मदद नहीं करते, चाहे वह संस्थान की बात है, चाहे वह विकास की बात है,चाहे वह नेशनल हाई-वेज़ की बात है, चाहे वह ॥M की बात है, चाहे वह ॥I की बात है, जितने भी संस्थान है यदि केन्द्र से हिमाचल प्रदेश में उन संस्थानों को खोलने में सहयोग न होता, विकास कार्य में पैसे देने के लिए उनका सहयोग न होता तो आपकी स्थिति क्या बनती? इसलिए मुझे लगता है कि जो बात आप दो साल पहले हमको कहते थे आज हम भी इस बात को कह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं कह रहे हैं । हम यही कह रहे हैं कि यह सरकार आपकी है। केन्द्र सरकार आपको सहयोग दे रही है और सहयोग देती रहेगी लेकिन प्रदेश में विकास को ठीक प्रकार से संचालित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। इसलिए मैं यह बात कर रहा था। घोषणा करने में इनको बड़ा मजा आाता है। इतना मजा आता है कि हर जगह फट्टा लगाने देते हैा। इन्होंने तीन मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिए। उनका नामकरण तक कर दिया। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और पहले ही उनका नामकरण कर दिया। तीनों कॉलेजों के नाम भी तय कर दिये हैं। जब तीनों कॉलेज चलेंगे तब नाम रख लेना। अभी नाहन कॉलेज के लिए आप लोगों ने यहां से स्टाफ भेजने की बात कहीं। लेकिन जितना भी स्टाफ वहां पर भेजा गया, स्टाफ के सब लोगों ने कहा कि हम वहां पर जाने के लिए तैयार

03.03.2016/1620/जेएस/एएस/3

नहीं है। हिमाचल प्रदेश में दो मेडिकल कॉलेज है एक आई0जी0एम0सी0 है और दूसरा

टांडा मेडिकल कॉलेज है। आप लोग दो को चलाने की स्थिति में नहीं है और घोषणा तीन की कर के गए हैं और ऐसी स्थिति में आपको बजट प्रावधान के साथ वे चीजें करनी चाहिए थी वह आपने नहीं की और सिर्फ फट्टा लगाने की जल्दी की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी0एच0सी0 खोल रखी है लेकिन उसमें ताला लगा हैं। वहां पर न डॉक्टर, न फार्मासिस्ट, न कोई कर्मचारी है और इस प्रकार से ईलाज हो रहा है। मेरे पास उसके फोटो पड़े हैं । मैंने मोबाईल से वहां के फोटो ले रखे हैं। आपकी बाघा क्यारी की पी0एच0सी0, कंगड़ी की पी0एच0सी0, खुलानाग की पी0एच0सी0, उद्घाटन कर दिए, और आजकल एक रिवाज़ और चला है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

03.03.2016/1625/SS-DC/1

श्री जय राम ठाकुर क्रमागतः

जिस बात को लेकर हमारे साथी भी कह रहे थे। कुछ लोग वहां जाकर कहते हैं कि यहां के राजा हम लोग हैं, जिनकी हमने जमानतें जब्त कर रखी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो-दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मैंने जमानत जब्त की है। लेकिन वे अपने आपको वहां पर राजा कहते हैं कि राजा साहब हम हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर वे घोषणाएं करते हैं और घोषणाएं करने के बाद उद्घाटन करने की होड़ लगी है। इसने एक उद्घाटन किया है तो दूसरा दो उद्घाटन करने के लिए जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ठीक सुझाव दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सुझाव की दृष्टि से जो बातें कही गईं तो यह उचित रहेगा कि कम-से-कम जो इस प्रकार से राजा साहब का नाम लेते हैं और कहते हैं कि यहां के चीफ मिनिस्टर हम हैं। इस संख्या को कम करने की कोशिश करिये। आर्थिक दृष्टि से जितना नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है उसमें कम-से-कम कुछ तो राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यहां हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कह दी हैं।

Deputy Speaker: Now, please wind up. I am calling next. अब काफी हो गया।

श्री जय राम ठाकुर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर समाप्त कर दूंगा। मेरी बात खत्म हो रही है। एक जो विधायकों की एनुअल प्लानिंग की मीटिंग हुई। उसमें हम गये, हमने अपनी बात रखी। लेकिन विधायक प्राथमिकता में हम देख रहे हैं कि तीन साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद एक भी हमारी डी0पी0आर0 नहीं बनीं। अगर किसी एक-आध की डी0पी0आर0 बनी है तो उसके लिए सैंक्शन नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम-से-कम जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो प्लानिंग की बैठक में हम चर्चा करते हैं जिसमें मुख्य मंत्री जी ने अपना कंसर्न भी शो किया और कहा भी, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल नहीं हो पा रहा। इस बात को लेकर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

03.03.2016/1625/SS-DC/2

उपाध्यक्ष महोदय, कई बार तो हम सोचते हैं कि हमें अपनी ओर से लिख करके विधायक प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि उसमें देने का कोई फायदा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे बहुत बातें कहने के लिए थीं लेकिन आप कह रहे हैं कि समय की कमी है। आपने जो मुझे यहां पर समय दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस माननीय सदन में अभिभाषण प्रस्तुत किया है उनके प्रति बहुत सम्मान व्यक्त करते हुए इस धन्यवाद प्रस्ताव का, जोकि सत्ता पक्ष की ओर से रख गया, समर्थन करने में असमर्थ हूं, धन्यवाद।

समाप्त

03.03.2016/1625/SS-DC/3

उपाध्यक्ष: अब श्री संजय रतन जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री संजय रतनः उपाध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2016 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस माननीय सदन को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां इस सम्मानीय सदन के समक्ष रखीं। उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री जगजीवन पाल जी ने इस माननीय सदन में रखा, जिसका अनुसमर्थन माननीय सदस्य, श्री अजय महाजन जी ने किया। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने जब से छठी बार हिमाचल प्रदेश की बागडोर सम्भाली है, जो विकास पिछले पांच सालों में हिमाचल प्रदेश में रूक गया था उसको गति प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। पिछले तीन सालों में जो हमारा कांग्रेस पार्टी का मैनिफैस्टो था, जिसका ज़िक्र माननीय विपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने सदन में किया, उसको एक नीति दस्तावेज़ बनाकर सरकार ने उस पर कार्य किया। लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा उसमें किये गये वायदे पिछले तीन सालों में पूरे किये गये हैं और बाकी जो 20 प्रतिशत के आसपास कार्य हैं उनको अगले दो सालों में पूरा कर दिया जायेगा। क्योंकि ये जो मैनिफैस्टो है

जारी श्रीमती के0एस0

03.03.2016/1630/केस/डीसी/1

श्री संजय रतन जारी----

यह किसी एक साल के लिए नहीं बनता। जब भी कोई पार्टी चुनाव में जीतती है तो अपने पांच साल के लिए सत्ता में आने पर वह क्या काम करेंगें, उसको उसमें दर्शाया जाता है। जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस वक्त इन्होंने भी इसी प्रकार से मैनिफैस्टो बनाया था और उसके ऊपर इन्होंने कार्य किया। उसको नीतिगत दस्तावेज बनाकर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो हिमाचल की जनता के साथ वायदे किए थे, उनको पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री महोदय ने अगले चुनाव से पहले-पहले हर किए हुए वायदे को पूरा करने का विश्वास हिमाचल की जनता को दिया। आप किन्नौर तथा लाहौल से

लेकर सिरमौर तक नज़र दौड़ाएंगें तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस सदन में जब चर्चा में हिस्सा ले रहे थे तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ। यह तथ्यों से परे हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में नज़र दौड़ाएंगें तो असंख्य काम सभी चुनाव क्षेत्रों में हुए हैं। अभी यहां से भाई बिक्रम सिंह जी कह रहे थे कि ज्वालामुखी में विकास हुआ । अगर ज्वालामुखी में विकास हुआ तो साथ लगते चुनाव क्षेत्र देहरा में भी विकास हुआ है। जसवां-प्रागपुर में भी विकास हुआ है। अगर ज्वालामुखी में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसी स्कूल को अपग्रेड किया है तो जसवां चुनाव क्षेत्र के स्कूलों को भी अपग्रेड किया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो माननीय सदस्य बिक्रम जी खड़े हो कर यहां बता सकते हैं। अगर हमने मुख्य मंत्री महोदय से गर्ल्ज़ स्कूल ज्वालामुखी को अपग्रेड करवाया है तो हमने गर्ल्ज़ स्कूल देहरा को भी अपग्रेड करवाया है। हमने जसवां चुनाव क्षेत्र के गर्ल्ज़ स्कूल प्रागपुर को भी अपग्रेड करवाया है। हमने जसवां चुनाव क्षेत्र के गर्ल्ज़ स्कूल गरली को भी अपग्रेड करवाया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहीं भेदभाव नहीं किया। अगर उन्होंने खुंडियां में डिग्री कॉलेज खोला तो उन्होंने डाडा

03.03.2016/1630/केस/डीसी/2

में भी डिग्री कॉलेज खोला, रक्कड़ में भी खोला। भाई बिक्रम जी कह रहे थे कि ज्वालामुखी में एस.डी.एम. ऑफिस खुला। वह खुला लेकिन उसका सबसे ज्यादा फायदा देहरा और जसवां चुनाव क्षेत्र को हुआ क्योंकि हमारा जो एस.डी.एम. देहरा था, उसके पास प्रोटोकॉल डियूटी होती थी। बहुत से मंदिर देहरा सब डिविज़न के अंदर थे। उन मंदिरों का कार्य एस.डी.एम. देहरा को देखना पड़ता था। जब एस.डी.एम. ऑफिस ज्वालामुखी में खुला, तब ज्वालामुखी और उसके आसपास जितने मंदिर थे, उनका कार्य एस.डी.एम. ज्वालामुखी देख रहा था और देहरा में 24 घण्टे आपको एस.डी.एम. उपलब्ध रहा। वरन क्या होता था कि आपके संसारपुर टैरेस से अगर कोई आदमी एस.डी.एम. से कोई कार्य करवाने के लिए आता था तो देहरा में एस.डी.एम. साहब नहीं मिलते थे। अगर देहरा के हरिपुर साईड से कोई व्यक्ति आता था तो देहरा में एस.डी.एम. साहब नहीं मिलते थे। जब से ज्वालामुखी में एस.डी.एम. ऑफिस खुला,

देहरा के एस.डी.एम. 24 घंटे वहां उपलब्ध है और अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आप शिक्षा का क्षेत्र लें तो असंख्य स्कूल, सैंकड़ों स्कूल जो भारतीय जनता पार्टी के समय में बन्द हुए थे, उनको भी पिछले तीन सालों में चालू किया गया। इसके अलावा नए स्कूल खोले । इसके अलावा जहां से स्कूलों की डिमांड आई वहां स्कूलों को अपग्रेड किया। यही नहीं यहां पर कहा जा रहा था कि स्कूल खोल दिए लेकिन उनमें अध्यापक नहीं है। एस.एम.सी. के द्वारा प्रावधान किया गया, रिक्रूटमैंट प्रोसैस अलग से चला। उसमें समय लगता है लेकिन उसमें बच्चों की पढ़ाई को नुकसान न हो उसके लिए स्टॉप गैप अरेंजमैंट करके एस.एम.सी. के माध्यम से सरकार ने वहां अध्यापक उपलब्ध करवाए ताकि बच्चों की पढ़ाई ठीक तरीके से हो। सारी मूलभूत सुविधाएं शिक्षा संस्थानों में देने के लिए हमारी सरकार ने पूरी कोशिश की है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.3.2016/1635/av/ag/1

श्री संजय रतन----------जारी

स्कूल में अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए शिक्षा संस्थानों में वे सारी मूलभूत सुविधाएं चाहिए। आपने कहा कि स्कूल खोल दिए मगर वहां भवन नहीं है। पिछले साल ही सरकार ने भवनों के निर्माण हेतु 67 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करवाई है। अब बहुत से भवन बन रहे हैं। आपके क्षेत्रों में भवन बन रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में बन रहे हैं; सारे क्षेत्रों में भवन बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो नये डिग्री कॉलेज खोले हैं उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इन्होंने वे सारे के सारे डिग्री कॉलेज किसी शहर में नहीं बल्कि गांव में खोले हैं। मेरे खुंडिया में डिग्री कॉलेज खुला। आपके रक्कड़ में डिग्री कॉलेज खुला, डाडा में खुला। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो पायेंगे हिमाचल प्रदेश में जहां भी डिग्री कॉलेज खुले हैं वे ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं। इनके

खुलने से सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की बच्चियों को हुआ है। पहले माता-पिता अपनी बच्चियों को शहर में दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। केवल कुछ प्रतिशत बच्चे ही गांव से शहर पढ़ने जाते थे। मगर आज हमारे बच्चे घर की रोटी खाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्ष के कार्यकाल में यह सबसे बड़ा फायदा दिया है। यह कॉलेज एक या दो नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में सैंकड़ों कॉलेज खुले हैं। इसके अतिरिक्त आई.टी.आई. संस्थान खुले हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज खोले हैं, पोलीटैक्निक कॉलेज खोले हैं। यहां पर रवि जी और बिक्रम जी ने सैंट्रल युनिवर्सिटी का जिक्र किया, मैं भी उसके समर्थन में हूं। जब आपकी सरकार थी तो हालांकि मैं उस समय विधायक नहीं था। उस वक्त जब दिल्ली से टीम आई थी तो मैं उस टीम के साथ गया। हमारे देहरा सब डिविजन से दो मंत्री थे। इसमें एक माननीय रवि जी और दूसरे मेरे **प्रतिद्वंदी** थे। उस वक्त दोनों ही नहीं आए। मैं उस टीम के साथ गया और मैंने देहरा तथा ज्वालामुखी में उस टीम के साथ विजिट किया। मैंने उस वक्त ज्वालामुखी की जितनी भी सरायं थी उन सबसे लिखवार कर दे दिया कि हम सैंट्रल युनिवर्सिटी के लिए ज्वालामुखी में रैंट फ्री अकोमोडेशन उपलब्ध करवा देंगे। आज अगर इस सैंट्रल युनिवर्सिटी के ऊपर

3.3.2016/1635/av/ag/2

राजनीतिकरण किया जा रहा है तो उसमें दोषी आप है। आज आप देहरा-देहरा की बात करते हैं। हम भी देहरा के पक्षधर हैं। मगर सबसे बड़ी गलती आपके समय में हुई। वह गलती यह थी कि जब सैंट्रल युनिवर्सिटी की क्लासिज लगने की बात आई तो आपने देहरा सब-डिविजन, ज्वालामुखी या किसी और स्थान पर क्लासिज नहीं लगाई बल्कि आपने शाहपुर में क्लासिज लगाई। हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। मगर यदि आप उस वक्त वही क्लासिज देहरा में लगा देते तो शायद यह मुद्दा उसी समय खत्म हो जाता। वहां क्लासिज लगने से यह मुद्दा ऑटोमैटिकली खत्म हो जाना था। आपने शाहपुर में क्लासिज लगाकर उसमें धर्मशाला का क्लेम भी रख दिया और अब शाहपुर

वाले भी क्लेम कर रहे हैं। अब तो आपको शाहपुर से भी क्लासिज वापिस लेना मुश्किल हो जायेगी क्योंकि धर्मशाला में युनिविर्सिटी बनती है। एक तरफ देहरा की राजनीति हो रही है और दूसरी तरफ शाहपुर वाले बोलने लग पड़ेंगे। पीछे जब कंट्रोवर्सी चली तो शाहपुर वालों ने भी डिमांड कर दी कि युनिवर्सिटी शाहपुर में होनी चाहिए। आपकी सरकार थी, दो वहां से मंत्री थे। सभी मिल-बैठकर माननीय विपक्ष के नेता जो उस समय मुख्य मंत्री थे; इनसे अनुरोध करते तथा क्लासिज ज्वालामुखी में इतनी सरायं खाली थी उनमें लगा देते तो शायद आज यह कंट्रोवर्सी नहीं होती और आज सैंट्रल युनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाती। मेरा इस सदन के माध्यम से सबसे निवेदन है कि कृपया इस मुद्दे को खत्म कीजिए और सैंट्रल युनिवर्सिटी को बनवा लीजिए। ऐसा न हो कि हमारी कंट्रोवर्सी से यह युनिवर्सिटी बन न पाए और हिमाचल से बहुत बड़ा इनस्टिच्यूशन वापिस चला जाए। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर भी जमीन मिलती है वहां पर युनिवर्सिटी बनवा दी जाए मगर देहरा का हिस्सा देहरा को अवश्य दिया जाए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं। जो कुछ भी करना है हम सब आपसे में मिलकर करें क्योंकि यह फैसला हिमाचल के हित का है। यह इनस्टिच्यूशन न देहरा के लिए है, न कांगड़ा के लिए है, न धर्मशाला के लिए है बल्कि यह इनस्टिच्यूशन हिमाचल के लिए है। हिमाचल का इनस्टिच्यूशन हिमाचल में ही खुलना चाहिए। इस इनस्टिच्यूशन के बनने से आज करोड़ो रुपये आमदनी बढ़ती। उस वक्त ये इनस्टिच्यूशन जहां-जहां अनाऊंस हुए वे बनकर तैयार भी हो गये हैं। मगर हम

आज भी कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। हम यही फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि देहरा में बनेगा या धर्मशाला में बनेगा। इस समस्या का समाधान किसी भी तरीके से किया जाए और इस इनस्टिच्यूशन को हिमाचल प्रदेश में जल्दी से जल्दी बना लिया जाए।

टी सी द्वारा जारी

03.03.2016/1640/TCV/DC/1
श्री संजय रतन ----- जारी

हमारी सरकार ने पिछले तीन साल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बहुत ज्यादा काम किया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सामाजिक पेंशन 600 रूपये किया है। 70 परसेंट विकलांग व्यक्तियों को और 80 साल से ऊपर आयु के व्यक्तियों को 1100 रूपये दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। स्वतंत्रता सैनानियों की पैंशन बढाई गई इसके लिए मै माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूॅ। स्वतंत्रता सैनानी की मृत्यु के उपर उनको अनुदान मिलता था, उसके साथ-साथ उनकी पत्नी के देहान्त पर भी माननीय मुख्य मंत्री ने 10 हज़ार रूपये अनुदान किया है। उनकी पुत्र के विवाह के लिए उन्होंने 51 हजार रूपया अनुदान किया है और पौत्री के विवाह के लिए 21 हजार रूपये अनुदान किया है। इसलिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। कमज़ोर वर्ग के जो विद्यार्थी है, वह कंपीटिशन में बैठते हैं, उनके लिए निःशुल्क कॉचिंग का प्रबंध माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किया है। हिमाचल प्रदेश के छात्र जो सिविल सर्विसिज़ की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उनको मेन परीक्षा में बैठने के लिए 30 हजार रूपये का अनुदान माननीय मुख्य मंत्री ने किया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पी0टी0ए0 के शिक्षक लगाए, उनको कांट्रैक्ट में कंवर्ट किया। लेकिन जब पिछली सरकार थी कोर्ट केसिज़ की वज़ह से कुछ पी0टी0ए0 के शिक्षकों को निकाल दिया गया था। अभी तक वह कांट्रेक्ट में शामिल नहीं हो सके। उनके उस पीरियड को रेगुलेराइज्ड करके उनको कांट्रेक्ट में कन्वर्ट किया जाये। 10-12 साल से वे टीचर्ज़ कांट्रैक्ट पर लगे हैं। पैरा टीचर्ज़ को भी आपने रेगुलेराइज्ड किया है और एक पैट कैटागिरी (प्राईमरी असीसटैंट टीचर्ज़) जो बी0एड0 हैं और जे0बी0टी0 के अंगेस्ट काम कर रहे हैं। उनके लिए भी नीति बनाकर उनको भी पक्का किया जाये। इस मान्य सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बहुत बातें की गई। ये कहा गया कि जब आपकी सरकार थी तो आप यू0पी0ए0 सरकार से कुछ नहीं लेकर आये। हमारे लोगों ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में है और हमें पैसा नहीं मिल रहा। इसमें सच्चाई है कि पिछले दो सालों में हमने 'प्लालिंग कमीशन' को खत्म करके 'नीति आयोग' बनाया। लेकिन उस नीति आयोग से कौन-सी

नीति निकली , उसका अभी तक किसी को ज्ञान नहीं हैं। हमें

03.03.2016/1640/TCV/DC/2

मालूम नहीं है कि नीति आयोग क्या काम करेगा? कौन-सी उसकी गाईड लाईन्ज़ है? किसके आधार पर स्टेट्स को पैसा मिलेगा? आपने प्लानिंग कमीशन को डिजोल्व करना था, आप डिजोल्व कर देते। मगर पहले नीति आयोग को बना देते। नीति आयोग का ड्राफ्ट बन जाता, उसके बाद आप प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देते। नीति आयोग बना नहीं और प्लालिंग कमीशन आपने खत्म कर दिया। राज्यों को पता नही लगा कि हमें कौन-सा हिस्सा मिलेगा, किस तरीके की प्लॉन बनाकर हम आगे जायें? मैं अपने विपक्ष के भाईयों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधान मंत्री बनने से पहले हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज थे। हिमाचल प्रदेश की हर चीज़ को वह जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को वह जानते हैं। सरकार चाहे आपकी रही, सरकार चाहे हमारी है। आपने भी सरकार चलाने के लिए लॉन लिए हम भी सरकार चलाने के लिए बीच में लॉन लेते हैं। आज अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में हिन्दुस्तान की सरकार, जिसको हिमाचल के बारे में हर चीज़ का पता है और आप हर छोटी-छोटी बात पर कह देते हैं कि नरेन्द्र भाई मोदी ने ऐसा कर दिया। हम जानते हैं, आपके इतने अच्छे संबंध है। आप माननीय प्रधान मंत्री महोदय से एक आर्थिक पैकेज़ की बात हिमाचल प्रदेश के लिए कीजिए। एक बहुत बड़ा पैकेज़ अगर आप हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आएंगे, मैं सत्ता पक्ष की ओर से आपसे प्रोमिज़ करता हूं कि पूरा-का पूरा सत्ता पक्ष आपके साथ चलेगा और इसका वैल्कम करेंगे। आप जो भी स्वागत समारोह की बात करेंगे,

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी

3.03.2016/1645/RKS/AS/1

श्री संजय रतन...जारी

जितना भी हिमाचल प्रेदश में स्वागत होगा, वह हम करेंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा

मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आप नरेन्द्र भाई जी से एक आर्थिक पैकज लेकर आएं, उनसे बात करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने जो इस सदन को सम्बोधित किया, जगजीवन पाल जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा और अजय महाजन जी ने जिसका अनुसमर्थन किया, मैं उसका पूरजोर शब्दों से समर्थन करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में जनता के साथ किए गए हर एक वायदे को अगले चुनाव से पहले-पहले पूरा करेगी और हम 7वीं बार भी सत्ता में यहां पर काबिज होंगे। आप भाई यहां पर बैठे होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

3.03.2016/1645/RKS/AS/2

उपाध्यक्षः श्री वीरेन्द्र कंवर

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम आचार्य देवव्रत जी ने 25 फरवरी, 2016 को जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा मुझे लगता नहीं कि उन्होंने इस भाषण को मन से पढ़ा होगा। ये जो हमार अभिभाषण होता है यह सरकार का एक नीतिगत दस्तावेज होता है। क्या करना चाहते हैं? कहां इस प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे पूर्व वक्ता श्री जय राम ठाकुर जी ने कहा कि यह तीसरे वर्ष आते-आते सिकुड़ता ही जा रहा है। जैसे जगजीवन पाल जी कह रहे थे कि यह पैन ड्राईव में ही आ गया है। इस अभिभाषण में इन्होंने कोई नीति नहीं दशाई है। अगर आप पहले वर्ष का अभिभाषण देखें और अभी का देखें तो हम यह कहेंगे कि जैसे-जैसे परीक्षा आती है वैसे-वैसे यह स्योर-शोट होता जा रहा है। जो कि परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार किया जाता है। उसी दृष्टि से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी तो धूमल जी ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता रहेगी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार । पांच वर्ष हमने धूमल जी के नेतृत्व में बड़े जोर से काम किया। चाहे इस देश के अंदर यू.पी.ए. की सरकार थी। यू.पी.ए.की सरकार के होते हुए हमारे कार्यों को जगह -जगह रोका जाता था। यू.पी.ए. गवर्नमेंट में हमारे दो मंत्री केंद्र में थे। एक उद्योग मंत्री, दूसरे कॉमर्स

मिनिस्टर थे। लेकिन जो अटल जी के समय में हिमाचल प्रदेश को पैकेज मिला था, हमारा दुर्भाग्य है यू.पी.ए.गवर्नमेंट ने उसे वापिस लिया। आज आर्थिक पैकेज की बात करते हैं। पूर्व वक्ता संजय रतन जी ने कहा कि आर्थिक पैकेज लेकर आएं। 32 परसेंट से बढ़ाकर 42 परसेंट की इनक्रीज नीति आयोग ने हिमाचल प्रदेश को दी है। हर प्रदेश को दी है। 5 वर्षों में 76 हजार करोड़ रुपया हिमाचल के हिस्से में आएगा। किसी से कोई भेदभाव माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने नहीं किया है। ऐसा ही पूर्व वक्ता धर्माणी जी कह रहे थे कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की नीयत अच्छी नहीं है। वे अच्छी नीयत वाले व्यक्ति नहीं है। जहां लोगों ने पूरे देश के अंदर कांग्रेस से दुःखी होकर किसी व्यक्ति

3.03.2016/1645/RKS/AS/3

को चुना, जहां भारतीय जनता पार्टी की 118 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर अगर किसी के कारण बहुमत मिला तो वह नरेन्द्र मोदी जी के कारण मिला जो इस देश के लोगों ने दिया।

श्री एस.एल.एस. द्वारा ...जारी

03.03.2016/1650/SLS-DC-1

श्री वीरेन्द्र कंवर ....जारी

283 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 336 सीटें एन.डी.ए. को मिलीं। आज कांग्रेस की स्थिति कैसी है? कांग्रेस की स्थिति यह है कि कभी मिस्टर क्लीन राजीव गान्धी 400 सीटें लेकर आए थे और आज आप 40 के ऊपर सिमट गए। अगर ऐसे ही चलते रहे,

जैसे जे.एन.यू. में भारत विरोधी लोगों का समर्थन करते रहे तो स्थिति और बदलेगी। पेपर में एक दिन एक कार्टून आया था। उसमें पूछा था कि आपने जे.एन.यू. में समर्थन क्यों किया? कहते हैं कि करें भी क्या, अभी तो हमारे पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस की ऐसी स्थिति हो गई है। आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि जब प्रदेश से केंद्र में दो-दो मंत्री थे, वह भी हिमाचल को कुछ नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी धूमल जी ने अपने कार्यकाल में जो करके दिखाया, 85 से ज्यादा अवार्ड अगर किसी को मिले तो वह उस समय की हिमाचल प्रदेश सरकार को मिले। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन तीन वर्षों में कभी अवार्ड का मुंह भी देखा? एक भी अवार्ड नहीं मिला। आपकी तीन वर्ष की कारगुजारी कहां है? आज प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। हमारी मूलभूत समस्याएं सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं। देश की आजादी के 67-68 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम इसी का चिंतन कर रहे हैं। पीने के पानी की इस समय क्या स्थिति है। अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई। प्रदेश के अंदर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पीने के पानी की वजह से ही आज शिमला जैसे शहर में मलयुक्त पानी लोगों को पिलाया गया; इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? पीलिया जैसा भयानक रोग शिमला जैसे विश्व के मानचित्र पर पर्यटक राजधानी के रूप में माने जाने वाले शहर में फैला। धूमल जी की सरकार के समय इसे वैस्ट डैस्टिनेशन का दर्ज़ा भी मिला था। आज वहां पीलिया फैला है। पीलिया के कारण पूरे प्रदेश में पर्यटन प्रभावित हुआ है।

खेल पर्यटन के रूप में लाखों लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में मैच देखने के लिए आने वाले हैं। लेकिन यहां पर भी जानबूझकर खेल के नाम पर राजनीति की जा रही है। उस स्टेडियम की कैपेसिटी 20,000 की है लेकिन वहां

03.03.2016/1650/SLS-DC-2

3 लाख से ज्यादा लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया है। लाखों लोग प्रदेश के अंदर आने वाले हैं। पूरे विश्व के लोग धौलाधार की सुंदरता और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों

को देखने वाले हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार उसमें भी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। मैंने कहा कि पानी की समस्या आज मेरे अपने विधान सभा क्षेत्र के अंदर भी है। बहुत सारे सोर्सिज ऐसे हैं जहां सीधे पानी दे दिया गया है। पिछली बार भी वहां पर डायरिया फैला था। जो स्थिति 5-7 वर्ष पहले हुआ करती थी आज भी वैसी ही स्थिति हो गई है। धूमल जी के समय में पीने के पानी की 9 स्कीमें बनीं और 800 से ज्यादा हैंड पंप लगे। टैंकरों से जो पीने का पानी आता था वह लोगों को सुचारू रूप से मिलने लगा था। लेकिन आज वह स्कीमें संभाली नहीं जा रही हैं। उन स्कीमों के ऊपर स्टॉफ नहीं है। मेरे क्षेत्र में 70 से ज्यादा ट्यूबवैल लगे।

जारी ...गर्ग जी

03/03/2016/1655/RG/DC/1

श्री वीरेन्द्र कंवर -----क्रमागत

आज उन स्कीमों को संभालने के लिए इनके पास स्टाफ नहीं है। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में 70 से ज्यादा टियूबवैल वहां लगे। लेकिन पिछले दो महीनों से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण यह है कि वहां स्टाफ नहीं है। आज तीन वर्षों में एक भी हैण्ड पम्प वहां नहीं लगा है। वैसी ही स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है। क्या नीति है इनके पास? कम-से-कम एक स्वास्थ्य केन्द्र तो हर विधान सभा क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए जहां सभी किस्म के चिकित्सक वहां हों ताकि गरीब मजदूर और आम-आदमी को फर्स्ट एड मिल सके, वह वहां अपना इलाज करवा सके और उनको बाहर न जाना पड़े। आज मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न के उत्तर पर मैंने पूछा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने पद सृजित हैं? माननीय उपाध्यक्ष जी, सिर्फ एक सी.एच.सी. है वह बंगाणा में है। एक पी.एच.सी. थानाकलां में,, एक पी.एच.सी. लठैणी में और एक पी.एच.सी. जो अभी नई खुली है वह रायपुर मैदान में है। लेकिन पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र एक डॉक्टर है। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि मात्र एक डॉक्टर है। बाकी सारी-की-सारी खाली पड़ी हैं। मैंने हर विधान सभा सत्र में इस प्रश्न का रखा, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला और आज तो विधान सभा के अंदर जो

आश्वासन मिलते हैं उनका भी कोई महत्व नहीं होता। हर बार कहा गया कि शीघ्र डॉक्टर भेजे जा रहे हैं। पिछली बार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में स्क्रब टाइफस जैसा भयानक रोग फैला। लेकिन वहां कोई दवाई नहीं मिलती, निजी डॉक्टर से लेकर दवाई खा रहे हैं, 6 दिन के बाद पी.जी.आई. भेज दिया और पी.जी.आई. में जाकर मौत हो रही है। मुझे उस समय बहुत दुःख हुआ जब एक 11 साल के बच्चे की ऊना अस्पताल में मौत हो गई। उसका किडनी, लीवर आदि स्क्रब टाइफस से फेल हो गए थे। वह बच्चा 6 दिन तक निजी अस्पताल से दवाई लेता रहा। एक डॉक्टर तक वहां नहीं मिला। अगर बंगाणा अस्पताल में कोई जाता है, तो आयुर्वेदिक की एक लेडी डॉक्टर है वह कहती है कि मैं आपको ऊना के लिए रैफर कर देती हूं जैसे रैफरल हास्पीटल बना दिया। रैफर करने का अस्पताल अब बंगाणा बन गया है। 70-80 किलोमीटर से पहले आज कोई फर्स्ट एड नहीं मिल पाती है। अगर पूरे विधान सभा क्षेत्र में देखें, तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वहां पीने-के-पानी की व्यवस्था नहीं है और आज उसी तरह से मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण हमारा बहुत सारा

03/03/2016/1655/RG/DC/2

इलाका खेती पर निर्भर है। वहां लोग किसान हैं। जब भी हम गांवों में जाते हैं, तो सबसे पहले महिलाएं हाथ जोड़कर कहती हैं कि इन बन्दरों का इन्तजाम करिए। तीन वर्ष से मैं विधान सभा में देख रहा हूं कि कोई सत्र ऐसा नहीं होता जब जंगली जानवरों, पशुओं और गउओं के बारे में प्रश्न यहां न आता हो। हम चर्चा यहां करते हैं और इस पर बहुत भारी चर्चा होती है, कोई गैर-सरकारी संकल्प दिवस ऐसा नहीं होता जिसमें इस बात की चर्चा नहीं होती हो। मुख्य मंत्री जी कबूतरों वाली कहानी हमें हर वर्ष सुनाते हैं। पिछले तीन सालों से झूठे आंकड़े यहां दिए जा रहे हैं कि इतने बन्दर कम हो गए। ये भरमौरी साहब यहां आंकड़े दे देते हैं। मैं बार-बार विभाग वालों से पूछता हूं कि बन्दरों की गिनती हुई, तो कहते हैं कि कौन से बन्दरों की गिनती?

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट आप बैठ जाएं। अभी 6 माननीय सदस्य चर्चा में और भाग लेने वाले हैं, तो अब इस माननीय सदन की बैठक एक घण्टे के लिए बढ़ाई

जाती है। अब आप बोलिए।

श्री वीरेन्द्र कंवर : मैंने कहा कि सरकार की कोई नीति नहीं है। आप प्रयास तो करें, मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो संभव नहीं हो पातीं। लेकिन असंभव कौन सी समस्या है? प्रयास तो हमारे उस ओर हों। जब धूमल साहब की पिछली सरकार थी, तो एक प्रयास हुआ और मंकी पार्क्स बनाए गए। कोशिश हुई कि एक जगह इनको रखा जाए। लेकिन यह जानवर इस प्रवृत्ति का है कि वह एक जगह टिक नहीं पाता। बन्दर संरक्षण पार्क का

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2016/1700/MS/AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर जारी-------

आइडिया सफल नहीं हो पाया फिर नसबंदी केन्द्र खोले गए। प्रयास तो उस दिशा के अंदर हुए हैं। मैं यहां पर मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कौन सा प्रयास हुआ है? हर चौथे दिन स्टेटमैंट आ जाती है कि हम वानर पार्क बनाएंगे, सैंक्चुरी बनाएंगे और सारे बंदर वहां छोड़ देंगे। कौन सा प्रयास हुआ है? कौन सी नीति यहां बनाई गई है? एक वर्ष से माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग और सरकार को आदेश दिए हुए हैं कि आप हरेक पंचायत में एक गौ-सदन बनाइए। लेकिन यह सरकार हाथ-पर-हाथ धरकर बैठी है। मेरा यहां प्रश्न लगा था जिसमें मैंने पूछा था कि कितनी पंचायतों के अंदर गौ-सदन बनाए गए? उत्तर आया कि सूचना एकत्रित हो रही है। अरे, क्या इतने गौ-सदन बना दिए और इतने पशु वहां रख दिए कि इनसे गिनना ही मुश्किल हो रहा है। क्या मजाक प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है? हर वर्ष सदन को बेवकूफ बनाया जाता है। अरे, कम-से-कम बैठकर कोई नीति तो लेकर आओ। हमारे जो संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत लिखे हैं उनमें कहा गया है कि जो सरकार

बनेगी, वह प्रयास करेगी कि जो दुधारू पशु हैं, और उसमें स्पैशल कहा है कि गऊ का बध प्रतिबन्धित होना चाहिए क्योंकि भारत की इकॉनोमी का अगर मूल कुछ रहा है तो वह गऊ रहा है। इसीलिए शायद हमारे पूर्वजों और ऋषि-मुनियों ने इसको धर्म की आड़ करके माता कहा है कि इसमें 3200 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं। लेकिन आज वह गऊ आवारा है। मैं मंत्री जी से कह रहा था कि कम-से-कम आप ब्रीडिंग पॉलिसी बदलिए। ये जो "जर्सी" एक शब्द यहां पर आ गया, तो जैसे मैंने कहा कि विदेशी लोगों और विदेशी चीजों से आजकल हमें बहुत मोह हो गया है। हम विदेशी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। वैसे ही भारतवर्ष में जब यह नस्ल आई तो लोगों ने एकदम इसको अपना लिया और जो देशी मूल की गऊएं थीं उनकी प्रजातियां खत्म होती गईं। वास्तव में यह जर्सी गऊ नहीं है बल्कि कहते हैं कि यह सूअर का दूध बढ़ाने के लिए एक ब्रीड तैयार की गई थी और इसको गऊ का नाम दे दिया गया। जब गऊ का नाम दे दिया फिर लोगों की श्रद्धा हो गई। ऐसा भी है कि शायद यह गऊ एक सीमा तक दूध देकर बांझ हो

03/03/2016/1700/MS/AG/2

जाती है। लोगों का न ही इस गऊ के साथ मोह होता है और न ही इसके बछड़े के साथ मोह होता है। वे बछड़े कृषि के काम में भी नहीं आते हैं। विदेशों में शायद इस पशु को मीट के लिए तैयार किया गया था। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन यह रहेगा कि इसके लिए नीति बनाई जाए कि भारतीय मूल की जो सहिवाल नस्ल है उसकी वैटरिनरी में जो कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं वहां पर व्यवस्था की जाए और इस प्रजाति को बदला जाए। भारतीय मूल की जो गऊएं होती थी, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी अपने उपन्यास "गोदान" में इसका उल्लेख किया है और गऊ का महत्व बताया है कि कितना लगाव उस गऊ और उसके बछड़े के साथ होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि यह सरकार यहां पर इस बारे में नीति बनाए ताकि धीरे-धीरे लोगों के अंदर गऊ रखने की प्रवृत्ति पैदा हो। उसी तरह से बंदरों के लिए भी कोई नीति तय की जाए। इनको मारना है तो मारो। आप भी देख रहे हैं कि धीरे-धीरे हिमाचल के किसान फसल बीजना छोड़ रहे हैं। आज हमारे यहां पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर जंगली पशुओं और आवारा बैल/गऊओं के कारण मौतें हो रही हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले महीने ही एक आवारा पशु के

वाहन के आगे आने से एक दुर्घटना घट गई और पूरा परिवार उसमें समाप्त हो गया। इसलिए मेरा वन विभाग से निवेदन रहेगा कि इसके लिए कोई नीति बनाई जाए। मंत्री जी के रहते-रहते वन तो रहेंगे ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

03.03.2016/1705/जेएस/एजी/1

श्री वीरेन्द्र कंवरः --------**जारी**--------

मैं महिलाओं का विरोध नहीं कर रहा हूं। आपने फोरैस्ट गार्ड महिलाएं लगा दी। अब वे जंगल में जा नहीं पाती। जंगल में जो तस्कर है, वन-काटु हैं, उनको रोकने में वे असमर्थ हैं। आपने वहां पर बैरियर लगा दिए। आपने देखा कि पिछले दिनों ऊना के अन्दर डिप्टी रेंजर को भी पीटा गया। पूरे स्टाफ को वहां पर पीटा गया। उनके पास कौन सा हथियार है जिससे वे उन तस्करों से निपट सकें? आप उनको सुरक्षा के लिए कम से कम कोई हथियार तो दो ताकि जितनी फोरैस्ट विभाग में तस्करी हो रही है उसको आप बन्द कर सकें। अगर आप वास्तव में सीरियस है तो आप उस तस्करी को बन्द करें नहीं तो ये सारे के सारे वन खत्म हो जाएंगे। माननीय उपाध्यक्ष जी यह जो सरकार की दोहरी नीति है किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ, यह गलत है। आप बड़े भारी पी0टी0ए0 के चैम्पियन बन रहे हैं। अरे, पी0टी0ए0 वाले तो आपने रख लिये लेकिन कम्प्युटर वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वे भी तो क्वालिफाईड है। उन लोगों ने भी डिप्लोमा/डिग्रियां ली हुई हैं। आप उनके लिए क्यों नहीं पॉलिसी बना रहे हैं? आऊट सोर्सिज में, हैल्थ डिपार्टमैंट में तो आर0के0एस0 में बदल करके आपने फिर से उनको रैगुलर कर दिया। लेकिन 10-10 सालों से आपने डी0सी0 ऑफिस में, ब्लॉकों में आऊट सोर्सिंग के माध्यम से सोसाइटियां बना करके बहुत सारे नौज़वान रखे हैं जिनके 8-10 साल हो गए। मैंने इस बारे में प्रश्न लगाया था। मैंने प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी थी। उनका क्या कसूर है, आप दोहरी नीति उनके लिए प्रदेश के अन्दर क्यों बना रहे

हैं? आपको अगर करना है तो एक पॉलिसी बनाईये। चाहे वे आऊट सोर्सिंग के माध्यम से लगा है। अगर 8 साल उसके पूरे हो गए हैं तो उसको रैगुलर किया जाए। सामाजिक अधिकारिता मंत्री यहां पर बैठे हैं। मैं पिछले दिनों इनसे मिला भी था। इनके विभाग का एक कर्मचारी मेरे पास आया और रोने लगा और कहने लगा कि मैं तो सुसाईड कर दूंगा। मैंने कहा कि क्या हुआ? उसने कहा कि 14 साल हो गए और ये सरकार 8 साल में रैगुलर करने की बात करती है लेकिन 14 साल से इनको रैगुलर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं, मंत्री जी के पास गया और मंत्री जी भी यह कहने लगे कि बात तो ठीक है । इनके साथ शोषण हो रहा है, लेकिन मैं भी

03.03.2016/1705/जेएस/एजी/2

मज़बूर हूं। आपकी कौन सी मज़बूरी है? मंत्री जी आप प्रपोज़ल बना करके आप मुख्य मंत्री जी के पास ले जाईये। दूसरे डिपार्टमैंट्स में आप उनको भेज दीजिए। वे बहुत ज्यादा लोग नहीं है थोड़े से लोग हैं, जिनको रैगुलर किया जाना है। उनको 14-14 साल हो गए हैं। कुछ लोग तो उनमें से रिटायर भी हो गए हैं । अपने रैगुलर होने के इन्तजार में अब वे रिटायर भी हो गए। बस थोड़े दिनों के बाद उनके कागजात मंगवाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसी तरह से वॉटर गार्ड है । मैंने प्रश्न किया था कि तीन घण्टे उनसे काम लिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष जी 12-12 घण्टे उन गरीब आदमियों से काम लिया जाता है। उनका शोषण हो रहा है। अगर वे आज वॉटर गार्ड न हो तो आपका सारे का सारा वाटर सप्लाई सिस्टम ठप्प हो जाएगा। कम से कम आप उनको दैनिक भोगी मज़दूर तो बना दो। उनको कम से कम मिनिमम वेजिज़ तो दे दो ताकि वे कम से कम अपना पेट तो भर सके । हमारी सरकार के समय में बहुत से अध्यापक थे जो सबोर्डिनेट स्लैक्शन बोर्ड से टैस्ट क्वालिफाई करके आए थे, आप डैड लाईन कर देते कि 31 मार्च तक जिसके पांच वर्ष पूरे हो जाएंगे उनको रैगुलर कर देंगें। अगर लगा ही अप्रैल महीने में होगा, 5 अप्रैल या 10 अप्रैल को लगा उसको तो एक साल का शोषण हो गया। मेरा कहना है कि उस नीति पर भी सरकार विचार करें। आज उसी

तरह प्रिंसिपल, हैड मास्टर्ज़ के साथ कर रहे हैं पहले एडहॉक के ऊपर उनकी प्रोमोशन होती थी अब एक नया शब्द एक हमारे बड़े बुद्धिजीवी सैक्रेटरी हैं, वे नए-नए शब्द लाते हैं।

श्री एसएस द्वारा जारी---

03.03.2016/1710/SS-AG/1

श्री वीरेन्द्र कंवर क्रमागतः

ये प्लेसमैंट शब्द इसमें ले करके आए हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जिस तरह से आपने पी0टी0ए0 अध्यापकों को रेगुलर किया है, आज आप उनको उसी तरह से रेगुलर करिये, जिनके 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। किसी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए।

आज सड़कों की स्थिति क्या है? मेरे ऊना डिवीजन की हालत बहुत खराब है। मैं तो ऊना की बात बता सकता हूं कि ऊना डिवीजन की लाइबिलिटी 6 करोड़ रुपये से ऊपर है और जो बंगाणा की है वह 3 करोड़ से ऊपर है। अगले महीने से टारिंग सीजन शुरू हो रहा है। लेकिन न डिपार्टमैंट के पास तारकोल है और न ही सीमेंट है। न ही जिन लोगों ने काम किया है उनको पैसे देने को हैं। काम की स्थिति क्या है? तीन वर्षों से जब से यह सरकार आई है मैं तो हैरान हूं कि कई जगह जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो डंगे लग रहे हैं, जिस डंगे को उखाड़ा जा रहा है उसके ही पत्थर उसमें डाले जा रहे हैं। मैंने एस0डी0ओ0 से शिकायत की। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो। तुम्हारा कोई आदमी वहां पर खड़ा नहीं है। कहते हैं कि क्या बात है आपसे कोई ठेकेदार का झगड़ा है, अगर झगड़ा है तो मैं उससे आपका समझौता करवा देता हूं। ये शब्द विभाग के लोगों के हैं। इतनी बुरी हालत है। टारिंग हो रही है तो फिर तीन-तीन महीने के बाद वहां गड्ढे पड़ रहे हैं। आप उसको जा कर देखिये। आप स्थिति देखिये।

Deputy Speaker: Please wind up now.

श्री वीरेन्द्र कंवरः कोई व्यक्ति वहां पर नहीं होता है। आज सड़कों की हालत हमारे क्षेत्र के अंदर खराब हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट पर अपनी बात कहकर

भाषण समाप्त करूंगा। शायद अगले कल भी बंदोबस्त का प्रश्न लगा है। हमारे यहां पर चार-पांच पंचायतें ऐसी हैं जो ऊना के साथ लगती हैं। उसमें एक टक्का है। अन्य डंगोली, चताड़ा और सकोन है। उसमें बंदोबस्त कैंसिल हो गया है। अब लोग बड़े परेशान हैं। मैंने हर सत्र के दौरान इस प्रश्न को सदन में भी लगाया और माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया कि वहां पर बंदोबस्त शुरू कर देंगे। लेकिन हालत ये है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी विरासत आगे नहीं चढ़ रही है। बहुत सारी जमीनें बिक गई हैं। दूसरे लोगों की जमीनें

03.03.2016/1710/SS-AG/2

कागजों में बेच दी हैं। पता नहीं विभाग क्यों अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रहा? जब भी हम पूछते हैं तो कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से होगा। जब भी हम एस0ओ0 से मिलते हैं और अगली तारीख एस0ओ0 की ऊना में आने की होती है तो एस0ओ0 साहब बदल गये होते हैं। फिर नये एस0ओ0 साहब से मिलना पड़ता है। मैं पिछले तीन वर्षों से देख रहा हूं कि हर बार झूठे आश्वासनों के सिवाय कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अभिभाषण महामहिम जी ने पढ़ा है, मैंने पहले ही कहा कि मन से नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि अगर मन से पढ़ा होगा तो शायद इतना गलत नहीं होगा। ये जो अभिभाषण है मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं इस वाक्य के साथ कि एक व्यक्ति घर में रोज़ गुनगुनाता था कि *मैं सब कुछ तूझ पर वारूं, मैं सब कुछ तूझ पर वारूं*। एक दिन उसका पड़ोसी आ गया और कहता कि बहुत अच्छा गाते हो, मैंने भी याद कर लिया है। लेकिन आगे की लाइन क्या है? कहता कि *तज़ी एक न फाड़ूं मैं।* मैं वारूं तो सब कुछ लेकिन करूंगा कुछ नहीं। तो ये जो तीन साल की आपकी कार्यशैली है बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही, ऐसा मुख्य मंत्री जी कहते रहे लेकिन आपने तीन वर्ष के अंदर किया कुछ नहीं। इस करके मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं, धन्यवाद।

समाप्त

03.03.2016/1710/SS-AG/3

उपाध्यक्षः अब श्री यादविन्द्र गोमा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री यादविन्द्र गोमाः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी, 2016 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे सी0पी0एस0, श्री जगजीवन पाल जी द्वारा इस माननीय सदन में लाया गया है और जिसका अनुसमर्थन श्री अजय महाजन जी ने किया है मैं उसी श्रृंखला में अपने आपको शामिल करता हूं।

3.03.2016/1715/केस/एएस/1

श्री यादविन्द्र गोमा जारी---

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह अभिभाषण के ऊपर, कांग्रेस सरकार के पूरे तीन वर्षों के विकास कार्यों के ऊपर जिस तरह यहां पर वार्तालाप हुआ, और जिस तरह विपक्ष के साथ चाहे कोई भी हो, उन्होंने कहा कि गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश में विकास ही नहीं हुआ, जैसे ये इस माननीय सदन को बताना चाहते हैं कि जब इनकी सरकार सत्ता में थी, जो भी हिमाचल प्रदेश में कार्य हुए हैं, सभी इन्हीं के विधायकों, मुख्य मंत्री और इन्हीं के मंत्रियों ने किए हैं। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार जो कि माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के कुशल नेतृत्व में बनी है, इनका मानना है कि तीन वर्षों के भीतर कोई भी विकास कार्य उसमें नहीं हुआ है। हमारे विकास कार्यों को गिनाने से पहले इनको अपने पिछले पांच सालों के किए गए विकास कार्यों के ऊपर भी टीका-टिप्पणी करनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि हमारे तीन सालों के विकास कार्य जो हुए हैं वे अधिक मात्रा में हुए हैं। चाहे विपक्ष के साथी हैं चाहे हमारी सरकार के सत्तासीन साथी हैं, हरेक वर्ग, हरेक जाति, हरेक समुदाय को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी के साथ एक समान सम्पूर्ण विकास करवाया है चाहे सत्तासीन पार्टी का विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है, विपक्ष के विधायक जो कि पिछली सरकार में मंत्री भी थे, उन्होने ऐसी टीका-टिप्पणी की कि हमारे क्षेत्र में पूछा गया कि पूर्व विधायक का घर कहां है, वहां बंदर छोड़ने है। ये अनावश्यक बातें इन्होंने यहां पर की ऐसी बातें करके ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, ऐसी बातें उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे भी अपने समय में अपनी सरकार के मंत्री रहे थे। उस समय जो उन्होंने काम किया है वह भी लोगों के सामने हैं। मैं एक उदाहरण

देना चाहूंगा कि जब महेन्द्र सिंह जी परिवहन मंत्री थे, मेरा नया विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर बना लेकिन उस समय पहले राजगीर विधान सभा क्षेत्र हुआ करता था और एक बहुत बड़ी दुर्घटना मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुई थी। एक सरकारी बस जो कि पालमपुर से आशापुरी मंदिर

3.03.2016/1715/केस/एएस/2

को जाती थी, उस समय बसों की बहुत खस्ता हालत थी। मैं तो कह सकता हूं कि पिछली सरकार द्वारा वहां पर खटारा बसें चलाई गई थी और जो बस वहां पर गई वह ढांक से नीचे गिरी और एक ही गांव के दो जातियों के लोग वहां पर रहते थे, 36 लोग वहां पर मौके पर मर गए। उस समय पूर्व सरकार के मंत्री जिनको उसी समय वहां पहुंचना चाहिए था क्योंकि वहां से मंत्री जी का घर सिर्फ 50 किलोमीटर के करीब था, ये उसके अगले दिन आए। कोई भी सहायता वहां पर नहीं मिली। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जब मैंने लोगों के समर्थन से जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र की कमान सम्भाली माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाया गया और वहां पर जिनकी मृत्यु हुई थी उन सभी लोगों के परिवार को मुआवज़ा मिला और उन परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर, उनकी शिक्षा के आधार पर नौकरी कांग्रेस सरकार ने दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें यहां पर रखना चाहूंगा ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

3.3.2016/1720/av/ag/1

श्री यादविन्द्र गोमा जारी

जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने पैंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया इसके लिए मैं समझता हूं कि यह सभी विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। मगर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने एक बार भी नहीं कहा कि जो आपकी सरकार ने यह पुनीत कार्य किया है हम उसका समर्थन करते हैं। 600 रुपये

पैंशन लेने वाले केवल कांग्रेस पार्टी के वर्कर ही नहीं होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी समान रूप से शामिल हैं। अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत भी आमदन का क्राइटीरिया 35,000 रुपये कर दिया है। कई 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के परिवार सम्पन्न है मगर उनके बच्चे उन्हें खर्चा नहीं देते थे। इसलिए हम सभी विधायकों ने इस बारे में बात की थी और अब मुख्य मंत्री जी ने उनको 1100 रुपये पैंशन दी है। गृह आवास के लिए 48,500 रुपये से 75,000 रुपये की राशि कर दी गई है। मुरम्मत के लिए 25 हजार रुपये का प्रावधान किया है। इसी तरह राजीव आवास योजना के अंतर्गत 1280 तथा इंदिरा आवास योजना के तहत 2128 मकान वितरित किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में शिक्षा में गुणवत्ता लाने तथा प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में फैले हुए इलाकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए नई 21 प्राथमिक पाठशालाएं, 49 माध्यमिक पाठशालाएं, 92 उच्च पाठशालाएं और 58 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं खोली हैं। यहां पर कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से स्कूलों को स्तरोन्नत किया उसी के साथ शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के 878 तथा गैर शिक्षकों के 535 पद सृजित किए हुए हैं। इसी तरह पूरे प्रदेश में हाई एजुकेशन के लिए 17 नये डिग्री महाविद्यालय और 18 निजी महाविद्यालय खोले गए हैं।

यहां पर कुछ बातें स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी की है। यहां पर कहा गया कि बहुत रिक्तियां चली हुई हैं। मगर हमारी सरकार ने अस्पतालों के लिए

3.3.2016/1720/av/ag/2

266 नये पद सृजित किए हैं। इन तीन वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई नई योजनाओं को शुरू किया है और पूरे प्रदेश के हरेक विधान सभा क्षेत्र में समान विकास हुआ है। हमारे विपक्ष के साथी यहां पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रदेश में कोई विकास नहीं हो रहा है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हरेक विधान सभा क्षेत्र में जाकर घोषणाएं की हैं तथा वहां पर नये संस्थान खोले हैं

उसको शायद विपक्ष के साथी पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो राजगीर और थुरल विधान सभा क्षेत्रों में आपकी ही पार्टी के मंत्री और विधायक रहें मगर आप लोग उस इलाके में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करवा सके। मेरे विधायक बनने के बाद जब वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी का दौरा हुआ तो अनेकों स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया। वहां पर कई हाई स्कूलों को सीनियर सैकेंडरी स्कूल, कई मिडिल स्कूलों कों हाई स्कूल और कई प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल किया गया। मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे यहां एक अंदरेटा ग्राम पंचायत है। हमारे कांगड़ा जिले में एक मशहूर पैंटर सरदार शोभा सिंह जी

टीसीद्वारा जारी

03.03.2016/1725/TCV/DC/1
श्री यादविन्द्र गोमा ----- जारी

हुए हैं और उनकी पेंटिंग पूरे विश्व में प्रचलित है। हमारी अंद्रेटा पंचायत पूरे विश्व के मानचित्र में अंकित है। एक बार जब आपके पूर्व मंत्री और मुख्य मंत्री जी वहां से निकले तो लोगों ने वहां पर डिमाण्ड की थी कि इस स्कूल का दर्ज़ा बढ़ाकर इसका नाम सरदार शोभा सिंह के नाम से रखा जाये और इसको अपग्रेड करके +2 किया जाये। इसी तरह से एक बार तो वहां से श्री प्रकाश सिंह बादल जोकि उस समय मुख्य मंत्री थे, वे भी निकले और उन्होंने कहा कि इस स्कूल को मैं अपग्रेड करवाता हूं। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि दो-दो मुख्य मंत्रियों ने इस स्कूल को अपग्रेड करने का आश्वासन दिया। परन्तु यह स्कूल अपग्रेड न हो सका। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब इन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद वहां पर पहली बार दौरा किया, उसी समय इन्होंने इस स्कूल का दर्ज़ा बढ़ाकर सरदार शोभा सिंह के नाम

से किया। इसके लिए वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने भी माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद किया।

Deputy Speaker: Please don't disturb. Please be quite.

जयसिंहपुर में कंवर दुर्गा सिंह के नाम से हमारा जो कॉलेज है, उसके लिए 2007 में माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने बजट दिया था। सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। यह जानकर बड़ा अफ़सोस हुआ कि जहां पर साईंस ब्लॉक का निर्माण होना था, पूर्व सरकार ने उसका साईंस ब्लॉक ही काट दिया। जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाया गया। उन्होंने पिछली सरकार द्वारा इस कॉलेज के निर्माण हेतु जो दो करोड़ की जिम्मेवारी थी उसके अलावा दो करोड़ रूपये साईंस ब्लाक के लिए मंजूर किए। जिसके लिए मैं उनका अपनी ओर से और समस्त जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज हमारा शिवनगर में चलता था। उसको भी स्तरोन्त करके उसका सरकारीकरण कर दिया है। अगर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं तो पिछले तीन सालों में हमारे जयसिंहपुर उप-मण्डल में 50 बिस्तरों का सिविल अस्पताल माननीय मुख्य मंत्री जी ने मंजूर

03.03.2016/1725/TCV/DC/2

किया है। इसके साथ ही पी0एच0सी0, पंचरूखी के विस्तारीकरण के लिए इन्होंने बज़ट दिया है। पी0एच0सी0,भवाणा का विधिवत् उद्घाटन इन्होंने किया है और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पी0एच0सी0, मझेड़ा और रोपड़ी भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मंजूर की है। अभी हाल ही में जब 25 जनवरी का स्टेट-हुड फंक्शन जयसिंहपुर में मनाया गया उस समय भी एक पी0एच0सी, जगरूप नगर इन्होंने मंजूर की है। इसके अलावा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल रोपड़ी में मंजूर किया है। जयसिंहपुर की कानून व्यवस्था को संतुलित रखने के लिए हमारी मांग पर एक एस0डी0पी0ओ0 ऑफिस माननीय मुख्य मंत्री ने देने की घोषणा की है। आगजनी की घटना से निपटने के लिए इन्होंने

जयसिंहपुर के लिए एक फायर स्टेशन भी मंजूर किया है। इस तरह से जैसे हमारे साथी यहां कह रहे हैं कि नाबार्ड के माध्यम से कोई पैसा मंजूर नहीं

श्री आर0के0एस0 द्वारा--- जारी

3.03.2016/1730/RKS/DC/1

श्री यादविन्द्र गोमा...जारी

हो रहा है। लेकिन मैं इस सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि 3 वर्षों के भीतर नाबार्ड के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों, पुलों व पानी की स्कीमों के लिए इस समय तक 30 करोड़ रुपया मंजूर करवा दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 10 करोड़ रुपये की ओर स्वीकृति की है। जिसे 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विपक्ष के लोगों को भी इस बात का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने 10 करोड़ रुपये का इजाफा करवाया है। जिस तरह से यहां पर बातें हो रही हैं कि कांग्रेस सरकार के समय में तीन सालों के भीतर आधी-अधूरी बिल्डिंगों का उद्घाटन किया जा रहा है । मैं आपको इसका जीता-जागता प्रमाण देता हूं। एक मिनी सचिवालय जयसिंहपुर में कांग्रेस सरकार द्वारा मंजूर किया गया था। जब इलैक्शन आ रहे थे तो आपकी सरकार ने आनन-फानन में उसका उद्घाटन कर दिया था। जबकि उसमें बाऊंड्री वॉल भी नहीं लगी थी। उसका एक फ्लोर बनना बाकी रह गया था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जब वे दौरे में गए तो उन्होंने उस मिनी सचिवालय की चार दिवारी और उसके पूरे कम्पलिशन के लिए पैसे मंजूर करवाए। इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में वाटर सप्लाई और सिंचाई स्कीमों के लिए भी बजट उपलब्ध करवाया है। जो हमारी अनुसूचित जाती की पंचायते हैं। एस.सी.पी. के माध्यम से भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में 5 से 8 करोड़ के बीच में नई स्कीमें संचालित की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंन कांग्रेस पार्टी की नई योजनाओं, नई स्कीमों और विकास के बारे में इस सदन को अवगत करवाया है। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं कि 3 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। का मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अंत में, मैं भगवान से यही प्रार्थन करता हूं कि इनको अच्छी

बुद्धि दें। जो विकास हिमाचल में 3 वर्षों में हुआ है उसे देखने के लिए भी दिव्य दृष्टि दें और जो विकास आगामी दो वर्षो में होगा उसे देखने के लिए भी इनको दूरगामी सोच दें । इसी बात के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्वाद करता हूं। आपने मुझे समय दिया इसके लिए मै आपका धन्वाद करता हूं।

जय हिन्द, जय हिमाचल।

3.03.2016/1730/RKS/DC/2

उपाध्यक्षः श्री विजय अग्निहोत्री।

श्री विजय अग्निहोत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 फरवरी 2016 को महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया और उसमें माननीय सदस्य श्री जगजीवन पॉल ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुसमर्थन श्री अजय महाजन जी ने किया उस चर्चा में बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्य श्री जगजीवन पाल जी ने जब धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो एक आध मिनट के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया कि हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनका बहुत प्रभाव होना शुरू हो गया है। जिस कारण यहां विकास शुरू नहीं हो पा रहा है। पंजाब में नशा बढ़ गया और

श्री एस.एल.एस.....द्वारा जारी

03.03.2016/1735/SLS-AG-1

श्री विजय अग्निहोत्री ...जारी

और उस नशे का इम्पैक्ट अब हिमाचल प्रदेश में होना शुरू हो गया है। पड़ोसी राज्यों में जो हो रहा है वह तो हो रहा है लेकिन जो इस प्रदेश में हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी किसकी है, उसको रोकने का काम किसने करना है? इस अभिभाषण से हमें लगता है कि इस सरकार की उम्र एक साल और बढ़ गई, 3 साल हो गई। इसमें अवधि ही अवधि है, उपलब्धि कोई नहीं है। जिस क्षेत्र की बात करें; चाहे सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य

हो, उद्योग हो, कल्याण विभाग हो या बिजली विभाग हो; किसी भी सैक्टर की अगर बात करें तो पिछले 3 वर्षों में कोई उपलब्धि नहीं हुई है।

शिक्षा के बारे में यहां पर चर्चा हुई कि इतने स्कूल खुले, इतने स्तरोन्नत हुए, ...(व्यवधान)... पठानिया जी, आपके विभाग की तो इतनी बुरी हालत है कि अगर किसी ने पोल चेंज करवाना हो तो कहते हैं कि पहले पोल के पैसे जमा करवाओ, मज़दूर लेकर आओ, खड्डा खोदो और यह सब करने के बाद भी खम्बा बदला नहीं जाता; गाडा नहीं जाता। अगर ट्रांसफार्मर चाहिए तो उसके भी पैसे जमा करवाओ। ...(व्यवधान)... क्या 4.00 लाख से 200 KV का ट्रांसफार्मर आता है?

मैं शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहा था। आपने कहा कि इतने स्कूल स्तरोन्नत हो गए और कॉलेज खुल गए। आपने न देखा न सोचा, रूसा शुरू कर दिया । मैं आज अख़बार पढ़ रहा था। देखा कि विश्वविद्यालय के कुलपति दिल्ली गए हैं। मैंने नीचे पढ़ा कि किसलिए गए हैं। इसलिए क्योंकि हमारे यहां से जो ग्रेजुएट निकल कर गए हैं उनको बाहर की युनिवर्सिटीज एडमिशन नहीं दे रही है; उनको मान्यता नहीं मिल रही। फिर आप कहते हैं कि हमने शिक्षा का स्तर सुधार दिया, हमने शिक्षा में गुणवत्ता ला दी जबकि आज बाहर की युनिवर्सिटीज में हमारे बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिल रही है। यहां पर पिछले 3 वर्षों में शिक्षा का भट्ठा बैठा है। आदरणीय धूमल जी ने अपने भाषण में रजोल और रामनगर स्कलों का ज़िक्र

03.03.2016/1735/SLS-AG-2

किया। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के हैं। आप सर्वेक्षण करवा कर देख लो, बहुत से प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें पहली में या दूसरी में कोई बच्चा नहीं है। फिर अगले साल तीसरी में नहीं होगा और फिर चौथी में भी नहीं होगा। फिर वह बंद हो जाएंगे। यह क्यों हो रहा है, इसके बारे में चिंता नहीं है। हम नए खोलते जा रहे हैं। जी.पी.एस. अमरोह पिछले 2 साल पहले बंद हो गया। उसका स्टॉफ इधर-उधर भेजना पड़ा। वहां 3-4 स्कूल और बंद होने के कगार पर हैं। पूरे प्रदेश में यही हाल है। आप नए स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं जबकि पुराने बंद हो रहे हैं। आपने 1:20 स्टूडैंट टीचर रेशो रखी है जबकि आपके पास स्कूल 10 बच्चों वाले हैं और क्लासें 5 हैं, वहां आप कितने अध्यापक लगाएंगे? आप क्लास टीचर रेशो रखो। मैने पिछली बार भी कहा था कि अगर आपने शिक्षा का स्तर

बढ़ाना है, बच्चों में कंपीटिशन स्पिरिट लानी है, उनका बौद्धिक विकास करना है तो इन छोटे-छोटे स्कूलों को क्लब करो। इनको क्लब करके इनमें स्ट्रैंथ ठीक हो, अध्यापक ठीक हों तो फिर उनको व्हीकल सुविधा दो और दुसरी सुविधाएं भी दो। आप कहते हैं कि फलां इंटिरियर क्षेत्र है वहां स्कूल ज़रूरी है। वहां बोर्डिंग स्कूल शुरू करो; वहां बच्चों को रखो और पढ़ाओ, तब इनका स्तर उन्नत होगा। आप कहेंगे कि हमने प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल की बिल्डिंग में कॉलेज शुरू कर दिया। वहां न तो टीचर न पढ़ने का माहौल होता है और न कोई दूसरी सुविधा होती है। आप रूसा थोपे जा रहे हैं लेकिन न रूसा के सब्जैक्ट कंबीनेशन ठीक है और न रिजल्ट ठीक है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जबकि आप कहते हैं कि हम शिक्षा को बहुत ऊपर ले गए हैं।

जारी ...श्री गर्ग जी

03/03/2016/1740/RG/AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री-----क्रमागत

इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो बुरा हाल आज प्रदेश में है वह इसलिए है कि हमने बहुत ज्यादा स्कूल अपग्रेड कर दिए, बहुत ज्यादा स्कूल खोल दिए, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज आप बच्चों में क्या कैलिबर पैदा कर रहे हैं, और बच्चों के कैलीबर को कितना निखार पा रहे हैं, उसके अन्दर कितना सैल्फ-कॉन्फिडैंस ला रहे हैं और इस प्रतियोगिता के युग में आप उसको कहां खड़ा कर पा रहे हैं? इसलिए ये जो पिछले तीन वर्षों में आपने किया है चाहे वह 'रूसा' के माध्यम से हो, चाहे वह मशरूम ग्रोइंग इन्स्टीटियूशन्ज की बात हो, इस प्रकार से शिक्षा का कोई सुधार होने वाला नहीं है। मैडिकल कॉलेज की बात आई कि तीन मैडिकल कॉलेज हमने खोल दिए। जिस दिन सरकार जा रही थी उस दिन आपने कॉलेज की नोटिफिकेशन कर दी। फिर स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे कि Government in continuity. हमने घोषणा की और आपने पैसे दिए। तो भाई श्री बिक्रम सिंह जी किसके लिए रो रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं।

हमारी सरकार के समय में जो कॉलेज घोषित हुए थे, आपने कहा कि इसमें कोई पैसा नहीं है, हम इनको कैन्सिल करते हैं। इसलिए जो हम करें, वह continuous नहीं है और आप मनमर्जी करें, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा कि हम खांसें, तो खांसी और आप खांसें, तो अदा। इसलिए यहां दोहरे मापदण्डों की बात हुई है। आप कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। भेदभाव कहां नहीं हो रहा है? जय राम ठाकुर जी ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं, कहां-कहां जाते हैं, वे सारी बातें हुईं। लेकिन जहां तक भेदभाव की बात है, तो कोई कांग्रेस का विधायक है उसके पिछले तीन वर्ष की विधायक प्राथमिकता की डिटेल निकाल लो, उसकी कितनी डी.पी.आर्ज. बन गई हैं और यहां जो बैठे हुए लोग हैं उनकी डी.पी.आर. निकालो, कम्पेरीजन हो जाएगा कि भेदभाव हो रहा है या नहीं। जहां आपके विधायक नहीं हैं वहां आपने समानान्तर सरकार चला रखी है कि वह व्यक्ति बोलेगा, तो काम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पंचायत चुनावों के बारे में बात हुई कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुए और बहुत फेयर हुए। आप कहते हैं कि आप 70-75 या 77% सीट जीत गए। तो ऐसी ही सारी स्थिति है, आप सिर्फ 10 या 20% जीते हैं। एक बात की मैं और गारन्टी देता हूं कि अगर आपने उन चुनाव कराने वाले कर्मचारियों को मैनेज नहीं किया होता, आपकी इन्टरफेयरैन्स नहीं होती, आप खरीद-फरोख्त नहीं करते, तो जो आपके उम्मीदवार जीते हैं वे भी न जीतते। आज भी री-कॉउन्टिंग

03/03/2016/1740/RG/AG/2

करवा कर देख लेना जो डिब्बे हैं उनको खुलवाकर देखेंगे, तो आज आपके और भी उम्मीदवार हारेंगे। बी.डी.सी. में आपने खरीद-फरोख्त की। बी.डी.सी. आप कैसे जीते? हम जीते, वाईस चेयरमैन हमारा बना। लेकिन बी.डी.सी. चुनावों में जो आपकी इन्टरफेयरेंस हुई, यहां पूरे प्रदेश में ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं होगा जिस दिन बी.डी.सी. के चेयरमैन और वाईस-चेयरमैन का चुनाव होना था उस दिन वहां कोरम पूरा नहीं हुआ और कहा गया कि अगली डेट बाद में बताई जाएगी। फिर हम उन अधिकारियों के पास गए, एस.डी.एम. और तहसीलदार से बात की और पूछा कि आप अगली डेट क्यों नहीं दे रहे? वे बोले कि ऊपर से फोन नहीं आया कि कब वे फ्री हैं, उस ढंग से डेट देंगे।

आपकी सरकार में यह चल रहा है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और लोग ही सरकार चला रहे हैं। पहले वाईस-चेयरमैन का चुनाव हुआ, नदौन में पहले चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसकी गिनती करवाई, उसका परिणाम घोषित किया, फिर उसके पश्चात वाईस चेयरमैन का चुनाव किया। ऐसा कभी हुआ है? यह इन्टरफेयरेंस नहीं, तो और क्या है? उस सबके बावजूद भी मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में चार जिला परिषद वाड्र्स हैं। आप एक पर जीते हैं और वह भी 600 वोटों से। जो हारे हैं उनमें से एक 4500 वोटों से, एक 2400 वोटों से हारा है और एक तो तीसरे स्थान पर गया है जिसकी तो गिनती ही क्या करनी है? आप कहते हैं कि हमने 70% सीटें जीत ली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में नशे के बारे में बात हुई। इस प्रदेश में नशे से बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो रही है।

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2016/1745/MS/AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी----------

स्कूल जाने वाले बच्चे नशा कर रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी इसका बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। दुःख इस बात है कि मैंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, एस0पी0 को, एस0एच0ओ0 और डी0एस0पी0 को नाम लेकर बताया कि फलां व्यक्ति ऐसे-ऐसे धन्धे करता है, शराब बेचता है बच्चों को गांव में 5-5 और 10-10 रुपये की शराब बेचता है। दो साल हो गए धर्माणी जी उनको पकड़ना तो दूर जब वहां पुलिस की गाड़ी भी आती है तो उनको पता होता है कि आज इधर से फलां जगह के लिए जा रहे हैं। आज ये एडमिनिस्ट्रेशन है और आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस है। मेरे गांव का एक बच्चा ड्रग्स लेकर मर गया और तीन लोगों को पिछले दो सालों के अंदर नशा निवारण केन्द्र में भर्ती करवाना पड़ा। यह अलार्मिंग स्थिति पूरे उस एरिये की है। जहां

हम बताते हैं कि यहां यह धन्धा हो रहा है उनको प्रोटैक्ट कर किया जाता है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन उनसे हफ्ता लेता है। हम यहां बातें करते हैं कि पंजाब में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पंजाब को आप साइड में रहने दो। आप अपने प्रदेश और क्षेत्र को देखो कि हम कहां जा रहे हैं। "देवभूमि" कहलाए जाने वाले हिमाचल प्रदेश में आज जितनी ड्रग एडिक्शन हो रही है मुझे नहीं लगता किसी अन्य राज्य में इतनी हो रही होगी। यूथ कहीं पर हमारा पुलियों पर बैठा हुआ सुट्टे लगा रहा है। मैंने सोचा कि इसको जुकाम हुआ होगा लेकिन बाद में पता चला कि वह फ्ल्यूड सूंघ रहा है। कोई भांग पी रहा है, कोई कैप्सूल खा रहा है, कोई आयोडैक्स खा रहा है और कोई बूट पॉलिश ही खा रहा है। जिसकी जितनी हैसियत है उस ढंग से वह लगा हुआ है लेकिन प्रशासन चुप है।
आज प्रदेश में खनन माफिया सक्रिय है। पूरे प्रदेश में यही हाल है और मेरे चुनाव क्षेत्र में भी हाल बहुत बुरा है। वहां जे0सी0बी0 के साथ खड्डों को खोदा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है और पानी की विकट समस्या हो रही है। मेरे क्षेत्र में दो खड्डें हैं जिनमें एक मान खड्ड और दूसरी कुणाह खड्ड है। ये दोनों खड्डें आज सूखने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। एक मान खड्ड में तो पानी मार्च महीने के बाद बहता ही नहीं है। पानी कहीं यहां मिलता है फिर दूसरी जगह मिलता है और फिर तीसरी जगह जाकर मिलता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टोन क्रशर जे0सी0बी0 के साथ अवैध खनन कर रहे हैं। वहां पर

03/03/2016/1745/MS/AG/2

अनसांईटिफिक खनन हो रहा है। वहां के कई ठेकेदार कहते हैं कि हमने डम्प खनन की परमिशन ली है। पिछले एक साल में उन्होंने लाखों मीट्रिक टन वहां से मटीरियल उठा लिया है क्या उनका डम्प ही खत्म नहीं हो रहा है? मैं यह चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके विभाग के लोग, आपके मंत्री या आपका कोई भी व्यक्ति मेरे साथ वहां चले। मैं उन दोनों खड्डों में घूमकर बताता हूं कि किसका कहां डम्प है।
इसी तरह से रिवर बैड पर एन0जी0टी0 ने कहा कि वहां पर स्टोन क्रशर नहीं चलेगा लेकिन हमारे यहां सारे-के-सारे स्टोन क्रशर रिवर बैड पर जा रहे हैं और पुल के पास-पास लगे हुए हैं। वहां का पानी मिट्टी के रंग का हो गया है। फिर कह रहे हैं कि इन तीन सालों में हमने बड़ी-भारी छलांग लगा दी। एक भी चीज का बता दो जिसमें आपने

कन्ट्रोल किया है। चाहे वह खनन है, वन काटने की बात है या शराब और ड्रग माफिया की बात है। मैं कहता हूं कि सरकार कहां है? और तो और दो-तीन दिन पहले मैट्रोपोल के लिए कहा कि येलो लाइन लगा देंगे। आप लोगों के कहने से तो चार दिन में वह नहीं लगी। फिर कहते हैं कि सरकार चला रहे हैं। -(व्यवधान)- नहीं तो सरकार छोड़ दो। हम करवाकर बताते हैं। फिर कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। माननीय कृषि मंत्री जी आपने पिछले तीन सालों में इस प्रदेश में कृषि के लिए और इस प्रदेश के युवाओं को खेत तक पहुंचाने के लिए कौन से इन्सेंटिव दिए या उनके ऊपर कौन सा फोलोअप किया? आज नशे और बेरोजगारी की समस्या के पीछे अगर कोई कारण है तो वह कारण यह है कि आज हमारी आने वाली जनरेशन को खेत का पता ही नहीं है। वे खेत में जाते ही नहीं हैं और वे खेत में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। -(व्यवधान)- तीन सालों से तो आपकी जिम्मेदारी है। पिछली सरकार के समय में कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उछाल आया था। पिछली सरकार के समय में पॉली हाउसिज लगने शुरू हुए और "दीन दयाल उपाध्याय किसान/बागवान समृद्धि योजना" आई। तब लोगों में इसके प्रति इंट्रस्ट पैदा हुआ था लेकिन आपने पिछले तीन सालों में कुछ नहीं किया। आप इस प्रदेश के युवा को यदि खेत तक नहीं पहुंचाएंगे तो कुछ नहीं होगा। -(व्यवधान)- क्रशर बन्द हो गए थे अब शुरू हुए हैं। वे ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद करवा दिए थे। अभी दो महीने पहले दुबारा शुरू किए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

03.03.2016/1750/जेएस/एएस/1

श्री विजय अग्निहोत्रीः--------**जारी**-------

तीन, चार-चार महीने, वे बन्द क्रशर भी रात को आपके खम्भों से बिजली को कुंडी लगा करके चलाते रहे। वहां आपके विभाग के लोग मिले रहे। मीटर कट गया लेकिन क्रशर चलते रहे। मंत्री जी, आपके पास मैं नाम लिख करके दे दूंगा । इस प्रदेश के युवा को खेल और खेल के मैदान में पहुंचाने की कोशिश करो। अगर कुछ करना है। जब इस प्रदेश के युवा के मन में थोड़ा सा मादा हो जाएगा कि मैं पसीना बहा सकता हूं, मैं खेत

में जा सकता हूं, मैं खेल के भी मैदान में जा सकता हूं तो उसे नशे से भी छुटकारा मिल जाएगा, बेरोजगारी से भी छुटकारा मिल जाएगा और यह प्रदेश आगे बढ़ेगा। सारी की सारी अराजकता खत्म हो जाएगी। जहां तक सिंचाई विभाग की बात है मेरे वहां एक बहुत बड़ी सिंचाई की स्कीम का काम चला हुआ है और आदरणीय धूमल जी ने उसका शिलान्यास किया था । वह काम थोड़ा आप लोगों ने लेट किया था लेकिन वह चल रहा है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कोहला-मझयार-सेरा फेज़-I,II,III बहुत बड़ी सिंचाई की योजना है जिसका काम 2002 में शुरू हुआ। वर्ष 2010-11 में मैंने वहां उनको कहा कि इसे जनता को समर्पित करने की तैयारी करो क्योंकि इसका काम पूरा हो गया है। वे कहते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा काम बचा है, उसके बाद उद्घाटन करवा देंगे। अभी तीन वर्ष से उसका लोकापर्ण नहीं हो सका। उसके ऊपर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? करोड़ों रूपया उसके ऊपर लग चुका है लेकिन पानी अभी तक खेत तक नहीं पहुंच पाया है। वहां हेण्डपम्प लगाए जाते हैं तो कई जगह 10-10, 15-15 मीटर की दूरी पर लग जाता है, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां पर हेण्डपम्प नहीं लगता है। हालत यह है यानि सरकार में रहने वाले लोगों से अभी तक यलो लाईन नहीं लगी लेकिन वहां पर जो नेता हैं उनके कहने पर सारे काम होते हैं। मैंने अपनी विधायक निधि से हेण्डपम्प लगाने के लिए पिछले साल कुछ पैसे दिए। वे भी नहीं लगावाए। वे भी लड़-लड़ करके अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं। लोक निर्माण विभाग को विधायक निधि से पैसा जाता है और दो-ढाई साल तक उसके टेण्डर नहीं होते हैं। टेण्डर होते हैं तो ठेकेदार को जा करके बोला जाता है कि इसका काम आपने शुरू नहीं करना है । जब कोई काम

03.03.2016/1750/जेएस/एएस/2

शुरू कर देता है तो उस ठेकेदार की पेमैंट रुक जाती है या फिर कोई अधिकारी ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसकी बदली हो जाती है। पंचायत चुनावों में भी ऐसा ही हुआ। वहां पर बोला गया कि वोट आपने देना है तो दो। वहां पर बी0डी0सी0 बनी। एक वहां

पर बैंक में लगा था और उसको कहा गया कि एक लाहौल-स्पिति में भी बैंक है। एक वहां पर बी0डी0सी0 मेम्बर प्राईवेट स्कूल चलाती है उसके वहां बी0पी0ओ0 गया, वहां डिप्टि डायरैक्टर गया, उन सबने उसको वहां पर बैठ कर डराया कि अगले अप्रैल से अपना स्कूल आप बन्द समझो। ये सरकार चला रहे हैं? वन माफिया, खनन माफिया और शराब माफिया को रोकने के लिए उपाध्यक्ष महोदय सरकार के पास कोई मज़बूत तंत्र नहीं है लेकिन यदि किसी बी0जे0पी0 के व्यक्ति को डराना हो उसके ऊपर केस बनाना हो, उसके ऊपर भेद-भाव करना हो और कालिया जी यही कह रहे थे कि मेरे साथ बड़ा भेद-भाव हुआ था और मेरे ऊपर केस बना दिए। मैं बताता हूं पिछले दो वर्षों में भारतीय युवा मोर्चा मण्डल का जो अध्यक्ष है उसके ऊपर इन्होंने केस बनाया। वहां का जिला परिषद सदस्य था उसके ऊपर केस बनाया। ऐसे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता जो भी काम करता है उनके ऊपर झूठे केस बना करके फंसाया जा रहा है और डराया जा रहा है। ये कानून व्यवस्था है। लेकिन जहां जरूरत होती है, एक आदित्य पिछले साल से गुम है उसका आज तक पता नहीं चला। अभी पिछले 4-5 दिन से एक भट्टा नाम गांव है उसमें दसवीं में पढ़ने वाला एक छात्र वहां से गुम है और मुझे यहां पर फोन आया कि वह तीन दिन से गुम है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

03.03.2016/1755/SS-DC/1

श्री विजय अग्निहोत्री क्रमागतः

एफ0आई0आर0 दर्ज़ नहीं है। मैंने एस0एच0ओ0 को फोन किया। बोले कि पता नहीं लोग बोलते हैं कि भंगड़ था शायद खुद ही चला गया। मैंने कहा कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं? अगर किसी का बेटा गु म हो गया है तो ये लॉजिक देते हैं कि पता नहीं, भंग पीता था, इसलिए कहीं चला गया होना। तो ऐसी कानून-व्यवस्था मेरी कांस्टीचुऐंसी में है।

अगर मेरी कांस्टीचुऐंसी में सबसे बड़ी समस्या है तो वह सड़कों की है। हर सड़क खड्ड बन चुकी है। एक तो उपाध्यक्ष महोदय इन जैम्मरों को ठीक करवाओ, बीच-बीच में फोन बज जाता है। ये सरकार की तरह ही चल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे वह

रंगस-धनेटा सड़क की बात हो, चाहे वह कांगू-मालग जसाई होते हुए धनेटा जाने वाली सड़क की बात हो। चाहे वह पन्याली-माजरा-डोहग सड़क की बात हो। गलोड़ से फाहल-टिप्पर जाने वाली सड़क हो। गलोड़-गाहलियां-दांदड़ू जाने वाली सड़क हो। चाहे वह जियाणा-सुकराला हो। चाहे वह नादौन-गौना-बसारल-धनेटा वाली सड़क हो। भट्ठा से सलौणी सड़क है। रंगस से बड़ा है। हर सड़क की बहुत बुरी हालत है। मैं एक और बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो सड़कों के लिए रिपेयर एंड मैटीनैंस का पैसा जाता है, यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। पैसा जाता है, हम प्रश्न पूछते हैं तो बोलते हैं कि इतने लाख रुपया इस सड़क पर लगा दिया। लेकिन वास्तव में वहां कुछ होता नहीं है। जब वहां की इंक्वायरी करेंगे तो बोलेंगे कि बरसात में बह गया। इस करके इन सड़कों की बहुत बुरी हालत है। पिछले तीन सालों से रिपेयर और मैंटीनैंस में कुछ नहीं हुआ। किसी सड़क की टारिंग नहीं हुई है। इसलिए मैं इन सड़कों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनकी हालत ठीक कर दीजिये। सरकारी बसें तो बंद हैं। एक रूट हमीरपुर-होशियारपुर वाया धनेटा नेहरी होते हुए जाता था, वह बंद हो गया। एक हमीरपुर-धनेटा पंचधाम बस थी। एक हमीरपुर वाया गालियां थीं। ये सब बसें बंद हो गईं।

Deputy Speaker: Please wind up.

03.03.2016/1755/SS-DC/2

श्री विजय अग्निहोत्रीः सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। लेकिन प्राइवेट बसें जो वहां पर चलाते हैं, प्राइवेट बस ऑपरेटर मेरे पास कई बार आये कि इन रोडों की हालत सुधार दो नहीं तो हम भी बसें बंद कर देंगे। दो प्राइवेट रूट भी वहां बंद हुए हैं। इस करके वहां पर सड़कों के बारे में ज़रूर ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां नाबार्ड के तहत बहुत सालों से एक सड़क बन रही है। चार साल पहले वहां पर टैंडर हुआ है। उस सड़क का नाम मैड़ से टिक्कर वाया जियाना-सुकराला है। उस ठेकेदार ने पिछले चार सालों में कोई काम ही नहीं किया है। मैंने बार-बार कहा। बार-बार एस0ई0, एक्सियन, एस0डी0ओ0 से बात की। विधान सभा में बात की। प्लानिंग की मीटिंग में बात की। लेकिन पिछले चार साल से उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। आदमी चाहे खास हो या न हो, लेकिन वह कभी कोई बहाना करता है और कभी कोई बहाना करता है।

ऐसे ठेकेदारों के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उस काम को rescind क्यों नहीं कर रहे हैं? जो काम पहले ढाई करोड़ रुपये में होना था, अब साढ़े चार करोड़ रुपये में होगा। एक वहां सड़क बनी - पंसाई-भूम्पल वाया मझेली। दोनों ऐजिज़ पर पुल बनने हैं। वे पुल नहीं बने। बीच की सड़क बन गई, पक्की हो गई और साढ़े तीन करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो गया। लेकिन चार सालों से उसके ऊपर एक भी पुल नहीं बना। वह सड़क किस काम की जब वह कहीं मिली ही नहीं। कोई वहां जाता नहीं है। वह जंगल से चली और जंगल में खत्म हो गई। इस करके इन सड़कों के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है।

Deputy Speaker: Please wind up now.

श्री विजय अग्निहोत्री: बिल्कुल सर, वाइंड अप कर रहा हूं। स्वास्थ्य सुविधाओं की जहां तक बात है पिछले तीन सालों से पी0एच0सी0 कांगू की बिल्डिंग बन कर तैयार हो गई है। उसे थोड़ा-सा ठीक करना था। पीछे मैंने प्रश्न किया था तो बोला था कि पिछले सितम्बर में यह शुरू हो जायेगी। लेकिन आज तक वह शुरू नहीं हो पाई है।

108 एम्बुलैंस का हाल बहुत बुरा है। पीछे धनेटा में एक केस हुआ --(व्यवधान)-- सरकार का हाल भी वैसा ही है। 108 के लिए फोन किया। एम्बुलैंस सेवा आधे घंटे के अंदर मिलती है। लेकिन वह दो घंटे के बाद आई। उस वक्त तक धनेटा में लेडीज़ की मौत हो गई।

03.03.2016/1755/SS-DC/3

Deputy Speaker: Now I not going to record it. आप बैठ जाईये। Otherwise it will not be recorded.

श्री विजय अग्निहोत्री: सर, मैं दो मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं। जहां तक पैंशन की बात है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की।

जारी श्रीमती के0एस0

3.03.2016/1800/केस/एएस/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी----

आपने एक बार बढ़ाई उसके लिए आपका धन्यवाद लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि 80 साल के लोगों की हमने पैंशन शुरू कर दी। आपने शुरू तो कर दी लेकिन नम्बर ऑफ पैंशन आपने कहां बढ़ाया? उसमें बजट कहां बढ़ाया आपने? कितने 80 साल के लोगों को आऊट ऑफ द वे उनकी अलग से वरिष्ठता सूची बनाई? उनको पहले दी जाए या कब दी जाए यह कुछ भी नहीं है और जो मरता है उसी को पैंशन लग रही है। कई दो-दो साल से इंतज़ार कर रहे हैं। 80 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों की कौन सी प्रायोरिटी लिस्ट आपने बनाई है? 1100 रु0 देने की घोषणा कर दी लेकिन पर्ची पर लिख कर गुजारा नहीं चलेगा।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, समाप्त करें। अगले वक्ता श्री नरेन्द्र ठाकुर। अग्निहोत्री जी, कृपया बैठ जाएं और इस माननीय सदन की बैठक एक घण्टे के लिए और बढ़ाई जाती है।

श्री विजय अग्निहोत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

3.03.2016/1800/केस/एएस/2

उपाध्यक्षः श्री नरेन्द्र ठाकुर।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष जी, 25 फरवरी को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव श्री जगजीवन पाल जी ने रखा और माननीय सदस्य श्री अजय महाजन जी ने जिसका अनुमोदन किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा उसके बाद सत्ता पक्ष के जो भी माननीय सदस्य यहां पर बोले, उन सभी ने उसको बार-बार पढ़ा और इसकी प्रतिलिपि हमें भी दी गई और हमने भी इसको पढ़ा और स्थिति यह आ गई कि हमें यह जुबानी याद हो गया है। इस अभिभाषण में ऐसा कुछ भी नहीं है । जो प्रोग्रैस रिपोर्ट यहां पर पिछले दो सालों की रखी गई है इसमें न कोई सोच है, न कोई नयापन है न कोई ऐसी

पॉलिसी है जिस पर डिटेल में चर्चा की जाए। मैं समझता हूं कि जब से हिमाचल प्रदेश राज्य बना उस समय एक नक्शा खींचा गया, एक ट्रैक बना कि इसके ऊपर इस प्रदेश की डवैल्पमैंट होनी है और वर्तमान सरकार उसी ट्रैक पर चली हुई है और स्पीड भी बहुत धीमी है जैसे शिमला-कालका रेल चलती है। परन्तु यह सरकार भूल गई है कि अब बुलेट ट्रेन भी बन गई है, उससे ज्यादा रफ्तार की ट्रेनें भी बन गई है। इस सरकार ने अपनी कार्य पद्धति नहीं बदली है और हर क्षेत्र में यह सरकार बिल्कुल असफल ही नहीं बल्कि असहाय नज़र आ रही है। सत्ता पक्ष वाले बड़ी जोर-शोर से बोल रहे हैं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में पहले 100 हैंडपम्प थे अब 105 हो गए, मेरे चुनाव क्षेत्र में पहले 50 स्कूल थे, अब 52 हो गए, पांच पी.एच.सी. थीं अब छः हो गई और बार-बार कह रहे हैं कि सारी की सारी कृपा माननीय मुख्य मंत्री की है, हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उनकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है ।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

3.3.2016/1805/av/ag/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी

आपके बोलने से तो यह लग रहा है कि आपमें से कोई भी चुना हुआ सदस्य नहीं है। आप टोटली माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर डिपैंड कर रहे हैं। आप इतनी ज्यादा चापलूसी क्यों कर रहे हैं? हमारे माननीय सदस्य श्री बिक्रम जी ने ठीक कहा कि अब मंत्री मण्डल में कोई ऐक्सटैंशन नहीं होनी है। आप जो कृपा-कृपा वाली बात कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा कृपा तो निर्मल बाबा ने करनी थी अगर आप उनके पास जाते। आपको दो समोसे की जगह चार देते, लड्डू देते, कुछ न कुछ तो देते। यहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहां पर आज के बेसिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा ऐसे मुद्दों पर होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश की इकॉनोमी कैसे सुदृढ़ हो। हमारे लोगों की पर-केपिटा इनकम कैसे बढ़े। हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़े और जो यहां पर लाखों पढ़े-लिखे बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार कैसे तलाशा जाए।

शहर और गांव का वातावरण कैसे स्वच्छ बने। शिक्षा में कैसे सुधार हो तथा हर गांव को कैसे पक्की सड़क जाए। यह जो महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा पढ़े गये अभिभाषण की पत्रिका हमें दी है और आप जो सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं इस मुद्दे पर आप किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने आपको सजैशन दी है, आज जमाना बदल चुका है। वक्त के साथ चलना सीखो। आज की सबसे बड़ी समस्या कृषि है। हमारा हर व्यक्ति डायरैक्टली और इनडायरैक्टली यानि कम से कम 70 प्रतिशत लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। खासकर बागवान अभी थोड़े-बहुत बचे हुए हैं। मगर जिस ढंग से यह सरकार काम कर रही है वे भी कुछ समय बाद सर्वाइव करने वाले नहीं है। हमारे कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में कृषि पूर्णतया खत्म हो चुकी है। सिर्फ गेहूं की थोड़ी-बहुत फसल होती है। इस बार तो वह भी कुछ खास नहीं है क्योंकि वर्षा कम हुई है। आप कोई भी फसल ले लो, प्रदेश में कृषि पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहां हाउस में इस बारे में बार-बार डिसक्शन हो रही है। मुझे भी इस सदन का सदस्य बने हुए 20 महीने का समय हो गया है। इसके कारण क्या है? कृषि खत्म क्यों हो रही है, इस बारे में चर्चा नहीं हो रही है।

3.3.2016/1805/av/ag/2

सरकार ने प्रदेश में क्या किया? यहां पर समस्या क्या है, इस बारे में सबको पता है मगर हमारी सरकार ने इसके लिए कोई ड्रास्टिक स्टैप नहीं लिया है। यह कोई हिमालय पर्वत नहीं है जो चढ़ा न जाए। बंदरों, स्ट्रे एनिमल्ज और जंगली जानवरों से क्या हम अपनी फसलों को नहीं बचा सकते? इस समस्या से हम किसानों को बाहर निकाल सकते हैं मगर सरकार में काम करने की ज़ील होनी चाहिए। कल यहां पर वन मंत्री जी बोल रहे थे कि यहां पर बंदरों की संख्या 48,000 कम हो गई है। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोई बंदर मरा है? उनका सिर्फ स्टरलाइजेशन हुआ है। स्टरलाइजेशन से बंदर मरता नहीं है। उसके बाद भी और पैदावार हो रही है और मरा हुआ बंदर तो हमें कोई नहीं मिला। हमने बाहर भी कोई नहीं भेजा तो इनकी संख्या कम कैसे हो गई? ऐसा गुप्त नुस्खा क्या है जिससे बंदरों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। आप ये गलत आंकड़े क्यों दे रहे हैं? मेरा सरकार से निवेदन है कि एक ड्रास्टिक स्टैप लेकर 5-6

महीने या एक साल के अंदर-अंदर इस समस्या को दूर करने के लिए अगर ऐक्स्ट्रा बजट भी खर्च करना पड़ रहा है तो कीजिए ताकि इससे निजात मिले। नहीं तो हमारे जो 70 प्रतिशत लोग डायरैक्टली और इनडायरैक्टली कृषि के साथ जुड़े हुए हैं उनके पास कोई चारा नहीं है। हमारे किसान डिपुओं पर निर्भर हो रहे हैं और यह इंतजाम तो टैम्परैरी है। भारत सरकार जो करोड़ों रुपये सब्सिडी पर खर्च कर रही है यह टैम्परैरी अरेंजमैंट है।

टी सी द्वारा जारी

03.03.2016/1810/TCV/DC/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर ----- जारी
परमानेंट अरेंजमेंट तो तभी होगा यदि कृषि को, बन्दरों, स्ट्रे एनिमल और जंगली जानवरों से बचाने का कोई न कोई प्रबंध किया जाये। वरना कृषि हमारे प्रदेश से जा रही है। दूसरे, शिक्षा के क्षेत्र के बारे में इस सदन में बड़ी चर्चा हो रही है। हमारे स्कूल अपग्रेड कर दिए गये हैं और हमारी शिक्षा का बुनियादी ढांचा हिमाचल प्रदेश में काफी फैल चुका है। हर जगह स्कूल खुल चुके हैं। लेकिन ज्यादा स्कूल खोलने से आज कुछ नहीं होने वाला है। आज जो स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है उसका युज़ क्या है। मैं जगजीवन पाल जी (मुख्य संसदीय सचिव) से सहमत नहीं हूं कि यह जो नशा है, यह हिमाचल प्रदेश में पंजाब से आ रहा है। लेकिन स्कूलों में हम जो शिक्षा दे रहे हैं, यह नशा इस शिक्षा से बढ़ रहा है। हमारे हमीरपुर जिला के जो डी0सी0, श्री रोहन जी थे, उन्होंने बच्चों का कैलीवर देखने के लिए स्कूलों का औचक दौरा किया। आप हैरान होंगे कि नवीं और दसवीं के बच्चे हिन्दी और इंग्लिश के चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये शिक्षा हम दे रहे हैं। दस पढ़ने के बाद वह बच्चा क्या करेगा? वह चाहे कहीं भी चला जाएगा उसको कोई नौकरी नहीं देगा। उसको प्राईवेट में भी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐग्रिकल्चर पहले ही खत्म हो रहा है। तब वह क्या करेगा? वह नशा ही करेगा। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश में जो नशा बढ़ रहा है यह जगजीवन पाल जी आपकी सरकार द्वारा जो वातावरण स्कूलों में क्रिएट किया जा रहा है यह उसकी वज़ह से बढ़ रहा है। आज सर, वक्त की डिमांड है। आप शिक्षा में सुधार लाईये। इसको आप मज़ाक मत समझिए। आप हजारों स्कूल खोल रहे हैं लेकिन इन स्कूलों को खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है।

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हर साल कम हो रही है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हर साल करोड़ों-अरबों रूपया आप स्कूलों/शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन आपको मिल क्या रहा है। आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? आपके स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे सिर्फ अपना नाम लिख रहे हैं। वे इलिट्रेट है। शिक्षा के नाम पर आप उनको धोखा दे रहे हैं। आप मुफ्त शिक्षा के नाम पर हमारे नौज़वान युवकों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इसके बारे में सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है। सरकार इसके बारे में सोचती ही नहीं है। सिर्फ तालियां बजाकर मेज़ थपथपा देते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरा स्कूल खोल दिया है। स्कूलों में बच्चे एक या दो और इसको आप गवर्नमेंट की उपलब्धि मान रहे हैं। ये कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि

03.03.2016/1810/TCV/DC/2

स्कूलों में शिक्षा के बारे में कैसे सुधार किया जाये। इसके बारे में सोचें। माननीय परिवहन मंत्री जी अभी बैठे नहीं है। मैं परिवहन विभाग के बारे में बात करना चाहूंगा। ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट का दिवालिया निकलने वाला है। ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट करोड़ों रूपये के घाटे पर चला हुआ है। लेकिन बाली जी यहां पर बार-बार घोषणाएं करते हैं कि हमारा बसों का काफिला बढ़ रहा है। ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट करोड़ों रूपये के घाटे पर चला हुआ है और नगरोटा में एक नया रीज़न ऑफिस खोल दिया है। नगरोटा से 12 किलोमीटर पहले एक रीज़न है। देहरा और बैजनाथ में ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमैंट का रीज़न है, ये नगरोटा में रीज़न खोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अभी बाली जी यहां पर बैठे नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक रीज़न खोलने में कितना खर्चा आया है? इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की बसें चला दी है। आपको पता होना चाहिए है, ये सिटी बसें हैं। ये इस पहाड़ी क्षेत्र में चलने वाली बसें नहीं हैं। इनकी सीटें कुछ आगे के लिए और कुछ पीछे को है। जो सवारी उस बस में हमीरपुर से शिमला बैठकर आएगी और उसका मुंह पिछली तरफ होगा, उसकी क्या हालत होगी? ये सिटी बसें ले ली और ये हमीरपुर से शिमला, हमीरपुर से चम्बा और हमीरपुर से मनाली जा रही है। लेकिन उन सवारियों से पूछो जो इसमें सफर कर रही है कि उनका क्या हाल है? ये बसें ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा--- जारी

3.03.2016/1815/RKS/AS/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर...जारी

इसमें बहुत ज्यादा घाटा एच.आर.टी.सी. को उठाना पड़ेगा। जब से यह सरकार आई है हमारे हमीरपुर जिला में कम से कम 25 रूट बंद कर दिए गए हैं। जब हम कहते हैं कि जो रूट बंद किए हैं, उनको शुरू करो। तो कहते हैं कि हमारे पास बस नहीं है, स्टाफ नहीं है। यह पब्लिक की डिमांड भी है। बस चलाने में डिपार्टमेंट नाकाम है। जो 5,000 के करीब पैंशनर्ज हैं, उनको पैंशन देने के लिए एच.आ.टी.सी. के पास पैसा नहीं है। जो एच.आर.टी.सी.डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, उनको 4-4, 5-5 महीनों और एक साल से पेंशन नहीं मिली हुई है। लेकिन नगरोटा में डिविजन खोलना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्या एच.आर.टी.सी. डिपार्टमेंट को बाली जी अपने साथ नगरोटा में ले जाएंगे? क्या बाकी प्रदेश उनके लिए कुछ नहीं है? उन पैंशनर्ज का ख्याल रखिए जिनको 5-5, 6-6 महीनों से पेंशन नहीं मिली है। जितना भी जो अभिभाषण हुआ, चर्चा हुई क्या उस पर कभी बेरोजगारी के ऊपर चर्चा हुई? लाखों लोग, लाखों स्टूडेंट्स यहां पर बेरोजगार हो रहे हैं। 3 साल में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है? क्या आप सबको ह्वाईट कॉलर जॉब दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी ने स्कील डवलेपमेंट के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट खोला है। कृपा करके आप उसमें लोगों को ट्रेनिंग दीजिए। जो ट्रेड, बच्चे अपनाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग दो, इनिशिएटिव दो। छोटे-छोटे उद्योग, छोटी- छोटी फैक्ट्री, छोटी- छोटी यूनिट लगाकर के कम से कम इस ओर ध्यान दीजिए ताकि वे अपनी रोजी -रोटी का प्रबंध कर सकें। न कोई जिक्र है, न सरकार गंभीर है। जहां तक हैल्थ की बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी इस बार सुजानपुर गए थे। सुजानपुर में एक पी.एच.सी है। बड़ी पुरानी पी.एच.सी. है। अनाऊंसमेंट हो जाती है कि पी.एच.सी को सी.एच.सी बना दिया गया। 2-3 बार पहले भी बना दिया गया था। पहले मुंह से ही बोलते थे कि इसे सी.एच.सी. बना दिया गया। इस बार वहां पर पट्टिका लगा दी गई। लेकिन वहां जो पी.एच.सी. की रिक्वायरमेंट है, वह भी पूरी नहीं है। न वहां इतने डॉक्टर हैं, न कोई एक्स-रे देखने वाला है न कोई मशीन है।

3.03.2016/1815/RKS/AS/2

लेकिन वहां पर पट्टिका सी.एच.सी. की लगा दी गई है और सी.एच.सी. बनाकर चले गए। जब आपके पास रिसोर्सिज नहीं हैं, तो ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आपके पास डॉक्टर नहीं हैं, स्टाफ नहीं है तो पट्टिका लगाने से क्या फायदा? संस्थान खोलने से क्या फायदा? क्यों आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं? मैं ज्यादा न बोलता हुआ, अंत में यही बोलना चाहूंगा कि जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है,मोदी जी ने एक नारा दिया हुआ है 'कांग्रेस मुक्त भारत'। आपकी संख्या केंद्र में 40-45 के बीच में है। अब जो पार्लियामेंट का नया इलैक्शन आएगा उसमें आप 40-45 भी नहीं दिखेंगे। जब हिमाचल विधान सभा का अगला इलैक्शन होगा तो यहां भी 'कांग्रेस मुक्त' हिमाचल होगा। इसलिए आप भी अपना प्रबंध कर लीजिए। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः श्री कृष्ण लाल ठाकुर

श्री एस.एल.एस. द्वारा.... जारी

03.03.2016/1820/SLS-As-1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्तापक्ष ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, आपने मुझे उस पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

इस अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष और हमारे दल के अन्य सम्मानीय सदस्यगण ने बड़ी विस्तृत चर्चा की है। इस अभिभाषण में कितनी सच्चाई है वह हर प्वायंट ऑफ व्यु से विस्तारपूर्वक बताया गया है। चाहे पंचायत राज चुनावों के दावों की बात हो चाहे बेरोज़गारी भत्ते की बात हो, सरकार के वह सब क्लेम झूठे हैं। इसलिए इसमें ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्र सरकार ने हमारा सैंट्रल टैक्सिज का शेयर 32 से 42 परसैंट कर दिया है। सैंट्रल ग्रांट भी रैस्टोर कर दी है। उसके बावजूद भी यह स्टेट प्लॉन में रिफ्लैक्ट नहीं हो रहा

है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है।

मेरा यह कहना है कि प्रदेश सरकार की शौर्ट टर्म या लौंग टर्म कोई भी इफैक्टिव प्लॉन नहीं है। विंटर सीजन में लौंग ड्राई स्पैल हुआ। इससे वॉटर सोर्सिज ड्राई होने के कगार पर पहुंच गए हैं। आने वाले समय में ड्रौट को कैसे टैकल करना है, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया है; विभाग में कोई हलचल उसके बारे में नहीं है। सोर्सिज ड्राई होने से दूसरा नुकसान यह होगा कि जो रूरल वॉटर सप्लाई स्कीम्ज हैं, उनमें डिसचार्ज कम हो जाता है जिससे इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। उससे और ज्यादा बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। इन संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार और विभाग को ड्रौट को टैकल करने के लिए एक शौर्ट टर्म प्लॉन बनानी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक आई. पी. एच. डिपार्टमैंट की बात है, पहले भी जौंडिस पर चर्चा हुई थी। हमें यहां सच बात कहनी चाहिए। मात्र भाषण देने से कोई लाभ नहीं होता। इस समय हिमाचल का आई. पी. एच. डिपार्टमैंट ओवर लोडिड है, एट ए टाईम 3 ऐक्टिविटीज को हैंडल कर रहा है। जैसे रूरल वॉटर सप्लाई, अर्बन वॉटर सप्लाई और सीवरेज तथा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल है। जितने भी साथ

03.03.2016/1820/SLS-As-2

के हमारे राज्य हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, उनमें हर जगह 3-3 विभाग इसके लिए हैं। अगर आई. पी. एच. अर्बन क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देगा तो रूरल पापुलेशन प्रभावित होगी; उनके साथ अन्याय होगा। अगर इरिगेशन इग्नोर होती है तो किसान के साथ अन्याय होगा। मैं नहीं कहता कि यह बात रातोंरात हो सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार इस दिशा में सोचना शुरू करे, चाहे इसमें एक साल लग जाए। आई. पी. एच. विभाग की ट्राईफर्केशन करना बहुत आवश्यक है अदरवाईज जैसे जौंडिश प्रदेश के शहरों और गांवों में फैला है; यह एक बार थम भी गया तो दोबारा भी हो सकता है क्योंकि विभाग उस ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। जैसे विभाग इन चीजों में व्यस्त रहेगा तो वह डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लॉन की ओर ध्यान नहीं दे पाएगा। हालांकि वह कृषि विभाग ने

बनाना है लेकिन उसमें लाइजनिंग आई. पी. एच. विभाग की होगी। उसके बाद ही प्रधान मंत्री जी द्वारा चलाई गई प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की फंडिंग होनी शुरू होगी। वह अभी तक नहीं बन पाई है। इसलिए इन सारी बातों को लेकर मेरा कहना है कि आई. पी. एच. की ट्राईफर्केशन बहुत ज़रूरी है। यह मेरा सुझाव है। इसी ढंग से लाभ होगा अन्यथा अगर हम भाषण देकर चले जाएं तो कुछ होने वाला नहीं है। सैशन में हम भाषण करके चले जाते हैं। अगर सरकार में थोड़ी भी सैंस्टिविटी है तो इस ओर ध्यान दें, इस पर अक्सरसाईज करना शुरू करे। इस बार प्रदेश में हैंड पंप की संख्या भी बहुत कम कर दी है। इससे पहले जो धूमल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, उसमें हैंड पंप बहुत ज्यादा लगते थे जो अब बहुत कम कर दिए हैं। हैंड पंप एक आलटरनेटिव है, एक एस. ओ. एस. है। लोगों की पानी की स्कीम जहां फेल हो जाती है वहां यह ज़रूरी है, इसलिए इनकी संख्या बढ़ाई जानी बहुत ज़रूरी है। रूरल में हमारी ज्यादातर स्कीमों के ट्रीटमैंट बैड्ज और ट्रीटमैंट यूनिट्स खराब पड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा विभाग और सरकार से आग्रह है कि ट्रीटमैंट यूनिट्स को दोबारा बनाकर फंक्शनल बनाया जाए ताकि कल को जो बीमारियां फैलने की संभावना है, वह रुके। उसमें फिर ब्लेम गेम होती है। एक दूसरे को दोष देते हैं। विभाग भी एक-दूसरे को दोष देते हैं

03.03.2016/1820/SLS-As-3

और पक्ष-विपक्ष भी एक-दूसरे को देते हैं। वह बात न हो।

जारी ...श्री गर्ग जी

30/30/2016/1825/RG/DC/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर----क्रमागत

क्योंकि अब quantity के साथ quality का समय आ गया है। इसलिए अब हमें क्वालिटीटेटिव भी होना पड़ेगा। पहले तो ऐसा होता था कि पानी दे दो और क्वालिटी

की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, परन्तु अब क्वालिटी वाटर चाहिए। ये ही चीजें सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक निर्माण विभाग में अपने प्रदेश की सड़कों के बारे में बात करुंगा। अगर प्रदेश में हम सड़कों की हालत खराब कहें, उसको बुरा कहें, तो यह बिल्कुल सही बात है और यदि नालागढ़ की सड़कों की बात करें, तो वे तो वर्स्ट हैं। यह बिल्कुल सच्चाई है। आप में से यदि कोई मंत्रीगण नालागढ़ जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि सड़कों का वहां क्या हाल है? चाहे वे लिंक रोड्ज हों, चाहे वे स्टेट हाइवे हों, एम.डी.आर. हों और सबसे बड़ी दुर्दशा, जिसको मुझे बार-बार कहना पड़ता ह और बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां एक एन.एच.-21 है, अब उसका नया नाम 105 है। वह सड़क पिन्जौर से नालागढ़ तक बन गई है, लेकिन नालागढ़ से स्वारघाट तक उसका जो पोरशन बचा हुआ है उसके लिए सारी फण्डिग हमने केन्द्र सरकार से करवाई है। बल्कि as per DPR लैण्ड ऐक्वीजीशन प्रदेश सरकार ने बीयर करना था, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कम था, पार्टली पेमेन्ट हो गई, पार्टली बच गई। तो मैंने मुख्य अभियनता से as a special case डी.पी.आर. बनवा कर तीन बार गडकरी जी से मिला, तो पूरी फण्डिग 15 करोड़ रुपये लैण्ड ऐक्वीजीशन के लिए भी आ गया है और कंस्ट्रक्शन के लिए भी पूरा पैसा 50 करोड़ रुपये आ चुका है। परन्तु बड़े दुःख की बात है कि यह सब कुछ होने के बावजूद भी न तो प्रभावित किसानों को जमीनों का मुआवजा दिया गया है और न ही कंस्ट्रक्शन वर्क ठीक हुआ है। वह इतना ज्यादा पूअर है, स्पीड बहुत कम है, न तो स्पीड सन्तोषजनक है और न क्वालिटी सन्तोषजनक है। जो सड़क बनाते हैं वह साथ-साथ टूटती भी रहती है, मुझे पता नहीं लगता कि एन.एच. डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और प्रदेश सरकार उससे क्या करवा रही है। उसके लिए हमने धरने, प्रदर्शन किए, चक्का जाम किया। यहां तक की इसी माननीय सदन में मैंने एक बार यहां तक कह दिया था कि अगर सड़क नहीं बनेगी, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। चलो, उसके लिए मैं लोगों के बीच में गया, काफी लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि आपने अपना पूरा काम कर दिया है, आत्मदाह तो उनको करना चाहिए जो अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए वह बयान मैंने सब लोगों के बीच में विदड्रॉ कर

30/30/2016/1825/RG/DC/2

लिया। परन्तु फिर भी आज पोजीशन वही है और सड़क की हालत वैसी ही है। जो ठेकेदार काम नहीं कर रहा था उसके लिए विभाग ने उसको work rescind करने के लिए नोटिस दिया है। तो ठेकेदार हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने उसको नोटिस पर ही work rescind करने के अगेन्स्ट स्टे दे दिया है। तो मैंने बार-बार कहा कि इस स्टे के लिए अर्ली वैकेशन के लिए एप्लीकेशन लगाएं और यह स्टे वैकेट होना चाहिए। लेकिन अभी तक स्टे वैकेट नहीं हुआ। धर्माणी जी यहां बैठे हैं, मुझे लगता है कि यह उस रोड से अब नहीं जाते होंगे। आपको जाते हुए कितने साल हो गए? अब तो उस सड़क से 10-12 साल से नहीं जाते होंगे।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री राजेश धर्माणी) : नहीं, अब नहीं जाता हूं।

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः नहीं जाते और अब जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। परन्तु हमने तो लोगों के बीच में रहना है और लोगों को बहुत परेशानी है। लेकिन हाल वही है, यह पार्टी की बात नहीं है, यह तो ग्रॉउन्ड रियलिटी है। अगर वह रोड ठीक नहीं होती, तो मेरा यह कहना है कि लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। अब लोकतंत्र में हम जो कर सकते थे, हमने किया, परन्तु हाल बहुत बुरा है और हम इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं इस बारे में हम मिल-बैठकर सोचेंगे। इससे भी बड़ा स्टैप और क्या हो सकता है? लेकिन वह आत्मदाह नहीं होगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। उससे तो आप लोग उल्टा खुश होंगे। ऐसा नहीं करेंगे, इसके अलावा और क्या स्टैप्स हैं, देखेंगे। हम ऐसा करके आप लोगों को ओबलाइज नहीं करेंगे, हम तो इससे भी कोई बड़ा काम करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके आगे एक और बात है। हमारा जो ऐनुअल री-सरफेसिंग कोट या जो री-कारपेटिंग होती है, मैंने बार-बार यह मुद्दा उठाया है। मुझे बताया गया कि उसकी लाईफ पांच साल होती है दुबारा जो टारिंग करते हैं। मुझे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था। परन्तु बड़े दुःख की बात है और लोगों के बीच में हमें बहुत शर्म आती है जैसे ही टारिंग करते हैं वह साथ-साथ टूट जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण मैंने बार-बार बताया था। उसकी थिकनेस 20 एम.एम. लेते हैं, 20 m.m is too much on lower side. कहीं यह 10 एम.एम. भी जाती है। तो जैसे ही गाड़ी आती है वह टूट जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि यह 32 या 40 एम.एम. होनी चाहिए अर्थात सवा या डेढ़ इंच। उससे मैं मानता हूं कि नंबर ऑफ किलोमीटर कम हो जाएंगे, परन्तु जो हमारा

काम होगा वह क्वालिटी वर्क होगा और

30/30/2016/1825/RG/DC/3

लोगों में मैसेज जाएगा कि एक बार सड़क बन जाए, तो 4-5 साल चले। दो साल ही चल जाए। लेकिन यह तो दो महीने भी नहीं चलती है। हमारे यहां तो ऐसी पोजीशन है, शायद आप लोगों के यहां भी ऐसी ही पोजीशन होगी। तो यह लोक निर्माण विभाग से मुद्दा उठाने वाला है। इसकी स्पेसीफिकेशन चेंज करके इसको 32 एम.एम. करने की बहुत जरूरत है। यह मुद्दा उठाने वाला है। सभी विधायकों को इसका फायदा होगा।
उपाध्यक्ष महोदय, एक और विषय पीछे चर्चा में आया था कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों के अलावा जितनी ग्रामीण सड़कें हैं, जो पंचायतों की सड़कें हैं। हर बार बरसात होती है, वे खराब हो जाती हैं। उनमें क्या होता है, तो हमें यह टैंशन होती है कि इनको कैसे ठीक करें? कोई इधर से, कोई उधर से आता है, कई बार लोक निर्माण विभाग को कहते हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

03/03/2016/1830/MS/AG/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर जारी ---
लोक निर्माण विभाग वाले मानते है या नहीं मानते हैं हम उनकी मर्सी पर होते हैं और रोड्ज को खोलने के लिए तीन-चार महीने का समय लग जाता है। इससे गलत मैसेज जाता है क्योंकि जैसे गांव में कोई बीमार हो गया या गांवों वालों ने फसलें बेचने के लिए ले जानी होती है। हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय विधायकों ने कहा था कि इसके लिए कोई मैंटीनेंस फण्ड होना चाहिए। उस फण्ड को ब्लॉक की डिस्पोजल पर दे दें लेकिन वह पंचायत की पॉपुलेशन देखकर दिया जाए क्योंकि कई ब्लॉक छोटे होते हैं। जैसे हमारा नालागढ़ ब्लॉक है उसमें तीन चुनाव क्षेत्रों का पार्ट है। उसमें नालागढ़ पूरी है तथा दून और अर्की का भी उसमें पार्ट है। उसमें 40 बी0डी0सी0 मैम्बर्ज हैं और 69 पंचायतें हैं। पूरे प्रदेश में शायद दो-तीन ब्लॉक ही ऐसे होंगे जहां जिसमें पंचायतें होंगी। इसलिए पंचायतें और पॉपुलेशन देखकर मैंटीनेंस फण्ड दिया जाए क्योंकि आजकल

बजटिंग हो रही है और एक-दो दिन में फाइनल हो जाएगी। 8 मार्च को बजट भी पेश होना है। यहां पर सत्ता पक्ष वाले भी बैठे हैं। अगर आप ऐसा मैसेज दें कि इसकी ब्लॉकवाइज फण्डिंग हो जाए ताकि हमें किसी से आग्रह न करना पड़े। जो रूरल रोड्ज हैं वे अब बहुत ज्यादा संख्या में हो गए हैं। कभी विधायक फण्ड से, कभी एम0पी0 फण्ड से और कभी डी0सी0 फण्ड से इनको बनाते जा रहे हैं। लेकिन वे रोड्ज बनने के बाद बंद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि रोड्ज न बनना ठीक है लेकिन बनने के बाद यदि रोड बंद हो जाए तो बुरा लगता है।

हमारे नालागढ़ में जो 5-6 साल पुरानी स्कीमें हैं उनमें कइयों में एफ0सी0ए0 की क्लीयरैंस न होने की वजह से वे पैंडिंग पड़ी हुई हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि उसमें जल्दी ही एफ0सी0ए0 क्लीयरेंस हो जाए। इसके अलावा इंटर स्टेट कनैक्टिविटी में जो सी0आर0एफ0 होता है वह भी नालागढ़ चुनाव क्षेत्र के लिए कम दिया है जबकि मेरा चुनाव क्षेत्र पंजाब से लगता हुआ है। उसके लिए लिए भी फण्ड्ज दिए जाएं। इसी तरह से जो हमारी नाबार्ड से सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग की स्कीमों की एप्रूवल हुई है उसमें जो फण्डिंग हुई है वह as per schedule नहीं है। जैसे नाबार्ड की स्कीमों के लिए जो फण्डिंग होती है उसमें

03/03/2016/1830/MS/AG/2

तीन साल में स्कीम पूरी होनी चाहिए लेकिन जब फण्ड्ज ही जब as per schedule नहीं दिए जा रहे हैं तो उससे स्कीम और लेट हो जाएगी। इसलिए जो फण्डिंग है वह as per schedule हो।

एक हमारी बी0बी0एन0डी0ए0 बनी हुई है। नालागढ़ के लोगों को उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा है। अब अगर किसी ने कन्स्ट्रक्शन वर्क करना है तो कम-से-कम 10 चक्कर नक्शा एप्रूव करवाने के लिए लगाने पड़ते हैं। चलो, बी0बी0एन0डी0ए0 का मास्टर प्लान भी अभी हाल ही में केबिनेट ने एप्रूव कर दिया है। उसमें मेरा यह कहना है कि जो डवलपमैंटल ग्रांट है वह इस बार 20 करोड़ रुपये है लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले साल वह कम-से-कम 50 करोड़ रुपये हो ताकि लोगों को लाभ मिले। क्योंकि उद्योगों की वजह से वहां वर्कर्ज का लोड है। चाहे रोड्ज है, पानी

की स्कीमें हैं या सिंचाई की स्कीमें हैं सबके ऊपर उसके एक्स्ट्रा लोड को मीट करने के लिए फण्ड 20 करोड़ रुपये की जगह 50 करोड़ रुपये होना चाहिए। इसके अलावा बी0बी0एन0डी0ए0 में नालागढ़ और दून दो चुनाव क्षेत्र पड़ते हैं और नालागढ़ का लगभग 65 परसेंट एरिया उसमें पड़ता है। उसके बावजूद पिछले दो-तीन सालों से और चुनाव क्षेत्रों की अपेक्षा वहां के लिए कम फण्डिंग हो रही है। मेरा बी0बी0एन0डी0ए0 के बारे में यह भी कहना है क्योंकि यह उद्योग मंत्री जी के अण्डर पड़ती है कि नालागढ़ की जितनी भी पंचायतें हैं और पॉपुलेशन है उसके अनुपात में यहां फण्डिंग की जाए ताकि नालागढ़ के लोगों के साथ अन्याय न हो। एक बात और कहना चाहता हूं कि बी0बी0एन0डी0ए0 में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर भी पैनी नजर रखने की जरूरत है क्योंकि डवलपमैंट ग्राउंड लैवल तक बहुत कम पहुंचती है इसलिए भ्रष्टाचार पर चैक लगाया जाए। इसके अलावा, केन्द्र सरकार का नालागढ़-दून के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। अभी हाल ही में माइक्रो स्मॉल एण्ड मिडियम एंटरप्राइजिज मिनिस्ट्री के मंत्री श्री कलराज मिश्र जी बद्दी में आए थे तो उन्होंने 150 करोड़ रुपये का टैक्नॉलोजी सेंटर, पहले उसको टूल रूम कहते थे लेकिन अब उसका लैटेस्ट नाम टैक्नॉलोजी सेंटर रखा है। वहां उसका

03/03/2016/1830/MS/AG/3

फाउंडेशन स्टोन रखा है। इससे जहां उद्योगपतियों को फायदा होगा उसके साथ-साथ जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, उनको भी फायदा होगा। इसके अलावा जहां तक उद्योगों की बात है जो इन्वेस्टर मीट हुई, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उसका फायदा क्या होना था स्टेट गवर्नमैंट का इतना इनडिफ्रेंट एटिच्यूड towards industries है कि नालागढ़ से उद्योगपति उद्योगों को शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राज्य सरकार का एटिच्यूड उद्योगपतियों के साथ भी इनडिफ्रेंट है और जो लोकल हमारे वर्कर्ज हैं उनके साथ भी वैसा ही एटिच्यूड है। उससे बहुत नुकसान हो रहा है। -(व्यवधान)- यह भी हमारे अध्यक्ष जी ने ठीक बताया कि एक्स्ट्रा कन्स्टीच्यूशनल पैरेलल फोर्सिज जो हमारे हरेक चुनाव क्षेत्र में भेज दिए हैं जहां से कांग्रेस के विधायक नहीं जीते हैं, तो वे लोग पैरेलल गवर्नमैंट चलाने की कोशिश करते हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

03.03.2016/1835/जेएस/एजी/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः -------जारी--------

लोगों की डिमांड्ज़ भी हमारे पास ही आनी है। वो कोशिश करते है अपने आपको बड़ा सुपर इम्पोज़ करके कि हम सब कर रहे हैं। करते तो हैं, लेकिन ज्यादा गलत करते हैं। डेढ़ साल और बचा हुआ है वे करेंगें उन्हें लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है डेढ़ साल के बाद तो वे लोग वहां आस-पास भी नहीं दिखेंगे। इसी तरह से माइनिंग में भी धांधली हो रही है। लीगल माइनिंग अगर हो तो हमारा जो बिल्डिंग मटिरियल है रेता और रोड़ी है उसके रेट जैन्यून रहेंगे परन्तु होता क्या है कि लीगल माइनिंग तो है नहीं ,लोग चोरी से माइनिंग करते जा रहे हैं तो उसके रेट और ज्यादा बढ़ गए हैं इसलिए चाहे प्राईवेट सेक्टर या गवर्नमैंट सेक्टर में काम करना है उसके रेट भी बढ़ गए हैं। तो लीगल माईनिंग को जल्दी अलाऊ करें यह भी मेरा इंडस्ट्री मिनिस्टर से आग्रह है और समय पर यह काम होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात है कि सरकार ने तीन इंडस्ट्री एरिया घोषित किए थे। दभोटा नालागढ़ में पड़ता है, कंदरौड़ी कांगड़ा में और पंडोगा ऊना में है, दो तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ सेंक्शन कर दिए हैं और उनमें काम शुरू हो गया परन्तु दभोटा जो कि नालागढ़ में पड़ता है, उसका अभी तक पता नहीं क्या स्टेटस है? अभी तक उसको फाईनल नहीं किया है। मेरा आग्रह है कि उसको जल्दी किया जाए नहीं तो डेढ़ साल बाद लोग आपको खुद जवाब देंगें। जहां तक ऐजुकेशन की बात है, माना कि स्कूल खोले जा रहे हैं परन्तु क्वालिटी ऐजुकेशन भी होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में भी स्कूल खोले गए हैं। जितना हमारा शेयर बनता है उससे कम स्कूल खुले हैं, और स्कूल वहां पर खुले और जो क्वालिफाईड स्टाफ है, not only through SMC but through Subordinate Services Selection Board भी आएं ताकि जो पहले से स्कूल खुले हैं उनके अंदर वेकैंसी फिलअप हो तथा जो नए स्कूल खुले हैं उनमें भी ढंग से पढ़ाई हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले समय में बात मैनेजेबल नहीं रहेगी। जितने स्कूल खुले हैं उनमें प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए।

03.03.2016/1835/जेएस/एजी/2

उपाध्यक्ष महोदय, नालागढ़ में पिछले एक साल में जो फ्रीक्वेंट पावर कट्स लग रहे हैं जिससे आम जनता तथा साथ में उद्योगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में भी विधान सभा में एक प्रश्न लगा था। मंत्री जी अभी बैठे नहीं है। यह भी सरकार की नाकामी है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ आनी चाहिए लेकिन जब इतने पावर कट लगेंगें तो वह कहां से आएगी? और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहां पर उद्योग स्थापित करने के बारे में सोचेगा इसलिए बिजली के सिस्टम को ऑग्युमैंट करने की जरूरत है ताकि फ्रीक्वेंट पावर कट से छुटकारा मिल सके

इसी तरह से हैल्थ सर्विसिज़ का भी नालागढ़ में बहुत बुरा हाल है। हमारी जो ग्रामीण पी.एच.सीज़् हैं उनमें बहुत रिक्तियां है तथा नालागढ़ हॉस्पिटल में सेंक्शंड स्ट्रैंथ बैड के मुताबिक नहीं है जबकि उसको 100 बिस्तरों का अस्पताल घोषित किया गया है। उसमें स्पैशेलिस्ट की स्ट्रैंथ पूरी नहीं है। वहां पर उद्योगों की वजह से हॉस्पिटल पर काफी प्रैशर रहता है। ओ.पी.डी. के अनुपात में वहां पर डॉक्टरों की स्ट्रैंथ नहीं है तो इसको भी देखा जाए। फ्लड कंट्रोल के बारे में कहना चाहता हूं कि नालागढ़ को नालों के गढ़ के नाम से जाना जाता है। वहां पर बरसात में नाले चलते हैं तथा बाद में सूख जाते हैं क्योंकि नालागढ़ फुटहिल में है और जो पहाड़ से नाले बहते हैं उससे वहां की फर्टाईल लैंड का इरोज़न होता है और साथ लगती प्रापर्टी को भी नुकसान होता है। इसके लिए भी मैंने पहले ही साल एम.एल.ए. प्रायोरिटी में Channelization of various nullahs in Nalagarh Assembly Constituency and construction of small dams wherever feasible के बारे में स्कीम डाली थी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले तीन सालों में उनकी फीज़िबिलिटी स्टडी नहीं हो पाई। यह कब होगी? इसके लिए फंडिंग सैंटर गवर्नमैंट ने देनी है तथा सैंटर गवर्नमैंट ने अब 90:10 कर दिया है। स्टेट गवर्नमैंट ने सिर्फ 10 परसेंट देना है । एक बार डी.पी.आर. बना करके भेज दें। वह दो हजार करोड़ की है या एक हजार करोड़ की बने परन्तु सरकार ने पिछले तीन सालों सरकार और आई.पी.एच. डिपार्टमैंट डी.पी.आर. ही नहीं बना पाया तो इतना indifferent attitude towards Nalagarh Constituency इन सब चीजों से पता लगता है।

श्री एसएस द्वारा जारी--

03.03.2016/1840/SS-AG/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर क्रमागतः

बाकी यही हाल हमारा ट्रांसपोर्ट का है। जो मैक्सिमम कई रूटस थे वे दो-तीन साल पहले कैप्ट इन अबेयंस कर दिये थे। कुछ समय के लिए उनको टाल दिया गया था। परन्तु आज तक वे रिस्टोर नहीं हुए हैं। नयी सड़कें बन गई हैं जोकि पास हो गई हैं, उन पर नये रूटस चलाने की आवश्यकता है। मेरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, श्री बाली जी से आग्रह है, वैसे उन्होंने कहा भी है कि नई बसें चलायेंगे। लेकिन अभी तक चली नहीं हैं। वे चलानी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन चीज़ें के लिए लोगों की बड़ी डिमांड है। गवर्नमैंट सैंसटिव होनी चाहिए। सरकार में सैंसटिविटी कम है। मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं कर रहा हूं। सैंसटिविटी वाकई कम है। आप किसी अफसर को कहते हैं लेकिन अफसर का डर कम हो गया है। पहले होता था कि अगर असैम्बली क्वैश्चन कर दिया, विधान सभा में चर्चा होगी तो अफसर में एक बड़ा टैरर होता था। अब बहुत नॉर्मल हो गया है। सभी लोगों में डर कम रह गया है। उनको पता है कि इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमैंट की जो असंवेदनशीलता है, यह सारा उसका असर है। मैं यही कह सकता हूं कि गवर्नमैंट संवेदनशील हो। अगर सरकार में संवेदनशीलता नहीं रहेगा तो साल या डेढ़ साल अब सरकार का और बचा है, वह चेंज तो अवश्य होना है लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रेसफुल चेंज हो। जैसे हम हैं आप भी इतने रहें। यह न हो कि आप सिंगल डिजिट में रह जाएं। वह बहुत दुख की बात है। --(व्यवधान)--दिल तोड़ने की बात नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि आप लोग सिंगल डिजिट न रह जाएं। हमें साऊंड ऑपोजिशन चाहिए। आप सभी सम्माननीय मंत्रिगण और विधायकगण बैठे हैं। आप माननीय मुख्य मंत्री जी को कंवे कर दीजिये कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमने आज तक ऐसी अनारकी नहीं देखी कि अफसर किसी की बात को मानते नहीं हैं। एक तो सरकार में कोई तालमेल नहीं है। ऐसा पहली बार देखा है। काफी बातें और बोलने के लिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चार-पांच मिनट और बोल लूं।

Deputy Speaker: Please wind up now. You can further speak for two minutes.

03.03.2016/1840/SS-AG/2

श्री कृष्ण लाल ठाकुरः मेरा यही कहना है कि जैसे ड्रग एडिक्शन के बारे में मेरे साथ बैठे साथी विजय अग्निहोत्री जी ने बताया कि हमें अपने युवाओं को खेत-खलियान की तरफ मोड़ना चाहिए। वह तभी सम्भव होगा अगर हमारी खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होने के लिए इरिगेशन चाहिए। वह मैंने पहले ही बता दिया कि इरिगेशन तभी सम्भव है अगर हम उसके लिए अलग डिपार्टमैंट बनायेंगे। तभी हम इफैक्टिव इरिगेशन दे पायेंगे। इससे एक तो ड्रग एडिक्शन की समस्या में फायदा हो सकता है। बाकी जो दूसरे माफियाज़ हैं उसके बारे में सभी लोगों ने बोला है मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। जितने भी सैक्टर्ज़ हैं हर सैक्टर्ज़ में गवर्नमैंट फेल हुई है। हमें इस बात का दुख भी है। अगर सरकार सभी क्षेत्रों में बराबर-बराबर चले तो अच्छी बात है। हमारे मैम्बर्ज़ की तरफ से जो सुजैशन्ज़ आती हैं वे नॉर्मली कंस्ट्रक्टिव होती हैं। बीच में मजाक भी होता है। आपकी तरफ से तो कोई मैम्बर जे0एन0यू0, कोई जे0एंड0के0 और कोई हरियाणा की तरफ भटक गया। भटकाव मजाक के लिए हो सकता है लेकिन उससे आपको नुकसान होगा। अगर मजाक के लिए करें तब तो ठीक है लेकिन अगर सीरियसली सोचते हैं तो आपकी बहुत दुर्दशा होने वाली है। कंट्री फर्स्ट होना चाहिए। जो हमारी केन्द्र में सरकार है उसके लिए कंट्री फर्स्ट है। इस समय केन्द्र में जो भारत की जनता ने सरकार बनाई है वह बहुत स्ट्राँग बनाई है। उसके लिए आप हर चीज़ पर अपोज़ न करके थोड़ा बड़ा दिल रखकर सच्ची बात बोल दें। सच्ची बात ही बोलनी चाहिए और केन्द्र सरकार जो हिमाचल को इतना दे रही है, 32 से 42 परसैंट कर दिया है, उसके लिए आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। इसमें ज्यादा न पड़कर हमें अपनी कांस्टीचुऐंसी और स्टेट के बारे में सोचना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

3.03.2016/1845/केस/एएस/1

श्री सुरेश कुमारःउपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया और माननीय सदस्य श्री जगजीवन पाल जी ने उस पर धन्यवाद प्रस्ताव और श्री अजय महाजन जी ने जिसका अनुसमर्थन किया, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझसे पूर्व पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने विस्तार से इस पर चर्चा की और सत्ता पक्ष की ओर से जो भी वक्ता रहे, सभी का प्रयास रहा कि पिछले तीन वर्षों की जो उपलब्धियां रही और जो विकास हुआ उसको बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए लेकिन मेरा मानना है कि पिछले तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में पूरी तरह विफल रहा। अगर आप देखें तो तीन वर्षों के दौरान सरकार किसी भी प्रकार का विकास करवाने में असफल रही। कुल मिला कर कुछ लेखा जोखा तो इसका इस चुनाव में मिल गया और बाकी 2017 में पता चल जाएगा लेकिन जिस प्रकार से यहां पर सभी सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पंचायती राज चुनाव के बारे में कहा कि पंचायती राज चुनावों में 70 और 76 प्रतिशत कांग्रेस समर्थित सदस्य चुन कर आए, मेरा मानना है कि जब चुनाव पार्टी चिन्ह् पर हुए ही नहीं तो ऐसा कैसे सम्भव है? मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि आपकी सरकार के जो नुमाईंदे या नेता हैं उन्होंने अपनी तरफ से धन तथा बल से भरसक प्रयत्न किया लेकिन उसके बावजूद भी ये चुनावों में जो चाह रहे थे उसको पाने में नाकाम रहे। यहां तक कि कई सदस्य जो चुन कर आए, जैसे कि राजगढ़ बी0डी0सी0 की बात मैं करना चाहूंगा। वहां पर एक सदस्य जीत कर आया जिसके पिता जी फोरैस्ट डिपार्टमैंट में क्लास-IV है। उसके ऊपर इतना प्रैशर बनाया गया कि खुद डिप्टी रेंजर उसके घर तक पहुंचे। डी0एफ0ओ0 ने फोन किया और जिस दिन चुनाव था उस दिन तो जो हमारा केंडिडेट, बी0डी0सी0 का मैम्बर वहां से जीता था उसके फादर को डी0एफ0ओ0 ने अपने ऑफिस में ही बुला लिया। इतना ज्यादा प्रैशर बनाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, इसके उपरान्त भी उसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और हमारी पंचायत समिति वहां पर बनी। इस प्रकार के एक नहीं अनेकों उदाहरण है। एक हमारी मैम्बर थी उसके पति को उठा लिया। एक बी0डी0सी0 मैम्बर को उठा लिया और वहां के एक नेता जब तक बी0डी0सी0 का चुनाव

नहीं हुआ उसको अपनी गाड़ी में ले करके घुमाते रहे। इस प्रकार से धन और बल का पूरा प्रयोग किया गया। कर्मचारियों को सख्त आदेश थे कि सारी वोटें हमारे पक्ष में करो। इतना होने के बावजूद भी हमारे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर प्रधान, बी0डी0सी0 मेम्बर्ज भारतीय जनता पार्टी समर्थित जीत कर आए। इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूंगा हमारे वहां

3.03.2016/1845/केस/एएस/2

पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में चुने हुए प्रतिनिधि तो बहुत कम थे लेकिन कर्मचारियों को उसमें विशेष रूप से बुलाया गया था। वहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके समक्ष वहां के एक नेता जिनको कि इस सरकार ने उपाध्यक्ष नोमिनेट किया है, अपनी पार्टी के कार्यक्रम में अपने कार्यकत्ताओं के सामने नेता जी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इनके कहने से काम नहीं किए तो आपकी हम ट्रांसफर कर देंगे। जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 29 सितम्बर, 2013 को माननीय मुख्य मंत्री जी एक कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने वहां मंच से यह घोषणा की थी कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी विधायक से मिलने विशेष रूप से विपक्ष के जो विधायक हैं, उनसे मिलने के लिए रैस्ट हाऊस नहीं जाएगा जबकि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में इस प्रकार से वहां पर अधिकारियों/कर्मचारियों को बुलाया गया और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने उनको दबाया गया कि अगर आप इनके कहने से काम नहीं करेंगे तो आपकी ट्रांसफर कर दी जाएगी। मुख्य मंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि विधायकों से मिलने भी आप नहीं जाएंगे लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उनमें अधिकारियों और कर्मचारियों को डराया जाता है। ये मेरे पास अखबार की कटिंग भी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

3.3.2016/1850/av/as/1

श्री सुरेश कुमार क्रमागत

जिसमें लिखा गया है कि 'कांग्रेस के कार्यक्रम में हाजिरी भर रहे हैं सरकारी अधिकारी'। मेरा यह कहना है कि आज विकास के काम तो ठप्प पड़े हैं परंतु अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें डराया व धमकाया जा रहा है। बाकी यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण पढ़ा उस पर बहुत सारी बातें हुई। यहां पर पैंशन की बात की गई। जो सामाजिक सुरक्षा पैंशन मिलती है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह पैंशन वर्ष 1977 में जब यहां पर शांता कुमार जी मुख्य मंत्री बने थे, उस समय शुरू की गई थी। उस समय इसको 50 रुपये से शुरू किया गया था। उसके उपरांत वर्ष 1998 से 2003 की माननीय धूमल के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको 50 रुपये से 100 रुपये किया। उसके उपरांत धूमल जी जब दोबारा वर्ष 2008 में मुख्य मंत्री बने तो इसको सौ रुपये से 200 रुपये और 200 रुपये से 300 रुपये किया। उसके बाद 300 रुपये से 350 रुपये और 350 से 450 रुपये तक लेकर गये। मगर वर्ष 2012 से पहले जब-जब भी कांग्रेस की सरकार रही इस पैंशन में एक रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। आज यहां पर बात हो रही थी कि सभी मामलों में पैंशन लगा दी गई है और अब कोई मामला पैंडिंग नहीं है। इसी सैशन में मेरा प्रश्न संख्या 2879 लगा था जिसके तहत मैंने सरकार से पूछा था कि 31 जनरवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रदेश में पैंशन के कितने मामले रिसीव हुए। उसके उत्तर में आया कि 1,30,901 मामले रिसीव हुए जिसमें से 95,933 को पैंशन दी गई और 34,968 मामले अभी भी लम्बित पड़े हैं। जब मैंने 80 वर्ष से ऊपर के मामलों में जानकारी जाननी चाही तो उत्तर आया कि कुल 26,465 मामले प्राप्त हुए जिसमें से 20,114 को पैंशन लगाई गई और अभी भी 6,351 मामले शेष रहते हैं। भाई जगजीवन पाल जी कह रहे थे कि 80 वर्ष से ऊपर तो सबको लगा दी। (---व्यवधान---) 31 मार्च तक लग जायेगी, यह तो पता चल ही जायेगा। वह भी देख लेंगे। इसके अतिरिक्त यहां पर हाउसिंग की स्कीम की बात की जा रही थी। हाउस बनाने के लिए जो

3.3.2016/1850/av/as/2

राशि 48,500 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया है मैं उसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। परंतु मेरा यह मानना है कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण 75,000 रुपये में मकान नहीं बन सकता। जो वैलफेयर के तहत एस.सी./एस.टी. और ओ.बी.सी. को मकान दिए जाते हैं उसमें मैं बताना चाहूंगा, अभी मंत्री हाउस में बैठे नहीं है। मैं यह

कहना चाहता हूं कि ये हाउसिज भी पिक एण्ड चूज के आधार पर दिए जा रहे हैं। जिला सिरमौर में वर्ष 2010 के मामले भी अभी लम्बित पड़े हैं और कुछ मामले ऐसे हैं जो कि वर्ष 2015 के हैं। वर्ष 2015 के जो मामले हैं वह भी वहां के नेता के कहने पर दिये जा रहे हैं। कई बार तो टी.डब्ल्यू.ओ. स्कूटर पर ही कागज लेकर पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने पिछले तीन वर्ष के कार्यकाल में इस प्रकार से भाई-भतीजावाद को भी बढ़ावा दिया है।

अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की बात करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं तो उसमें लिंक रोड्ज की तो बात ही छोड़िए मुख्य सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। यहां पर भाई विनय जी बोल रहे थे। मुझे लगता है कि जिला सिरमौर का विकास तो शायद रेणुका विधान सभा क्षेत्र तक सीमित हो गया है। हमारे जिला सिरमौर से तीन विधायक भाजपा समर्थित है, एक विधायक निर्दलीय है तथा मात्र एक ही विधायक कांग्रेस पार्टी का है। जितनी भी मशीनरी; चाहे एस.डी.पी. की बात हो, एन.सी.आर. तथा दूसरे फंड की बात हो वह सारा एक ही जगह केंद्रित हो गया है।

टी सी द्वारा जारी

03.03.2016/1855/TCV/DC/1

श्री सुरेश कुमार ----- जारी

उसको लगता है कि यदि रेणुका का विकास हो गया तो पूरे सिरमौर जिले का विकास हो गया। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत ही दयनीय है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की छैला-औछघाट सड़क की हालत बहुत ही खराब है। पिछले तीन वर्षों से हर सैशन में और प्लानिंग की बैठक में मैंने यह मुद्दा रखा है। लेकिन अभी भी इस सड़क की हालत बहुत ही दयनीय है। सोलन-मिनस सड़क इसकी हालत भी बहुत ही खराब है। यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क हैं। यह सड़क सोलन, पच्छाद, रेणुका, शिलाई और उत्तराखण्ड को जोड़ती है। पिछले साल जून-जुलाई में इसकी टारिंग हुई थी। यह हमारा दुर्भाग्य था की ऐसे मौसम में टारिंग हुई

जब बरसात का मौसम था। इस सड़क की टारिंग होने के तीन महीने बाद यह टारिंग ऊखड़ चुकी है। इसी प्रकार से सराहां -चण्डीगढ़ की बात है। हमारा दुर्भाग्य है, 2007 में इस सड़क का निर्माण हुआ था। 34 किलोमीटर की यह सड़क, इसको पक्का किया जाना था। लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी 34 किलोमीटर सड़क का निर्माण ही नहीं हो सका। पिछले वर्ष इस सड़क का कोई तीन किलोमीटर का हिस्सा पक्का किया गया था। लेकिन वह भी पूरी तरह खराब हो गया। कुल-मिलाकर जो भी मुख्य सड़कें हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। इन सड़कों की हालत कैसे ठीक होगी जब सब-डिवीजन में जे0ई0 ही नहीं होगें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के सराहां सब-डिवीजन में 4 जे0ईज0 की पोस्टें है और चारों की चारों खाली है और एक भी जे0ई नहीं है। यहां पर मात्र एक एस0डी0ओ0 है। इसी प्रकार से राजगढ़ सब-डिवीजन में 4 में से मात्र 2 जे0ई0 हैं। डिलमण में 4 में 2 जे0ई0 हैं। हाबण में 4 में 2 जे0ई0 हैं। जब जे0ई0 ही नहीं होगें तो किस प्रकार से उस क्षेत्र के काम होंगे। इसी प्रकार यदि बात करें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर पीने के पानी की स्कीमें, ग्रेविटी के पानी की स्कीमें हैं और कुछ लिफ्ट की स्कीमें हैं। लेकिन जितनी भी स्कीमें हैं, उनमें से 90 प्रतिशत स्कीमों में फिल्टर नहीं हैं। पिछले दिनों पीलिया का प्रकोप जहां पूरे शिमला, सोलन और सिरमौर में फैला। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिरमौर में भी सबसे अधिक मामले पीलिया के पाये गये। मैंने बार-बार सरकार के समक्ष पानी की स्कीमों में फिल्टर बैड लगाने के लिए मांग उठाई। लेकिन अभी तक उसमें कोइ सुधार नहीं हुआ। मेरे निर्वाचन क्षेत्र

03.03.2016/1855/TCV/DC/2

में आई0एण्डपी0एच0 के दो सब-डिविजन है। जिसमें एक राजगढ़ सब-डिविजन है और उसमें जे0ई0 की 4 पोस्टें हैं। परन्तु 4 की 4 खाली पड़ी हुई है। एक जे0ई0 नौराधार से डैपूटेशन पर आता था। लेकिन उसको पीलिया हो गया है और आजकल वह भी नहीं आ रहा है। कुल-मिलाकर एक एस0डी0ओ0 है। वह भी कभी बीमार रहता है और रिटायरमेंट पर बैठा है। इस प्रकार से इस आई0पी0एच0 सब-डिविजन की हालत बहुत ही खास्ता है। जब स्टॉफ नहीं होंगे तो कैसे विकास के काम होंगे? मैंने पिछले दिनों राजगढ़ में अधिकारियों की बैठक ली थी। उसमें मुझे पता चला कि कुल-मिलाकर जो

राजगढ़ सब-डिविजन है, उसमें जे0ई0 की 4 पोस्टें खाली है। एक पोस्ट वर्क इनस्पैक्टर, एक कम्पलैंड अटैंडेंट की खाली है, पम्पों ऑपरेटर की 27 पोस्टें खाली हैं। हैल्पर 33 और चौकीदार की 38 पोस्टें खाली हैं। बेलदार की 199 और फिटर की 112 पोस्टें खाली है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य आप 5 मिनट में वॉइंड-अप किजिए। मैं बैठक 10 मिनट के लिए एक्सटेंड करता हूं।

(सदन की बैठक 7.10 बजे सायं तक बढ़ाई गई।)

श्री सुरेश कुमारः उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2692 आज का ही मेरा प्रश्न था।

श्री आर0के0एस0 द्वारा--- जारी

3.03.2016/1900/RKS/DC/1
श्री सुरेश कुमार... क्रमागत

प्रश्न संख्याः 2692, इसमें मैंने पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में जिला सिरमौर में कितने हैंडपम्प लगे? अभिभाषण के पैराग्राफ नम्बर 50 में दर्शाया गया है कि प्रदेश में 16,881 हैंडपम्प पिछले 3 वर्षों में लगे। जो मेरा प्रश्न था उसमें बताया गया कि जिला सिरमौर में कुल मिलाकर 435 और मेरे विधानसभा क्षेत्र में 67 हैंडपम्प लगे। राजगढ़ में 27 और सराहं में 40 हैंडपम्प लगे। मैं यह पूछना चाहूंगा कि 16, 881 हैंडपम्प कहां लगे? मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की भारी कमी रहती है। हैंडपम्प का जो आंकड़ा बताया गया है क्या वह गलत है? मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत सारे कॉलेजिज खुले, बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया गया, बहुत से नए स्कूल खोले। अच्छी बात है। इसके लिए मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई स्कूलों को अपग्रेड किया गया। सरकार ने स्कूल तो अपग्रेड कर दिए परन्तु स्टाफ देना भूल गई। आदणीय महेश्वर सिंह जी ने आज एक विधान सभा प्रश्न लगवाया था। इसमें बताया गया है कि 982 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिसमें सिंगल टीचर है। जब मैंन उस प्रश्न को पढ़ा तो उसमें

अनेक ऐसे स्कूल हैं, जिनमें से एक स्कूल छंडासा, चम्बा जिला का भी है। उस स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है। अनेकों ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक-एक बच्चा या दो बच्चे हैं। आप जानते हैं कि एक अध्यापक महीने में 40-45 हजार सैलरी लेता है। अगर 45 हजार में एक बच्चा है तो भारत की बात छोड़ा वह यू.एस. ए. में भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सरकार को स्कूलों के अपग्रेडेशन में ध्यान न देकर क्वालिटी एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र मे कई स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया। परन्तु अभी भी अनेकों ऐसे स्कूल हैं जिनके अपने भवन नहीं है। 22 मिडल स्कूल ऐसे हैं जिनके अपने भवन नहीं है। 11 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो निजी भवनों में चल रहे हैं। इसके अलावा मैं सराहं कॉलेज की बात करना चाहूंगा। सरांह कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला था। सितम्बर, 2012 में भूमि का प्रबन्ध करके इस कॉलेज का शिलान्यास माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था। लेकिन जैसे ही सरकार बदली इस सरकार ने उस कॉलेज को बंद कर दिया। जब हम हाई कोर्ट में गए तो यह बताया

3.03.2016/1900/RKS/DC/2

गया कि वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं। जब इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा उसके बाद ही इस कॉलेज को खोला जाएगा। परन्तु बाद में सरकार ने उस कॉलेज को खोला। पहले कॉलेज 4 कमरों में चल रहा था। आज वह कॉलेज 3 कमरों में चल रहा है। गांव वालों ने उस कॉलेज के लिए 25 बीघा जमीन दी थी। परन्तु वहां धूमल जी की पट्टिका लगने के कारण सरकार ने उस भूमि का चयन चेंज कर दिया। अभी दोबारा माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया। 3 साल बीत गए अभी तक उसका कार्य शुरू नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगले 2 सालों में यह शुभ काम नहीं हो पाएगा। अगली बार जब हमारी सरकार आएगी तब यह कॉलेज बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार राजगढ़ कॉलेज का शिलान्यास उस समय के माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने 2005 में किया था। उस शिलान्यास को आज 11 साल हो गए, अभी तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया था और मुख्य मंत्री जी ने

आश्वासन भी दिया था कि बहुत जल्दी इसका कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। कुल मिलाकर चाहे हम सड़कों की बात करें, पेयजल की बात करें, शिक्षा की बात करें या अन्य विकास कार्यों की बात करें मेरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम पूरी तरह बंद पड़े हैं। जिन लोगों को सरकार ने नॉमिनेट करके ओहदे दिए हैं

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी....

03.03.2016/1905/SLS-AG-1

श्री सुरेश कुमार ...जारी

वह केवल पट्टिकाएं लगाने को ही विकास समझते हैं। यहां तक कि मैंने जो स्कीमें विधायक प्राथमिकता में डालीं थी, उनमें एक सड़क डिंगर-सिक्कल-डिंगर-किंगर-बघाणघाट थी जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की है। डॉ० वाई. एसक्ष् परमार, जिनके नाम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में वोट मांगती है, उनके गांव को यह सड़क जाने वाली है। वर्ष 2013-14 में जब मैं विधायक बना, उसके उपरांत उसकी डी. पी. आर. बनवाई गई जो अप्रूव भी हो गई और पैसा भी सैंक्शन हो गया। जब शिलान्यास की बात आई तो मेरे विधान सभा क्षेत्र से पूर्व विधायक, जो कि अब प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष है, वह शिलान्यास करने के लिए पहुंच गए। मैंने उस सड़क को विधायक प्राथमिकता में डाला था। जहां तक विभाग की बात है, मुझे बुलाने की बात तो दूर, मुझे सूचित तक नहीं किया गया। जब मैंने पूछा कि शिलान्यास कैसे हो रहा है, मैंने ही इस सड़क को विधायक प्राथमिकता में डाला है तो विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यह तो ठेकेदार करवा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि
ठेकेदार पर विभाग के अधिकारियों का कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने एक नई चीज देखी कि पहले तो शिलान्यास होते थे लेकिन अब तो भूमि पूजन भी होने लगा है। इसी प्रकार से मैंने विधायक प्राथमिकता में एक आई. पी. एच. की लिफ्ट वॉटर सप्लाई स्कीम दाड़ो देवरिया डाली थी, उसकी भी डी. पी. आर. बनी; 42.50 लाख रुपया उसके लिए स्वीकृत हुआ। जब शिलान्यास की बात आई तो वही नेता जी शिलान्यास के लिए पहुंच

गए। शिलान्यास का समय एक बजे रखा गया था परंतु जब उनको लगा कि विधायक आ सकता है तो शिलान्यास 10.00 बजे प्रातः करके ही चले गए। कुल मिलाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल शिलान्यास और पट्टिकाएं लगाने को ही विकास माना जा रहा है। मुख्य मंत्री जी ने भी मेरे क्षेत्र में दो बार दौरा किया है परंतु कोई भी बड़ी घोषणा या बड़ा कार्य या इन पिछले 3 सालों में नहीं हुआ है। कुल मिलाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं।

03.03.2016/1905/SLS-AG-2

मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखना चाह रहा हूं। आज ही विधान सभा में मेरा प्रश्न संख्या : 2716 लगा था। इसमें मैंने पूछा था कि क्या यह सत्य है कि जिला सिरमौर में पशु तसकरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं? यदि हां, तो गत दो वर्षों में पशु तसकरी के मामले कब-कब दर्ज़ किए गए और दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई? जब मुझे जवाब मिला तो मुझे पढ़कर हैरानी हुई। इसमें दर्शाया गया कि जिला सिरमौर में पिछले दो वर्षों में पशु तसकरी का कोई भी मामला दर्ज़ नहीं हुआ। मैं सदन में बताना चाहूंगा कि 15 अक्तूबर, 2015 को गायों से भरा एक ट्रक मेरे विधान सभा क्षेत्र में पकड़ा गया। शायद इस सदन के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी भी होगी। इसमें 10 बैल और 5 गाएं भरी थीं। उसको कुछ ग्रामीणों ने रोका। उसमें 5 लोग सवार थे। उनमें से 4 लोगों को पकड़ कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया तथा एक लड़का, जिसका नाम नोमान था, वह जंगल की ओर भाग गया। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु कैसे हुई, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता।

Deputy Speaker : Please wind up now.

श्री सुरेश कुमार : जो लड़के वहां पर थे उनमें से 12 लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा हत्या का मामला दर्ज़ किया गया जिनमें 3 उन लड़कों के पेरैंट्स तथा 9 लड़के थे। पेरैंट्स को तो छोड़ दिया गया लेकिन 9 लड़कों को करीब 3 महीने जेल में रहना पड़ा। 21 फरवरी को वह बच्चे रिहा हुए। नेशनल मीडिया से एन. डी. टी. वी. और ए. बी. पी. न्यूज चैनल भी वहां पहुंचा था। बड़े खेद का विषय है कि विधान सभा में भी इस प्रकार से झूठ बोला गया तथा बताया गया कि एक भी पशु तसकरी का मामला नहीं हुआ जबकि यह इतनी

बड़ी घटना थी।

जारी ...श्री गर्ग जी

03/03/2016/1910/RG/AG/1

श्री सुरेश कुमार-----क्रमागत

जिसमें लगभग दो हफ्ते तक धरना और प्रदर्शन होते रहे। बहुत सारे वी.एच.पी. कार्यकर्ताओं और कई अन्य संस्थाओं ने गौ वंश के समर्थन में वहां कई कार्यक्रम किए और इस पूरे मसले को कई रंग दिए जाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है जब मैंने प्रश्न किया, तो यहां उत्तर दिया गया कि एक भी मामला इस प्रकार का नहीं आया। मैं यहां बताना चाहूंगा कि इस सदन के प्रति भी अधिकारी असंवेदनशील हैं। इससे आप स्वयं ही अन्दाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि पिछले तीन वर्षों में जो सरकार है वह अपना कर्तव्य निभाने में पूरी तरह विफल रही है। विकास पूरी तरह ठप्प है और जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत किया गया, वह झूठ के पुलिन्दे के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 3 मार्च, 2016 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमलाः 171004 **सचिव।**